R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 23
01 से 15 सितंबर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

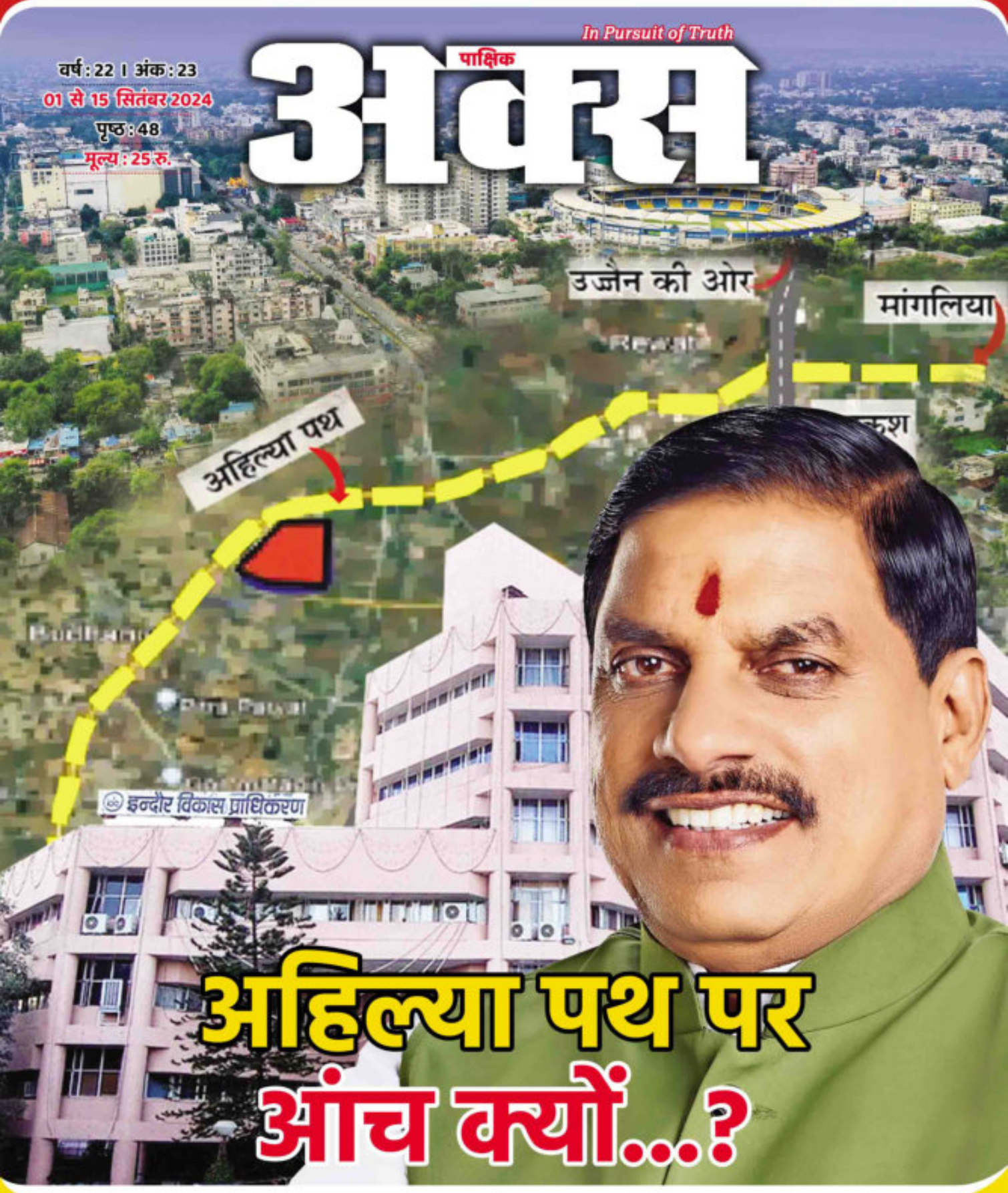

अहिल्या पथ पर आंच क्यों...?

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन की महत्वाकांक्षी परियोजना विवादों में

शहरों के विकास के लिए बने प्राधिकरण भ्रष्टों की गिरफ्त में

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

अब मिलेगी समय पर सहायता...

सड़क, औद्योगिक दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में निःशुल्क वायु परिवहन सेवा

पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा

संचालन प्रारंभ

"हमारी सरकार प्रदेश की जनता को सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हुए स्वस्थ मध्यप्रदेश के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संकल्पित है। अब प्रदेश में गंभीर रोगियों को पीएमश्री एयर एम्बुलेंस सेवा के जरिए उचित समय पर बेहतर इलाज मिल सकेगा"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें : 9111777858

सशुल्क एयर एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, सम्पर्क करें : 0755-4092530

- आयुष्मान कार्ड धारक को प्रदेश व देश में कहीं भी इलाज हेतु शासकीय और आयुष्मान सम्बद्ध अस्पताल में निःशुल्क सुविधा
- आयुष्मान कार्ड धारक न होने पर प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क परिवहन सुविधा जबकि प्रदेश के बाहर निर्धारित शुल्क पर परिवहन सुविधा
- सड़कों या औद्योगिक स्थलों पर होने वाली दुर्घटना, हृदय रोगी या जहर से प्रभावित व्यक्ति को अब मिल सकेगा अच्छे चिकित्सा संस्थानों में समय पर इलाज
- अस्पताल द्वारा मरीज की स्थिति की गंभीरता की जांच के उपरांत मिल सकेगी एयर एम्बुलेंस की सुविधा

एयर एम्बुलेंस सेवा की अनुमति

- दुर्घटना प्रकरण में संभाग के अंदर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा
- दुर्घटना अथवा अन्य आपदा की स्थिति में संभाग के बाहर परिवहन हेतु स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा
- दुर्घटना के अतिरिक्त अन्य गंभीर प्रकरणों में प्रदेश के अंदर संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता की अनुशंसा पर संभागीय आयुक्त द्वारा
- प्रदेश के बाहर गंभीर रोगी या दुर्घटना पीड़ित आयुष्मान कार्डधारी होने पर संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा
- सशुल्क परिवहन हेतु एन.एच.एम. कार्यालय स्तर पर अनुमति मिलेगी

- रोगी/पीड़ित को एयर एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए संजीवनी 108 एम्बुलेंस होगी उपलब्ध
- एयर एम्बुलेंस सेवा में हृदय रोग, श्वास और तंत्रिका संबंधी बीमारियों, नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य समस्याएं, उच्च जोखिम वाले गर्भधारण तथा आपदा की स्थिति को संभालने के लिये प्रशिक्षित चिकित्सक और पैरा मेडिकल स्टाफ रहेगा मौजूद
- हवाई परिवहन के दौरान रोगी/पीड़ित के लिए ₹ 50 लाख के दुर्घटना बीमा का प्रावधान

मध्यप्रदेश शासन

इस अंक में

लालफीताशाही

8 | मप्र रेरा में अटके बिल्डरों के...

मप्र में करीब 7 साल पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का गठन किया गया था, ताकि लोगों को नियत समय पर, सुविधाओं के साथ सही दर पर बिल्डरों द्वारा आवास मिल सके। लेकिन विडंबना यह है कि रेरा...

डायरी

10-11 | चर्चा में 2...

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक रिसोर्ट लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आदिवासी जिला मंडला में स्थित यह रिसोर्ट विवादित चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा और एसआर बघेल का है। बघेल पीआईयू...

समस्या

16 | फर्जी रजिस्ट्री घोटाला

जबलपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके सदस्य फर्जी रजिस्ट्री लगाकर बैंक से लोन लेते थे। बड़ी बात तो यह है कि इस गैंग को बैंक के अधिकारी ही चला रहे थे। गैंग बॉलीवुड मूवी स्पेशल 26 की तर्ज पर काम कर रहा था।

तहकीकात

18-19 | बगावत रोकने नया नियम!

नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

शहरों के विकास के लिए बने प्राधिकरण भर्राशाही, लापरवाही, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) भ्रष्टों की गिरफ्त में इस कदर है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना 'अहिल्या पथ' भी विवादों में फंस गई है। इस परियोजना में अफसरों ने कई तरह की मनमानी की है, जिससे योजना की राह में कांटे ही कांटे नजर आने लगे हैं।

राजनीति

30-31 | दलबदलुओं पर दांव

भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन राज्यसभा के लिए हो रहे चुनाव में पार्टी ने अपने नेताओं को दरकिनार कर दलबदलुओं को टिकट दिया है। इससे पार्टी में रोष है। वहीं लगातार दलबदलुओं को महत्व देने से पार्टी के कैडरबेस कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं।

महाराष्ट्र

35 | सीएम फेस का पेंच

महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल काफी अहम हो चुका है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा जल्द से जल्द घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि शरद पवार और पृथ्वीराज इसकी घोषणा करें।

बिहार

38 | नीतीश कुमार के कारण...

लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सम्राट चौधरी के हटाए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है, वो उनका नीतीश कुमार से बेहतर तालमेल का न...

6 -7 अंदर की बात
40 पड़ोस
42 विदेश
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 23, पृष्ठ-48
1 से 15 सितंबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
देवीराम-इंदौर, हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहगढ़,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर) 09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर) 09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर) 098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन) 094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम) 089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा) 075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

शहर परेशान...जिम्मेदार अंजान...पुलिस हैरान

दे श के दिल मप्र की राजधानी भोपाल के बारे में बड़े गर्व से शायर साकिब मजीद लिखते हैं कि...

हम अपना पहर दिखाएंगे, सपनों की लहर दिखाएंगे,
कभी फुर्सत में आना तुम, झीलों का शहर दिखाएंगे।

लेकिन आज शायद ही शहर की ऐसी स्थिति है कि शायद ही हम किसी को उसे दिखाने के लिए आमंत्रित कर पाएं। क्योंकि एक तरफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट और अन्य विकास कार्यों के कारण शहर कबाड़ बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जिन क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं चल रहे हैं, वहां गुमठियां और हाथ ठेले पर चलने वाली दुकानें अतिक्रमण जमाए हुए है। दरअसल, अजब-गजब वाले मप्र की राजधानी में कमीशन का एक ऐसा खेल खेला जा रहा है, जिससे शहर के लोग परेशान हैं... जिम्मेदार अंजान हैं और पुलिस हैरान है। यह खेल गुमठियों और हाथ ठेला दुकानों का है। शहर में लगभग हर चौक-चौराहे पर गुमठियों और हाथ ठेलों का अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से अवैध कब्जे का यह धंधा कमीशन के चक्कर में तेजी से पसर रहा है। दरअसल, शहर में अवैध कमाई का यह धंधा इस कदर सुनियोजित ढंग से चल रहा है कि कभी कभार दिखावे के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही होती है और अगले दिन ही पहले से अधिक अतिक्रमण कर लिया जाता है। आज स्थिति यह है कि शहर की पहचान झुग्गी-बस्ती, गुमठी और हाथ ठेलों वाले शहर की हो गई है। हम सभी जानते हैं कि राजधानी भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। ये कभी नवाबों की रियासत हुआ करती थी, जिसकी शिनाख्त आज भी शहर के हर कोनों पर देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरह से शहर की सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है, इससे भोपाल शहर की पहचान गुमठियों के शहर के नाम से हो रही है। भोपाल की हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों और पूर्व विधायकों की शह पर जहां-तहां अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इन गुमठी माफिया को भाजपा और कांग्रेस नेताओं का खुला संरक्षण मिल रहा है। जिला प्रशासन और नगर निगम जब इन अवैध गुमठियों को हटाने की कार्रवाई करते हैं तो स्थानीय नेता निगम कर्मियों के साथ मारपीट और बदसलूकी पर उतर आते हैं। कुछ पार्षद और छुटभैये नेताओं ने पूरे भोपाल में अवैध गुमठियों का कारोबार चला रखा है। हॉकर्स कॉर्नर की नई नीति में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, मुख्य मार्गों, स्कूलों और अस्पतालों के साथ सरकारी दफ्तरों के 100 मीटर के दायरे में गुमठियां और ठेले नहीं लगाने का प्रावधान है। मगर पूरे शहर में अवैध गुमठियों का बाजार तेजी से पनप रहा है जिसमें पार्षदों और उनके समर्थकों के अवैध कब्जे हैं। वैसे तो हर वार्ड में व्यवस्थित हॉकर्स कॉर्नर बनाए जा रहें हैं पर राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण समस्या जस की तस बनी हुई है। नगर निगम के कर्मचारी शहर की अवैध गुमठियों और ठेलों से 20 रुपए की रसीद काटकर पैसे वसूलते हैं मगर यह पैसे निगम के खाते में जमा नहीं होते हैं और पूरे शहर में इस तरह से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करके निगम के अफसर अवैध गुमठी के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं नगर निगम की सीमा में गुमठी रखवाने पर स्थानीय नेता हजारों रुपए तक ऐठतें है। इसमें उनके दलाल और गुमठी माफिया सक्रिय रहते हैं। वहीं शहर में इन अवैध गुमटियों पर अपराधी तत्वों का जमावड़ा रहता है। इस संदर्भ में महापौर कहती हैं कि कलेक्टर से पूछो... कलेक्टर कहते हैं कि नगर निगम कमिश्नर से पूछो... और नगर निगम कमिश्नर इसके लिए स्थानीय नेताओं को जिम्मेदार बताते हैं। यानि हर कोई इस अतिक्रमण से पल्ला झाड़ रहा है और जनता परेशान हो रही है।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

जंगल को बचाना होगा...

मप्र में 94 हजार 689 वर्ग किमी में जंगल है। देश के सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले मप्र में जंगल खतरे में हैं। मप्र के जंगलों को बचाने के लिए सरकार को नई नीति लानी चाहिए। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी हैं। वन विभाग को इसके लिए सचेत होना होगा।

● **अनुराग शर्मा,** इंदौर (म.प्र.)

भोजन का महत्व

दुनिया में 233 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्हें नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि उन्हें कुछ समय बिना खाए ही गुजारा करना पड़ा है। हमें खाने के महत्व को समझना होगा और बेवजह खाना फेंकने पर अंकुश लगाना होगा।

● **जयंत पाल,** भोपाल (म.प्र.)

सड़कों का विकास

चार साल बाद होने वाले सिंहस्थ के लिए उज्जैन को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ा जा रहा है, ताकि श्रद्धालु सुगमता से यहां पहुंच सकें। इससे एक तरफ प्रदेश में आवागमन की सुविधा बढ़ाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों के मामले में भी प्रदेश तरक्की कर रहा है।

● **राहुल सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

विकसित राज्य बनेगा मप्र

दिन पर दिन मप्र अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक विकास कर रहा है। मोहन सरकार मप्र को देश का सबसे विकसित राज्य बनाने में जुट गई है। मप्र की तरक्की का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मप्र 9वें नंबर पर काबिज तेलंगाना से बस 1 पायदान पीछे है। मप्र सरकार प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र को विकास का मॉडल बनाएगी। यानी हर विधानसभा क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के साथ ही वह सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, जो वहां के निवासियों में गर्व का भाव भर सके। इसके लिए सरकार विधानसभा क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से योजना बना रही है। इसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे आने वाले समय में मप्र विकास की नई ऊंचाईयों को छूएगा।

● **मयंक वर्मा,** राजगढ़ (म.प्र.)

चुनावी तैयारियों में जुटीं राजनीतिक पार्टियां

इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। देशभर में इस समय इन चारों राज्यों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं। मुख्य विधानसभा चुनाव जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे हैं। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपना दम भरना शुरू कर दिया है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। वहीं अन्य राज्यों में भी स्थिति यही है। भाजपा ने जहां बैठकों का दौर शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस भी चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है।

● **केशव मिश्रा,** नई दिल्ली

रोजगार बड़ी समस्या

मप्र सहित देशभर में युवा बेरोजगार बनकर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। इस समय देश में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। इससे निजात पाने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों से बातचीत कर युवाओं के लिए नई नीतियां बनानी चाहिए। वहीं राज्यों को चाहिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ाएं, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके।

● **पंकज शिवहरे,** रायसेन (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

पाला बदलेंगे जिशान और हीरामन।

महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक जीशान सिद्दीकी और हिरामन खोसकर बीते दिनों अजित पवार की जन सम्मान यात्रा का स्वागत करने और यात्रा सहित सभा में शामिल होने के बाद उनके सरकारी निवास देवगिरी पर मिलने पहुंच गए। इससे प्रदेश का सियासी माहौल गरमा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव से पहले ये दो विधायक पाला बदल सकते हैं। उक्त दोनों विधायकों ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पार्टी में जाने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि उनके और अजित के बीच करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। अजित से जिशान की मुलाकात के कुछ देर बाद कांग्रेस के एक अन्य विधायक हिरामन खोसकर भी देवगिरी पहुंच गए। हालांकि अजित की जिशान और खोसकर के साथ किस मुद्दे पर चर्चा हुई, इसका खुलासा तो नहीं हो सका लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि दोनों कांग्रेसी विधायक जल्द ही पाला बदल सकते हैं। जिशान और खोसकर कांग्रेस में अपनी उपेक्षा से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले अपने पिता व पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी के अजित पवार गुट में जाने के बाद से जिशान के कांग्रेस छोड़ने की चर्चा थी। तब जिशान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी को घोर जातिवादी करार दिया था तथा मजहब के आधार पर पार्टी में अपनी उपेक्षा का आरोप भी लगाया था।

क्या घर वापसी करेंगे अजित पवार

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है लेकिन राजनीतिक दलों में गठजोड़ की रणनीति जोरों पर है। खासकर अजित पवार के अपने चाचा शरद पवार और चचेरी बहन सुप्रिया सुले के प्रति सद्भाव, आत्मीयता और सम्मान दिखाने के कई मायने निकाले रहे हैं। असल में अजित ने शरद पवार को अपने परिवार का मुखिया बताया है और यह भी कहा है कि बारामती लोकसभा सीट पर चचेरी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को लड़ाना उनका एक गलत फैसला था। उनके इस बयान के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि महायुति सरकार के उपमुख्यमंत्री अजित पवार क्या फिर से घर वापसी करना चाहते हैं? आखिर उनका एजेंडा क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो अगर वे फिर से घर वापसी करते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह आश्चर्य की बात होगी। गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा का एक खेमा अजित को पसंद नहीं करता है। कई लोग सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि अजित पवार के साथ तालमेल से भाजपा को लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ। तभी उनको गठबंधन से हटाने की तैयारी भी चलने की खबर है। बहरहाल, राजनीति में जो दिखाई देता है वह हमेशा होता नहीं है। जो होता है वह दिखाई नहीं देता है।

आप में नम्बर दो नेता कौन ?

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह तीनों के जेल में रहने के दौरान केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने पार्टी के नम्बर एक नेता की भूमिका निभाई थी। कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी उनकी इस भूमिका को स्वीकार किया था। लेकिन अब सिसोदिया की जेल से रिहाई के बाद हालात बदल गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सुनीता केजरीवाल फिर परदे के पीछे चली जाएंगी या सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाती रहेंगी? पार्टी में नम्बर दो कौन सुनीता या सिसोदिया? गौरतलब है कि उस अवधि में सुनीता केजरीवाल काफी सक्रिय रहीं। वे विपक्षी गठबंधन इंडिया की रामलीला मैदान में हुई रैली में शामिल हुईं। कल्पना सोरेन के समर्थन में रांची की रैली में भी गईं और लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जिन सीटों पर लड़ रही थी उन पर खूब प्रचार किया। सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने हरियाणा में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान लॉन्च किया। उससे पहले पार्टी ने ऐलान किया कि वह हरियाणा की सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इस घोषणा के बाद वहां पार्टी ने एक रैली की, जिसमें सुनीता ने चुनाव प्रचार का बिगुल फूंका।

एमवीए का हिस्सा बनेगी आप!

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इस मौके पर उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकती है। इसका महत्व तब और बढ़ गया जब आप ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने बीते 5 अगस्त को कहा था कि आप इंडिया गठबंधन का एक मजबूत हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था और उसमें हमारी जीत भी हुई थी, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक अलग विषय है और इसे स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा।

मायावती की राह पर रावण

उप्र के बंटवारे का मुद्दा पिछले कई वर्षों से किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं रहा है। भाजपा छोटे राज्यों की पक्षधर रही है लेकिन उप्र के विभाजन के विरोध में हरित प्रदेश की वकालत करने वाली राष्ट्रीय लोक दल ने भी इसे भुला दिया है। मायावती ने जरूर आज से 12 साल पहले उप्र के बंटवारे का प्रस्ताव विधानसभा में पास करवा लिया था। वहीं अब आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर ने संसद में इस मुद्दे को उठाकर राजनीति गरमा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि लोकसभा में उप्र विभाजन की मांग चंद्रशेखर ने क्यों की? आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? क्या रावण मायावती की राह पर चल रहे हैं? जबकि मायावती और चंद्रशेखर एक-दूसरे के विरोधी माने जाते हैं तो फिर ये महज संयोग है या फिर किसी तरह का प्रयोग? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि दोनों नेताओं का वोटबैंक एक जैसा ही है। बसपा की घटती लोकप्रियता और चंद्रशेखर का बढ़ता प्रभाव आपस में जुड़े हुए हैं।

सॉरी...सॉरी...सॉरी...

शीर्षक पढ़कर आप आश्चर्यचकित जरूर हो रहे होंगे, लेकिन ये शब्द एक आईपीएस अफसर के हैं, जिन्हें मंत्रालय और पीएचक्यू के वरिष्ठों के सामने बोलने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल, जिस साहब की यहां बात हो रही है, वे हाल ही में बुंदेलखंड के एक संपन्न जिले में पुलिस अधीक्षक बनकर गए हैं। जिले की कमान संभालते ही साहब कुछ इस तरह मदहोश हो गए कि जिला बंद का आयोजन किया गया, और यह सफल भी रहा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि साहब को इसकी भनक भी नहीं लगी। उधर, जिला बंद होने से जहां लोग परेशान हुए, वहीं यह बात प्रशासनिक मुख्यालय और पुलिस मुख्यालय दोनों जगह पहुंच गई। दोनों जगह के वरिष्ठ अफसर भी इस बात से अचंभित हो गए कि आखिरकार इस बंद की खबर उन्हें क्यों नहीं दी गई। जब अफसरों ने इस मामले की पड़ताल की तो पता चला कि खुद इसकी खबर नवागत पुलिस अधीक्षक को भी नहीं थी। ऐसे में अफसरों ने उनकी जमकर क्लास ली। सूत्र बताते हैं कि अफसर साहब को कानून व्यवस्था का पाठ पढ़ाने के साथ ही खरी-खोटी सुनाते रहे और साहब सॉरी...सॉरी... की रट लगाए रहे। कहा जा रहा है कि साहब को जबसे नए जिले की कमान मिली है, वे सुध-बुध ही भूल गए हैं। उनके करीबी बताते हैं कि मौके का फायदा उठाने के लिए साहब तानाबाना बुनने में इस कदर मगन हो गए कि उन्हें जिला बंद की सुध ही नहीं रही। बताते हैं कि साहब पूर्व में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भी उटपटांग जवाब दे चुके हैं।

मैडम की कमाई... भाई रे भाई!

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक महिला अधिकारी की रोजाना की कमाई चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि अभी हाल ही में लोकायुक्त के छापे में जिस संस्थान के बाबू की करोड़ों रुपए की काली कमाई का पर्दाफाश हुआ है, मैडम भी उसी में काम करती हैं। गौरतलब है कि विगत दिनों लोकायुक्त पुलिस ने 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए एक बाबू को ट्रैप किया था। जब लोकायुक्त ने बाबू के यहां पड़ताल की तो करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ। इसी संस्थान में मैडम भी काम कर रही हैं और उनकी काली कमाई के चर्चे चारों तरफ हो रहे हैं। मैडम ने तहसीलदार के पद पर नौकरी पाई थी और अब वे प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बन गई हैं। सूत्र बताते हैं कि मैडम कमाई का कोई भी मौका नहीं चूकती हैं। भाड़ में जाए जनता... अपना काम बनता, की तर्ज पर मैडम दोनों हाथों से जमकर लक्ष्मी बटोर रही हैं। अगर सूत्रों की मानें तो मैडम सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में इतनी मेहनत से अपने मिशन पर काम करती हैं कि शाम को जब वे घर जाती हैं तो तकरीबन 2 लाख रुपए लेकर जाती हैं। यह इस बात का संकेत है कि मैडम किस तरह अपने संस्थान की आड़ में लोगों से काली कमाई कर रही हैं।

धर्म-राजनीति के शिकार हो गए कलेक्टर साहब

हाल ही में राजधानी के पड़ोसी जिले के एक कलेक्टर का तबादला हुआ। कहा जा रहा है कि साहब धर्म और राजनीति के शिकार बन गए। इसके पीछे खुद साहब ही दोषी बताए जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उक्त जिले की एक विवादित स्थान को आर्किलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित कर रखा है। इसकी वजह यह है कि दो संप्रदायों के लोग अपने-अपने धर्म को लेकर उक्त स्थान पर दावा करते रहते हैं। ऐसे में किसी तरह का विवाद न हो, इसको लेकर उक्त क्षेत्र को संरक्षित और प्रतिबंधित कर दिया गया है। बताया जाता है कि गत दिनों वहां के स्थानीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों ने उक्त स्थान पर पूजा करने की ठानी और इसके लिए कलेक्टर से अनुमति मांगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुमति मांगने के मामले को साहब ने इस तरह गंभीरता से लिया कि उन्होंने उक्त स्थान पर पूजा करने के लिए मना कर दिया। यही नहीं उन्होंने चिट्ठी-पत्री भी लिख डाली कि उक्त स्थान मस्जिद है, जहां पूजा नहीं हो सकती। साहब की यह करतूत स्थानीय विधायक और लोगों को इस कदर नागवार गुजरी कि उन्होंने इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचा दी। सरकार ने भी विचारधारा से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर साहब को वहां से रवाना कर दिया। सूत्र बताते हैं कि उक्त जिले में पूर्व मुख्यमंत्री साहब को लेकर गए थे। जानकार बताते हैं कि शायद इसी रसूख की वजह से साहब भावनाओं में बह गए और धर्म तथा राजनीति का शिकार बन गए।

स्वयंभू एसपी चित्त

एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा की तर्ज पर एक जिले के कप्तान साहब अपनी ही गलतियों का शिकार हो गए। ये साहब ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले में पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ थे। साहब किसी को कुछ नहीं समझते थे और जिले में अपना मॉडल चलाते थे। बताया जाता है कि पदस्थापना के दौरान साहब की नजदीकी एक पूर्व केंद्रीय मंत्री से इस कदर बढ़ गई कि उनका रसूख सातवें आसमान पर पहुंच गया। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ने विधानसभा का चुनाव लड़ा तो पुलिस कप्तान ने उनकी भरपूर मदद भी की। इससे साहब को ऐसा लगने लगा कि जिले में उनके आगे सब बौने हैं। इसका असर यह हुआ कि जिले के अन्य राजनेताओं के साथ ही वे जिले से आने वाले प्रदेश सरकार के एक मंत्री की बातें भी नहीं मान रहे थे। मंत्रीजी को यह बात नागवार गुजरी और वे साहब की इस नीयत पर इस कदर भड़के कि उन्होंने भी अपने पावर का उपयोग करते हुए स्वयंभू एसपी को जिले से रवानगी डलवाकर उन्हें चारों खाने चित्त कर दिया। अब साहब अपनी गलती पर हाथ मल रहे हैं।

पूर्व मंत्री की वापसी की सुपारी

अभी तक आपने किसी को जान से मरवाने की सुपारी का मामला सुना होगा, लेकिन प्रदेश सरकार के एक मंत्रीजी ने तो पार्टी छोड़कर गए एक पूर्व मंत्री को वापस लाने की सुपारी ले ली है। मालवा क्षेत्र से आने वाले उक्त मंत्रीजी अपनी राजनीतिक हैसियत के लिए जाने जाते हैं। संघ और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। इसलिए उन्होंने पूर्व मंत्री को विश्वास दिलाया है कि उनकी पार्टी में वापसी हो जाएगी। शायद यही वजह है कि दोनों नेताओं के बीच एक माह में कई मुलाकातें हो चुकी हैं। गौरतलब है कि जिन पूर्व मंत्री को पार्टी में लाने की कवायद में वर्तमान मंत्री जुटे हुए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी वापसी की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। लेकिन जिस दिन उन्हें पार्टी में वापस आना था, कुछ नेताओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई और पूर्व मंत्रीजी की घर वापसी का मामला अधर में लटक गया। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस बार उन्होंने प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री को माध्यम बनाया है और अपनी वापसी की मंशा जाहिर की है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है?

मप्र रेरा में अटके बिल्डरों के प्रोजेक्ट

मप्र में करीब 7 साल पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) का गठन किया गया था, ताकि लोगों को नियत समय पर, सुविधाओं के साथ सही दर पर बिल्डरों द्वारा आवास मिल सके। लेकिन विडंबना यह है कि रेरा की मनमानी के कारण बिल्डर्स के साथ ही आम आदमी भी परेशान है। इसकी वजह यह है कि रेरा में जांच के नाम पर बिल्डरों के प्रोजेक्ट लटकाए जा रहे हैं। इस कारण बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को शुरू नहीं कर पा रहे हैं। आलम यह है कि रेरा के अनुसार जिन फाइलों को निपटाने में ढाई दिन लगता है, वे फाइलें महीनों से रेरा में धूल खा रही हैं। रेरा की लालफीताशाही और भर्राशाही के खिलाफ समय-समय पर आवाज उठती रही है। एक बार फिर कुछ बिल्डरों ने रेरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

गौरतलब है कि प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी इंदौर, राजधानी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में बड़े-बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं। इन प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर रेरा की परमिशन लेने पहुंचते हैं। रेरा का काम इतना होता है कि वह अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई अनुमतियों का अवलोकन करे और नंबर दे दे। लेकिन विडंबना यह है कि बस इतने काम के लिए रेरा में महीनों तक प्रोजेक्ट लटके रहते हैं। जानकारी के अनुसार रेरा के खिलाफ शासन के पास कई शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें नियमों का उल्लंघन करने, प्रोजेक्ट्स में देरी करने और आकृति गार्डन के प्रमोटर्स के 12 प्रोजेक्ट्स को रद्द करने का आरोप भी शामिल है। इन शिकायतों पर शासन स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आकृति गार्डन प्रोजेक्ट के मामले में खुद प्रमोटर्स ने यह आरोप लगाया है कि रेरा ने उन्हें परेशान करने की नीयत से प्रोजेक्ट रद्द किए हैं। इसके कारण फर्म को बैंकों से मिलने वाला 80 से 100 करोड़ का लोन अटक गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी वैधानिक संस्था के प्रमुख अगर किसी मामले में खुद शामिल होते हैं, तो वे उस मामले की सुनवाई से बचते हैं।

क्रेडाई के विपिन गोयल का आरोप है कि शासकीय अधिकारियों से मिली मंजूरी को बार-बार जांचा जा रहा है और कमियां निकालकर प्रोजेक्ट्स को अटकाया जा रहा है, जो काम 30 दिनों में होना चाहिए, उसमें 6 से 8 महीने का समय लिया जा रहा है। रेरा एक्ट लागू होने के बाद 21 राज्यों के 217 शहरों में 13,000 बिल्डर-डेवलपर्स काम कर रहे हैं, लेकिन मप्र में समस्याओं को और बढ़ाया जा रहा है। शासन से बिना अनुमोदन के गलत सीए सर्टिफिकेट लागू कर दिया गया है। वहीं एजी-8 के प्रमोटर्स हेमंत कुमार सोनी का कहना है कि पलाश गृह निर्माण सहकारी संस्था लिमिटेड की जमीन पर रेरा ने 12 अप्रैल 2003 को आकृति डेवलपिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट किया था। काम में देरी होने पर फर्म के आकृति एक्वासिटी, आकृति गार्डन समेत 12 प्रोजेक्ट्स की सुनवाई की और परेशान करने की नीयत से सभी को रद्द कर दिया। बिल्डरों का कहना है कि रेरा के नियम सिर्फ बिल्डर और जनता के लिए हैं लेकिन खुद के लिए नहीं हैं। चार साल पहले प्रभावी हुए रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट (रेरा) में स्पष्ट लिखा है कि बिल्डर को किसी भी स्थिति में समय पर काम पूरा कर देना होगा। यदि बिल्डर समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो उसे 11 फीसदी दर से ग्राहकों को ब्याज अदा करना होगा। वहीं बिल्डर द्वारा काटी गई कॉलोनियों में प्लॉट या मकान बुकिंग करने पर ग्राहकों को भी समय पर बिल्डर को राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं करने पर बिल्डर भी ग्राहकों से ब्याज वसूल सकेंगे। ये तो रही रेरा द्वारा बिल्डर और जनता के लिए बनाए गए कानून की।

उधर, रेरा की लालफीताशाही के कारण जिन लोगों ने प्लॉट बुक कर लिए हैं उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। कॉलोनी रेरा से अप्रूवड नहीं होने से नगर निगम को हैंडओवर नहीं हो रही है। कई बिल्डरों ने ब्याज पर राशि उठा रखी है। रेरा की अनुमति नहीं मिलने से वे रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे हैं। इससे बुकिंग के बाद की राशि नहीं मिल रही है, रुपए अटक गए हैं। जानकारों का कहना है कि रेरा एक्ट-2017 के तहत एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को 30 दिन में मंजूरी देना जरूरी है। इसके बाद वह प्रोजेक्ट डीम्ड एप्रूव्ड माना जाता है। डेवलपर डीम्ड एप्रूव्ड प्रोजेक्ट को मंजूर मानकर घर बनाना और बुकिंग लेना शुरू कर सकता है। लेकिन रेरा में अधिकतर मामलों में क्वेरी 29वें दिन लगाई जाती है, जिससे वह डीम्ड एप्रूवल का पात्र न रहे। इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेरा का उद्देश्य मंजूरी देना है या उसे अटकाना।

● **कुमार राजेंद्र**

लोगों को 20 प्रतिशत तक महंगे मिल रहे घर

मप्र रियल एस्टेट रेगुरेटरी अथॉरिटी (रेरा) में अनुमतियों की लगातार पेंडेंसी बढ़ रही है। इसकी वजह से निजी तो निजी डेवलपर, बल्कि सरकारी एजेंसियों को भी परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल, जो अनुमति 30 दिन में मिल जानी चाहिए, उसे देने में रेरा को तीन महीने से एक साल तक लग रहा है। रेरा के पास प्राइवेट डेवलपर के आवेदन महीनों से लंबित हैं। कई मामले तो ऐसे सामने आए हैं, जिनमें रेरा नगर निगम और टीएंडसीपी की अनुमति पर भी आपत्ति ले रहा है। जबकि, इस तरह की अनुमति देना या आपत्ति उठाना रेरा के अधिकार में ही नहीं है। बिल्डरों का कहना है कि रेरा की वजह से लोगों को 20 फीसदी महंगे घर खरीदने पड़ रहे हैं। क्योंकि, प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले डेवलपर ज्यादा दरों की गाइडलाइन के मुताबिक जमीन खरीदता है। उसके बाद उस पर साढ़े बारह फीसदी रजिस्ट्री देता है, उसके बाद बाकी अनुमतियों के शुल्क चुकाता है। ऐसे में जब उसका प्रोजेक्ट रेरा के पास अटका होता है तो डेवलपर को अनुमति मिलने तक ब्याज भी चुकाना होता है। इस वजह से घरों की कीमत बढ़ती जाती है। कॉलोनियों को रेरा की अनुमति नहीं मिलने से प्रॉपर्टी बाजार पर बुरा असर हो रहा है। ठेकेदार, लेबर को भी काम नहीं मिल पा रहा है। सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। इससे तो इस कानून के पहले की स्थिति अच्छी थी। कॉलोनियां पूरी तरह से कम्प्लीट हैं। इसके बाद भी रेरा की अनुमति नहीं मिल रही है।

अधर में मंत्रियों के आश्वासन

विभाग की टालमटोल के चलते मंत्री निरुत्तर

जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले विधायक सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं, विभिन्न समस्याओं या अन्य मसलों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न उठाते हैं। जिनका जवाब विधानसभा के माध्यम से संबंधित विभाग उपलब्ध कराता है। यह जानकारी उपलब्ध कराना विभाग के लिए आवश्यक है। लेकिन पिछली विधानसभा के दौरान कुछ विभागों द्वारा जानकारी देने में टालमटोल भरा रवैया अपनाया गया। इस वजह से विभागीय मंत्री सदन में विधायकों के इन प्रश्नों का जवाब भी नहीं दे पाए। ऐसी स्थिति में आश्वासन देकर टाल दिया गया और विभाग को जानकारी जल्द उपलब्ध कराने पत्र भी भेजे गए।

मप्र विधानसभा में मंत्रियों की ओर से सवाल के जवाब देने के लिए दिए गए आश्वासनों की पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनमें कई गंभीर मामले भी हैं। खासकर भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे सवाल पूछने वाले विधायक भी असमंजस में फंसे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मां रतनगढ़ नहर सिंचाई परियोजना में बिना कार्य हैदराबाद की कंपनी मंटेरा वशिष्ठा माइक्रो जेवी को 412 करोड़ रुपए की राशि का एडवांस भुगतान किए जाने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने के सवाल पर सरकार ने कहा कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, हैदराबाद की ही मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी को किए गए भुगतान में अनियमितताओं का मामला भी पेंडिंग पड़ा हुआ है।

जानकारों का कहना है कि मप्र विधानसभा में विधायकों द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने में अधिकारियों की रूचि नहीं है। गौरतलब है कि तत्कालीन विधायक कुंवर रविंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा में सवाल उठाया था कि मां रतनगढ़ नहर सिंचाई परियोजना में कार्य किए बिना निर्माण एजेंसी मंटेरा वशिष्ठा माइक्रो जेवी हैदराबाद को 412 करोड़ का भुगतान किए जाने की शिकायत मिलने पर सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की है। इसके जवाब में विभाग ने कहा कि समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सदस्य रहे हर्ष यादव के सवाल सूरजपुरा जलाशय निर्माण एजेंसी को नियम विरूद्ध पूर्ण भुगतान करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, इसके जवाब में विभाग ने कहा कि कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

पूर्व विधायक केपी सिंह कक्काजू ने शिवपुरी जिले में उर परियोजना नहर निर्माण में आने वाले किसानों की जमीनों के मुआवजा भुगतान नहीं होने पर विभाग का जवाब था, भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। दिनेश राय मुनमुन में हैदराबाद की मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी को जल संसाधन विभाग द्वारा **भुगतान** में अनियमितता पर कार्रवाई के सवाल पर कहा- कार्रवाई नियमानुसार की जा सकेगी। पूर्व सदस्य राकेश मावई ने ग्वालियर, दतिया एवं भिंड जिलों में प्रस्तावित रतनगढ़ नहर परियोजना में हुई अनियमितता की जांच कराया जाना। नियम विरूद्ध भुगतान, जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यवर्धन सिंह ने राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ अंतर्गत पार्वती परियोजना से प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली में अनियमितता की जांच कराने पर विभाग ने जवाब दिया, जांच समिति गठित, प्रतिवेदन अपेक्षित। डॉ. हीरालाल अलावा ने मांग की थी कि धार जिले के मनावर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम काकडदा से बहदरा, सुरानी, नीलदा, धोलीबाड़ी, पठा-करोदियाखुर्द, जमानिया मोटा, पिपलिया मोटा, मंडावादा से पाडला तक सिंचाई के लिए परियोजनाओं जलाशय नहरों से लाभ दिए जाने और नलजल योजना जलजीवन मिशन के तहत पानी पहुंचाने पर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग की गई थी। इस पर मंत्री ने जवाब दिया था सरकार परीक्षण कराएगी। यह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे करीब सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और सिंचाई प्रोजेक्ट प्रारंभ करने के 100 से अधिक आश्वासन जंल संसाधन विभाग में पेंडिंग हैं।

मप्र देश विधानसभा में 7 साल पहले मंत्रियों की ओर से सवाल के जवाब देने के लिए दिए गए आश्वासन अभी तक पेंडिंग हैं। अकेले जल संसाधन विभाग के ही 113 सवालों के जवाब में दिए गए आश्वासन पर सरकार की ओर से अभी तक विधानसभा को अवगत नहीं कराया गया है। इसमें वर्ष 2017 में दिए गए कई आश्वासन भी शामिल हैं। इसे देखते हुए अब विधानसभा सचिवालय ने जल संसाधन विभाग को लंबित आश्वासनों की सूची भेजी है और इसका जल्द से जल्द जवाब भेजने को कहा है। यह विभाग 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद से अब तक मंत्री तुलसी सिलावट के पास है। सवाल करने वाले कई विधायक 2018 का चुनाव हारने के बाद 2023 में फिर विधायक बन गए हैं जिसमें मुकेश नायक भी शामिल हैं। वहीं, कुछ विधायक पिछले चुनाव में हार के कारण अब पूर्व विधायक बन गए हैं। पन्ना जिले में बांध टूटने के कारण और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जांच को लेकर विधानसभा में सवाल उठा था जिसमें ठेकेदार मेसर्स त्रिशूल कंस्ट्रक्शन जबलपुर से खर्च हुई राशि की वसूली होनी थी। इस मामले में सरकार ने विधानसभा में आश्वासन दिया था कि विभागीय जांच की जा रही है, और ठेकेदार के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई के लिए मुख्य अभियंता धसान केन कछार सागर द्वारा नोटिस जारी किया है। कार्यपालन यंत्री पन्ना ने सिरस्वाहा तालाब निर्माण का एग्रीमेंट अमान्य कर दिया है, और ठेकेदार से राशि की वसूली की जाएगी। फरवरी मार्च 2017 में विधानसभा सत्र के दौरान दिए गए मंत्री के आश्वासन का जवाब अब तक विधानसभा तक नहीं पहुंच सका है। यह बांध 2016 की बारिश में टूटा था और चार गांवों की बस्तियां जलमग्न हो गई थीं। शहडोल जिले के ब्यौहारी तहसील के ग्राम बिजहा में दुधारिया नदी पर सिंचाई परियोजना में किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है लेकिन मुआवजा नहीं दिया है। किसानों की 70.181 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का यह मामला पूर्व विधायक केदारनाथ शुक्ला ने मार्च 2017 के विधानसभा सत्र में उठाया था। इसका जवाब भी विधानसभा को सरकार अब तक नहीं दे सकी है।

● **विकास दुबे**

चर्चा में 2 अधिकारियों का मंडला वाला रिसोर्ट

मप्र की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक रिसोर्ट लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आदिवासी जिला मंडला में स्थित यह रिसोर्ट विवादित चीफ इंजीनियर जीपी वर्मा और एसआर बघेल का है। बघेल पीआईयू के ईएनसी हैं। जीपी वर्मा वही हैं जिन्होंने करोड़ों का एक टेंडर गुजरात की एक कंपनी एयरकॉन को दे दिया था, जो इंदौर स्थित जिला न्यायालय का था। टेंडर में टेक्नीकल क्वालिफिकेशन गलत होने के बावजूद भी जीपी वर्मा ने अपनी मनमर्जी करके टेंडर अवार्ड कर दिया। इस पूरे मामले को उनके कॉम्पीटिटर कल्याण टोल कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत की और यह मामला न्यायालय तक पहुंच गया, उसके बाद उनके टेंडर को निरस्त किया गया। कंपनी के मालिक को जेल की हवा खानी पड़ी। बाद में यह भी पता चला कि बैंक गारंटी भी नकली थी। इस पूरे मामले में अधिकारी मुंह देखते रह गए। इस पूरे मामले में जीपी वर्मा की भूमिका संदिग्ध है। इस मामले की इंदौर के एक थाने में शिकायत भी हुई थी। अब पता चला है कि इस मामले में वर्मा के खिलाफ लोकायुक्त ने ईई दर्ज कर ली है।

संजय खाड़े की एफआईआर

वहीं एक सनसनीखेज खबर सामने आई है कि निर्माण विभाग के एक अधिकारी संजय खाड़े जो कांग्रेस शासनकाल में एक पूर्व मंत्री के ओएसडी भी रह चुके हैं, पर लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। खाड़े वर्तमान में इंदौर में पदस्थ हैं।

1 पद, 4 की सिफारिश

वाकई मप्र अजब है और गजब है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता कार्यालय में भृत्य के लिए एक पद निकला है। यह पद दिव्यांग कोटे का है और आठवीं पास पात्रता है। लेकिन इस एक पद के लिए मुख्यमंत्री से लेकर विभागीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित 4 मंत्रियों की सिफारिश पहुंची है। इस कारण अभी तक इस एक पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार दिव्यांगों की भर्ती मैरिट के आधार पर (स्कूल-कॉलेज में मिले प्राप्तांक) की जाती है। बताया जाता है कि एक पद के लिए 10 नामों की वेटिंग लिस्ट बनाई गई है। इनमें से 7 अभ्यार्थी ऐसे हैं, जिनके आठवीं क्लास में 90 से लेकर 99.83 फीसदी अंक आए हैं। ऐसे में अफसरों के सामने समस्या खड़ी हो गई है कि किसको उक्त पद पर नियुक्ति दी जाए। क्योंकि कुछ स्नातक, बीटेक और पीजीडीसीए किए हुए अभ्यार्थी भी हैं। ऐसे में विभाग के सामने समस्या आ गई है कि किसको भर्ती किया जाए। वहीं वेटिंग लिस्ट देखकर कहा जा रहा है कि अगर वाकई दिव्यांग अभ्यार्थी इतने प्रतिभाशाली हैं तो सरकार उनके लिए कोई ऐसी पहल क्यों नहीं करती, ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े पद हासिल करें।

रापुसे से भापुसे में पदोन्नति के प्रस्ताव पर फंसा पेंच

राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति का मामला अधर में लटक गया है। दरअसल, इसके लिए डीपीसी मई तक हो जानी चाहिए थी। लेकिन देरी होने के कारण मामला फंस गया है। जानकारों का कहना है कि राज्य पुलिस सेवा के चार अधिकारियों की आईपीएस संवर्ग में पदोन्नति के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने पेंच फंसा दिया है। जीडीए ने गृह विभाग से प्रस्तावित अधिकारियों की जांच से जुड़ी रिपोर्ट पर जानकारी मांगी है। यह प्रदेश में पहली बार है, जब राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों से जुड़े प्रस्ताव पर दूसरे विभाग द्वारा अनापत्ति देने के लिए जानकारी मांगी गई है। वर्ष 2024 में प्रदेश को चार भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पद मिले हैं, जिन पर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति होनी है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय ने 12 अधिकारियों के नाम प्रस्तावित किए। गृह विभाग ने दस्तावेजों का परीक्षण कर सामान्य प्रशासन विभाग को अनापत्ति के लिए फाइल भेजी पर इसमें अधिकारियों ने पेंच फंसा दिया। अनापत्ति देने के स्थान पर जांच से जुड़ी जानकारियों पर स्पष्टीकरण मांग लिया। दरअसल, जिस अधिकारी का नाम प्रस्तावित किया जाता है, उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण या विभागीय जांच तो नहीं चल रही है या आरोप पत्र तो जारी नहीं किया गया, जैसी जानकारी देनी होती है। गृह विभाग ने इसे शामिल करते हुए फाइल भेज दी, पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने इस पर स्पष्टीकरण मांग लिया। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि हमारा प्रस्ताव पूरा है और उसमें सभी जानकारियों का समावेश है। एक बार फिर अवलोकन कर लिया जाए। यदि विभाग इससे संतुष्ट हो जाता है तो फिर मुख्य सचिव से अनापत्ति लेकर प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग भेजा जाएगा। वहां प्रस्ताव का परीक्षण करने के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की तिथि निर्धारित होगी, जिसमें 12 नामों पर विचार कर चार का चयन किया जाएगा। उधर, राज्य पुलिस सेवा संगठन भी सरकार के पास ज्ञापन लेकर पहुंचा है और कहा है कि हम लोग इतने दिनों से सेवा में हैं, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है।

डिप्टी कलेक्टर की डीपीसी 6 माह लेट

प्रदेश में 2023 के डिप्टी कलेक्टरों की डीपीसी का मामला भी अधर में लटका हुआ है। अभी तक यह डीपीसी 6 माह लेट हो गई है। डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने के लिए इस बार 8 पदों के लिए डीपीसी होनी है, जिसमें 24 नाम शामिल किए जाएंगे। यानि एक आईएएस के लिए 3 डिप्टी कलेक्टर दावेदार बनेंगे। सूत्रों का कहना है कि इनमें से 4 के लिफाफे इस बार बंद ही रहेंगे। इनमें से एक सुरेंद्र कुमार कथूरिया का लिफाफा पिछली बार भी बंद हो गया था। ये बर्खास्त कर दिए गए हैं। वहीं 3 और लोगों के लिफाफे बंद होने की संभावना है, इनमें पंकज शर्मा, कैलाश बुंदेला और कमल नागर का नाम शामिल है। दरअसल इन तीनों के खिलाफ जांच विचाराधीन है। अब देखना यह है कि डिप्टी कलेक्टर से आईएएस बनने की चाह रखने वाले किन-किन अफसरों की लॉटरी लगती है।

अब आईपीएस के तबादले की बारी

मप्र सरकार द्वारा हाल ही में आईएएस अधिकारियों की दो तबादला सूची जारी की जा चुकी है। इसके बाद अब सरकार आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले करने जा रही है। इसमें कई महत्वपूर्ण पदों पर आईपीएस अफसरों की नवीन पदस्थापना की जानी है। वहीं पुलिस मुख्यालय की कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं में जिम्मेदारी का प्रभार भी बदले जाने की संभावना है। जिन पदों पर नवीन पदस्थापना की सबसे अधिक चर्चा है, उनमें डीजीपी, लोकायुक्त, ईओडब्ल्यू, परिवहन आयुक्त, भोपाल और इंदौर पुलिस आयुक्त प्रमुख हैं।

उपरोक्त बड़े पदों के अलावा कुछ आईजी और एसपी भी बदले जाएंगे। धार, रतलाम, होशंगाबाद, रीवा, सतना, बड़वानी जिले के एसपी के साथ भोपाल व इंदौर के कुछ डीसीपी को भी बदला जा सकता है। लगभग आधा सैकड़ा राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी बदले जाने को लेकर प्रारंभिक दौर की चर्चा हो चुकी है। निरीक्षकों के नियमित तबादलों को लेकर अभी तक पुलिस तबादला बोर्ड की कोई बैठक नहीं हो सकी है, जिसके कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

मुश्किल में एडीजी

1993 बैच के आईपीएस अधिकारी अनिल गुप्ता मुश्किल में पड़ गए हैं। दरअसल, रवानगी की तैयारी कर रहे गुप्ता को शोकाज नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि तकनीकी विभाग में खरीद-फरोख्त करने की प्रक्रिया में त्रुटि मिली थी। जिसकी जांच वरिष्ठ अधिकारी 1992 बैच के जी जर्नाधन रेड्डी ने की थी और वे गुप्ता को फंसा गए।

ताकि दाग न लग पाए...

कथित तौर पर आशिकी के चक्कर में फंसे एक आईपीएस अधिकारी ने अपनी शादी की वर्षगांठ पर पत्नी को खुश करने और अपने को पाक साफ बताने के लिए फेसबुक पर अपनी धर्मपत्नी के एक से बढ़कर एक फोटो डाले। इन फोटो में साहब का अपनी पत्नी से प्रेम की झलक सबने देखी। दरअसल, साहब का प्रेम विवाह हुआ है। लेकिन इसके बावजूद वे अपने एक मातहत को भी अपना दिल दे बैठे हैं। इस बात की खबर साहब जहां पदस्थ हैं, वहां के हर एक व्यक्ति को है। वहीं साहब और उनके मातहत की आशिकी प्रशासनिक वीथिका में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। साहब की शादीशुदा जिंदगी में उनकी आशिकी विलेन न बन जाए, इसके लिए साहब ने अजब तोड़ निकाला और लोगों का मुंह बंद करने के लिए पत्नी के साथ अपना फोटो फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि साहब अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं।

आखिर क्यों भाग रहे ठेकेदार?

मप्र सिंचाई विभाग द्वारा 2 जिलों बालाघाट और सिवनी में टूटी-फूटी नहरों की मरम्मत की जानी है, लेकिन इसके लिए कोई भी ठेकेदार तैयार नहीं हो रहा है। दोनों जिलों से होकर गुजरने वाली 3 नहरें इस कदर खराब हो गई हैं कि उनका पानी रिस जाता है। ये नहरें हैं भीमगढ़ राइट बैंक केनाल, तिलवारा लेफ्ट बैंक केनाल, धुती लेफ्त बैंक केनाल। भीमगढ़ राइट बैंक केनाल का काम 11353.798 लाख रुपए का है। वहीं तिलवारा लेफ्ट बैंक केनाल का काम 6062,60 लाख का तथा धुती लेफ्त बैंक केनाल का काम 9841.32 लाख का है। अब तक 3 बार टेंडर निकाल चुका है। लेकिन विडंबना यह है कि पहली बार तो किसी ने टेंडर ही नहीं डाला। उसके बाद के दो बार जो टेंडर निकाले गए, उसमें एक में 2 और एक में 3 ठेकेदार शामिल हुए, लेकिन बाद में वह भी हट गए। सूत्रों का कहना है कि मप्र के एक रसूखदार नेता और पूर्व मंत्री के पुत्र जो वर्तमान में विधायक हैं, उनकी मनमानी के कारण कोई भी ठेकेदार उक्त काम को करने को तैयार नहीं है। बताया जाता है कि विधायक की ठेकेदारों से मांग है कि पहले 11 प्रतिशत कमीशन दो, फिर काम शुरू होगा। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में स्थानीय विधायक सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं।

● राजेंद्र आगाल

जनवरी में काम, प्रशासकीय स्वीकृति अभी

प्रदेश में एक तरफ सरकार सुशासन पर जोर दे रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का कड़ाई से पालन करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ऐसा ही मामला मंत्रियों के आवास के रिनोवेशन में सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा के लिए जनवरी में ही 20 करोड़ रुपए जारी कर काम शुरू करवा दिया गया था, लेकिन उसकी प्रशासकीय स्वीकृति अभी दी गई है। मंत्री इन बंगलों में ठाठ-बाट से रहेंगे, वहीं अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार भी मालामाल हो जाएंगे। दरअसल, प्रदेश में यह परंपरा चल पड़ी है कि हर साल मंत्रियों के बंगलों की साज-सज्जा पर करोड़ों खर्च होना है। इस बार तो हद यह हो गई कि जल्दबाजी में काम कराने के लिए बजट पहले जारी कर दिया गया और उसकी प्रशासकीय स्वीकृति अब दी गई है।

7 माह बाद भी बिना टीम पटवारी

मप्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बदले हुए 7 माह से भी अधिक का समय बीत चुका है। लेकिन, अभी तक कांग्रेस कमेटी का कोई अता-पता नहीं है। करीब दो माह पहले प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह द्वारा कहा गया था कि आने वाले 15 दिनों में कार्यकारिणी का गठन कर दिया जाएगा। लेकिन, अब तक कमेटी का गठन नहीं हो सका है। इस कारण प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बिना टीम के काम कर रहे हैं। यही नहीं मप्र कांग्रेस कार्यकारणी के लिए कार्यकर्ताओं को अभी इंतजार करना होगा।

दरअसल, कार्यकारिणी गठन को लेकर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का कहना है कि काम करने वाले (जमीनी) कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। पूरे समय पार्टी के लिए काम करने वालों को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। प्रदेश प्रभारी ने पुरानी कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले की कार्यकारिणी में एक हजार पदाधिकारी शामिल थे। सिर्फ पद लेकर घर पर बैठे थे, अब सिर्फ काम करने वालों को जिम्मेदारी मिलेगी। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद मप्र कांग्रेस कमेटी लगातार बैठकें कर रही है। नई कार्यकारिणी को लेकर मंथन किया जा रहा है।

सूत्रों का कहना है कि मप्र में कांग्रेस नेता बीते कई महीनों से पीसीसी के गठन का दावा कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों के नामों पर ही आम सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल, लोकसभा चुनाव में देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मप्र में सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसका बड़ा कारण प्रदेश में संगठन में हुआ बिखराव और नेताओं का दलबदल भी बताया जा रहा है। अब नए सिरे से संगठन खड़ा करने की कवायद जारी है। नई टीम के गठन में हो रही देरी के बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। बैठकों के जरिए पार्टी कमजोर कड़ी तलाशने में जुटी हुई है। पार्टी सूत्रों की मानें तो पीसीसी चीफ नई टीम को लेकर एक सूची पार्टी हाईकमान को सौंप चुके हैं। नई टीम में 100 के करीब पदाधिकारी होंगे। इस सूची को लेकर दिल्ली में चर्चा भी हुई, लेकिन वरिष्ठ नेताओं की अपत्ति के बाद इसे जारी नहीं किया जा सका। अब वरिष्ठ से भी नाम लिए जा रहे हैं।

कांग्रेस प्रदेश में युवाओं को आगे करना चाहती है। इसलिए प्रदेश कार्यकारिणी में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जगह देने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं पूर्व में हुई कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की बैठक में निर्णय हुआ है कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। राजनीतिक एवं वैचारिक प्रतिबद्धता से संबंध रखने वाले कांग्रेसजनों को संगठन में स्थान दिया जाएगा। मोर्चा संगठनों को और अधिक प्रभावी और गतिशील बनाने और सक्रियता के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। संगठन के प्रत्येक स्तर बूथ, सेक्टर, मंडलम, ब्लाक और जिलास्तर पर अधिक से अधिक सक्रिय और राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं की भागीदारी की जाएगी। सेवादल द्वारा प्रदेशभर में ब्लॉक स्तर पर पार्टी की गतिविधियों और कांग्रेस पार्टी से लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः प्रारंभ किए जाएंगे।

प्रदेश में कांग्रेस को विधानसभा में मिली हार के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जीतू पटवारी नई कार्यकारिणी बनाने के लिए लगातार मंथन कर रहे हैं। काफी समय बीत गया है, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया है। लगातार प्रदेश और दिल्ली में हुई बैठक के बाद अनुमान लगाया जा रहा था कि अगस्त माह में ही कार्यकारिणी की घोषणा कर दी जाएगी लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। कार्यकारणी के लिए कार्यकर्ताओं को अभी इंतजार करना होगा। दरअसल, कार्यकारिणी गठन को लेकर गत दिनों भोपाल पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि काम करने वाले जमीनी कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के नामों पर विचार किया जा रहा है। पूरे समय पार्टी के लिए काम करने वालों को कार्यकारिणी में जगह मिलेगी। प्रदेश प्रभारी ने पुरानी कार्यकारिणी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले की कार्यकारिणी में एक हजार पदाधिकारी शामिल थे। सिर्फ पद लेकर घर पर बैठे थे, अब सिर्फ काम करने वालों को जिम्मेदारी मिलेगी। इधर, कमलनाथ और नकुलनाथ के इशारे पर छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले की कार्यकारणी भंग कर दी गई है। जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी पीसीसी चीफ को नहीं दी गई है। इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

● **अरविंद नारद**

बगैर जानकारी दिए ही जारी किया प्रेस नोट

इधर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को जानकारी दिए बिना छिंदवाड़ा कार्यकारिणी भंग की गई है। छिंदवाड़ा कांग्रेस ने कार्यकारिणी को एक दिन पहले भंग करने का प्रेस नोट जारी किया है। प्रेस नोट में कमलनाथ और नकुलनाथ के चर्चा के बाद कार्यकारिणी भंग करने का जिक्र है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का प्रेस नोट में कोई जिक्र नहीं है। दरअसल, जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद से पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है। पटवारी के आने के बाद अब तक आधा दर्जन पूर्व मंत्री और तीन कांग्रेस विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उन्हें अध्यक्ष के रूप में अब तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जारी प्रेस नोट में लिखा गया कि मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व पूर्व सांसद नकुलनाथ से चर्चा के उपरांत कांग्रेस की समस्त कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। आगामी दिनों में जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे व पांढुर्ना जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झलके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा व पांढुर्ना की जिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी, पर्यवेक्षक, प्रभारी, चारों मोर्चा संगठन की कार्यकारिणी, समस्त प्रकोष्ठों व विभाग को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है।

मप्र में पहले विधानसभा उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। उनमें से एक हैं बीना की विधायक निर्मला सप्रे। ये कांग्रेस से भाजपा में शामिल तो हो गई हैं, लेकिन अभी भी कांग्रेसी विधायक बनी हुई हैं। शायद इन्हें हार का डर सता रहा है इसलिए विधायकी छोड़ नहीं रही हैं।

निर्मला को सता रहा हार का डर!

5 मई को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाली बीना विधायक निर्मला सप्रे करीब साढ़े तीन माह बाद भी विधायक पद से इस्तीफा नहीं दे पाई हैं। वहीं निर्मला सप्रे विधानसभा को भी नहीं बता पाईं हैं कि वे विधायक पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहीं। जानकारों का कहना है कि शायद उन्हें भी इमरती देवी वाला डर सता रहा है। इमरती देवी को एससी होने के कारण डबरा से कांग्रेस प्रत्याशी बनकर जीत मिली थी। मगर फिर उन्हें दलबदल के बाद हार मिली। यहां तक कि विधानसभा चुनाव 2023 में भी इमरती देवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। जानकारों का कहना है कि निर्मला सप्रे को इमरती देवी की कहानी याद आ रही होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि वह कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के टिकट पर लड़े और यहां भी जीत हासिल कर लें।

गौरतलब है कि विधानसभा ने बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के खिलाफ दलबदल के तहत नोटिस जारी किया है। विधानसभा कार्यालय ने उन्हें जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। लेकिन तकरीबन एक माह का समय होने को है लेकिन निर्मला सप्रे अभी तक विधानसभा सचिवालय का इस्तीफा न देने की स्थिति का कारण नहीं बता पाई हैं। उधर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निर्मला सप्रे अब कांग्रेस में ही रहना चाहती हैं और वह पार्टी के आला नेताओं से मिलकर भाजपा में शामिल होने के हालातों के बारे में अपना पक्ष रखना चाहती हैं। दूसरी तरफ भाजपा चुप्पी इसलिए साधे है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है, उसे किसी तरह की विधायक तोड़ने की जरूरत नहीं है। चुनाव के दौरान कांग्रेस का मनोबल तोड़ने के लिए उनके द्वारा चली गई चाल कामयाब हो चुकी है।

बता दें कि बीना विधायक निर्मला सप्रे को भाजपा में शामिल हुए साढ़े तीन महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक कांग्रेस के विधायक के तौर पर इस्तीफा नहीं दिया है। निर्मला सप्रे विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीती थीं। भाजपा में शामिल होने के बाद वे अब भी कांग्रेस विधायक हैं। बता दें कि मप्र के सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे बीते मई महीने में भाजपा में शामिल हो गईं थीं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से दो दिन पहले लिया। इस दौरान निर्मला सप्रे ने अपने फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि कांग्रेस में रहते हुए कोई इस क्षेत्र में विकास नहीं ला सकता, क्योंकि वहां न तो कोई सरकार है और न ही कोई एजेंडा। जब पूरा देश और राज्य विकास का अनुभव कर रहा है, तो हमारे बीना को क्यों छोड़ा जाना चाहिए?

...तो मैं इस्तीफा दे दूंगी

गौरतलब है कि बीना विधायक निर्मला सप्रे पहले ही कह चुकी हैं कि बीना को जिला बनाने सहित अन्य विकास के वादे 50 प्रतिशत भी पूरे होते हैं, तो मैं विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगी। मुझे विश्वास है कि बीना विकास को लेकर मेरी सभी मांगे जल्दी ही पूरी हो जाएंगी। निर्मला सप्रे का कहना है कि पार्टी जब बोलेगी तब मैं इस्तीफा दे दूंगी, लेकिन निर्मला सप्रे से सवाल किया गया कि इस्तीफा देने से क्या पार्टी ने ही रोका है, तब सप्रे ने कहा कि मेरी आधी मांगे भी मान ली जाती है तो मैं रिजाइन दे दूंगी। गौरतलब है कि बीना को जिला बनाने, रिंग रोड और सिंचाई परियोजना सहित 12 मांगे विधायक सप्रे ने रखी थीं। बीना को जिला बनाने की यूं तो कई बार मंचों से घोषणा की जा चुकी है, लेकिन इस बार विधायक सप्रे चाहती है कि बीना को जिला बनाने का नोटिफिकेशन ही जारी हो और अन्य कार्यवाहियां शुरू हो जाएं।

विधानसभा सचिवालय ने 24 जुलाई को विधायक निर्मला सप्रे को पत्र जारी किया था। इसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका का हवाला देते हुए उनसे विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं देने के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। उनसे पत्र की प्राप्ति के 10 दिन की अवधि में अध्यक्ष के समक्ष जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया था। पत्र जारी हुए महीनेभर से अधिक हो गया है, लेकिन उन्होंने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है। उन्होंने जवाब देने के लिए विधानसभा सचिवालय से समय मांगा है। विधानसभा सचिवालय सभा के अधिकारियों का कहना है कि विधायक निर्मला का जवाब प्राप्त होने के बाद ही इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। विधायक निर्मला सप्रे का कहना है कि उन्होंने पत्र का जवाब देने के लिए विधानसभा से एक महीने का समय मांगा है। इस अवधि में वे पत्र का जवाब दे देंगी। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पिछले दिनों मप्र विधान सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 1986 के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष को याचिका दायर की थी। इसमें कहा गया है कि विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस की सदस्यता त्यागकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, इसलिए निर्मला को विधानसभा की सदस्य निरर्ह घोषित कर उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। इसी याचिका के आधार पर विधानसभा सचिवालय ने निर्मला सप्रे को पत्र जारी किया है। गौरतलब है कि बीना विधायक निर्मला सप्रे गत 5 मई को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं। इसके बाद से ही कांग्रेस उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त करने की मांग कर रही है। हालांकि उन्होंने अब तक विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।

● **प्रवीण सक्सेना**

इस समय देश में जाति की राजनीति अपने चरम पर है। विपक्षी पार्टियां जातिगत मुद्दों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने में जुटी हुई हैं। इन सबके इतर मप्र की मोहन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियों को विकास का आधार बनाकर मप्र को विकसित राज्य बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का मानना है कि इससे प्रदेश में समुचित विकास होगा।

विकास के लिए बनेंगे 4 मिशन

अपने 8 माह के शासनकाल में कथनी और करनी की समानता के कारण प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ आबादी का मन मोहने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में एक समान विकास के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियों युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को लक्ष्य बनाकर काम करने जा रही है। इसके लिए अब प्रदेश की मोहन सरकार पूरी तरह मिशन मोड में आ गई है। सरकार हर कार्य मिशन बनाकर संपन्न करेंगी। इसी के तहत अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियों और केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण से प्रेरणा लेते हुए, मप्र सरकार ने युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों को लक्षित करते हुए 4 नए मिशन शुरू करने का फैसला किया है।

1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण, नारी सशक्तिकरण और किसान कल्याण मिशन नाम से नए मिशन शुरू किए जाएंगे। जिसमें गरीब, युवा, महिला और किसानों को प्राथमिकता देने के लिए योजना बनाई जाएगी। इसे लेकर सितंबर में मंत्री और अधिकारियों की बैठक होगी। अक्टूबर और नवंबर में कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने टारगेट भी दे दिया है। मप्र की स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री 4 जातियों को लेकर बड़े ऐलान करेंगे। लॉन्ग टर्म राहत देने के लिए मोहन सरकार योजनाओं को लागू करेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए देश में चार जातियां बताई थीं। उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ चार जातियां-गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं। मैं इन चारों जातियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा हूं। अब मप्र सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी का अनुसरण करते हुए इन चार जातियों के सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में काम करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार मप्र के स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर से चार मिशन शुरू करेगी। इनमें युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन शामिल हैं।

गरीब, युवा, महिला और किसानों को प्राथमिकता देने के लिए बनाए जा रहे मिशन को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रियों और अधिकारियों को चारों मिशनों की जानकारी देते हुए इसकी रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीएम सचिवालय ने इस सिलसिले में मंथन कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी शुरू कर दी है। मंथन कार्यक्रम सितंबर में भोपाल में आयोजित होगा। इसमें सभी मंत्री, अधिकारी और विषय विशेषज्ञ चार मिशनों की रूपरेखा तैयार करने को लेकर विचार-विमर्श करेंगे। कार्यशाला में मिशनों के क्रियान्वयन की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सीएम सचिवालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सरकार इन चार वर्गों के सशक्तिकरण के लिए ऐसी योजना बनाना चाहती है, जिससे उन्हें न सिर्फ फौरी तौर पर लाभ मिले, बल्कि इसका फायदा इन वर्गों को लॉन्ग टर्म (दीर्घकाल) में मिले। यही वजह है कि एक-एक पहलू का अध्ययन कर योजना तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में एक नवंबर में चार मिशन शुरू करने की घोषणा की थी। गरीब, युवा, महिला और किसानों को प्राथमिकता देने के लिए बनाए जा रहे मिशन में सरकार का फोकस चारों वर्गों के विकास और कल्याण पर फोकस रहेगा। युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्य योजना तैयार कर

शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का टारगेट

मप्र ने पिछले वर्षों में प्रगति और विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। समृद्ध, साक्षर, स्वस्थ और खुशहाल मप्र के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के लिए शुरू की गई विकास यात्रा निरंतरता जारी रहेगी। राज्य सरकार युवा, महिला, गरीब और किसान भाइयों के विकास और कल्याण के लिए मिशन मोड में कार्य करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में नवीन औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और निवेश को बढ़ाने के लिए रीजनल इन्वेस्ट समिट का श्रृंखलाबद्ध आयोजन किया जा रहा है। मप्र की खूबियों और यहां दी जा रही सुविधाओं से निवेशक आकर्षित हो रहे है। प्रदेश के बाहर के नामी उद्योगपतियों ने राज्य सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने में रूचि दिखाई है। प्रदेश में आने वाले निवेश और उद्योगों से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिससे वे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। युवाओं का संकल्प, मेहनत और सोच ही देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। प्रदेश में शुरू होने वाला युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प है। समय की मांग के अनुसार युवाओं को एआई, मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 485 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन में सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। किसानों को राहत प्रदान करने के साथ एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चार जातियां विपक्ष के जातिगत फॉर्मूले पर भारी पड़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक ने विपक्षी दलों की जातिगत राजनीति को तार-तार करके रख दिया है। लोगों को जातियों में बांटकर राज करने के कांग्रेसी मंत्र पर प्रधानमंत्री मोदी के महामंत्र ने ऐसा करारा प्रहार किया कि पूरा विपक्ष लहूलुहान हो गया। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में विकास का ऐसा मॉडल बनाने का निर्णय लिया है जिससे प्रदेश की पूरी आबादी का एक समान विकास हो सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एक समान विकास का जो फॉर्मूला बनाया है, उसके तहत प्रदेश सरकार अब प्रधानमंत्री की चार जातियों पर फोकस करते हुए मिशन मोड में काम करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर की। मुख्यमंत्री के अनुसार, मप्र सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन- युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी सशक्तिकरण मिशन मप्र के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास में 4 वर्गों- युवा, महिला, किसान और गरीब को आधार स्तंभ के रूप में परिभाषित किया है। मप्र सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर चार मिशन, युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन बनाकर काम करने जा रही है। मप्र के स्थापना दिवस आगामी 1 नवंबर से ये 4 मिशन अपना काम शुरू करेंगे। युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्ययोजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना महिला स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा शक्ति मिशन में शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता, नेतृत्व विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास की कार्ययोजना तैयार कर मिशन मोड में कार्य किया जाएगा। गरीब कल्याण मिशन में स्वरोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य करेगा। नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत बालिका शिक्षा, लाड़ली, लक्ष्मी योजना, लाड़ली बहना योजना, लखपति दीदी योजना, महिला स्वसहायता समूहों के सशक्तिकरण आदि कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएंगे। किसान कल्याण मिशन में सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसान कल्याण मिशन के अंतर्गत सरकार कृषि एवं उद्यानिकी को लाभ का व्यवसाय बनाने की दिशा में कार्य करेगी। किसानों को राहत एवं कृषि की पैदावार बढ़ाने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। युवा शक्ति मिशन युवाओं के भविष्य को उज्ज्वल और सशक्त बनाने का संकल्प है। हर गरीब और कमजोर व्यक्ति को समृद्धि और सुरक्षा की ओर ले जाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई मशीन लर्निंग और कोडिंग जैसी उभरती तकनीकों की भी शिक्षा प्राप्त करनी है। इसके लिए हमने 485 करोड़ रुपए का निवेश किया है। प्रदेश के 55 जिलों के महाविद्यालयों को एक-एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया है। 35 नए व्यावसायिक विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया है। शासकीय नौकरी के 11 हजार से अधिक नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। राज्य में 10 हजार करोड़ रुपए की लागत से 60 से अधिक नई उद्योग इकाइयों की स्थापना की जा रही है, जिनसे 17 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने विकास का पूरा खाका तैयार कर लिया है।

● श्याम सिंह सिकरवार

विकास का रोडमैप पर काम

मुख्यमंत्री की मंशा है कि मप्र में विकास के कार्य निरंतर चलते रहें। हर जिले में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया जाए। जिले के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रवार भी विकास कार्यों का विभाजन कर लिया जाए। विधायक, मंत्री आगामी चार-पांच वर्षों के लिए यह रोडमैप तैयार करें और कलेक्टर इन्हें सहयोग करें। इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। उन्होंने अफसरों से कहा है कि विकास कार्यों को प्राथमिकता निर्धारित कर पूरा करने की योजना भी बनाई जाए। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं को पात्रतानुसार मिले। कोई भी हितग्राही जनहितैषी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनप्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर कार्य करें। उन्होंने कहा है कि अधिकारी, जनप्रतिनिधि सरकार के अंग हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के आपसी समन्वय में किसी भी प्रकार की दूरी न रहे। आदर्श विधानसभाएं बनाने के लिए जरूरी विकास कार्य और उपाएं सुनिश्चित किए जाएं। सांसद और विधायक आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाएं कि वे अपने कार्यालय से ही व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक जिला एक उत्पाद की मार्केटिंग हो। रोजगारपरख कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों की बेहतर भूमिका रहे। जल गंगा संवर्धन अभियान और पौधरोपण अभियान बड़े पैमाने पर चलता रहे। पौधरोपण अभियान के तहत अच्छे छायादार और फलदार पौधे लगाए जाएं।

फर्जी रजिस्ट्री घोटाला

50 से अधिक फर्जी रजिस्ट्रियां मिलीं

एसटीएफ ने एक साथ गिरोह के सभी 9 सदस्यों के ठिकानों में छापा मारा तो 50 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्री, पैन और आधार कार्ड, कम्प्यूटर, फोटो कॉपी मशीन, मोबाइल और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले। एसटीएफ के मुताबिक, ये लोग एक साथ फर्जी रजिस्ट्रियां तैयार कर रख लेते थे, फिर जरूरत के हिसाब से शहर के अलग-अलग बैंकों में लोन के लिए फाइल लगा देते थे। एसटीएफ को उम्मीद है कि गिरोह में और भी सदस्य हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।

जबलपुर में पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके सदस्य फर्जी रजिस्ट्री लगाकर बैंक से लोन लेते थे। बड़ी बात तो यह है कि इस गैंग को बैंक के अधिकारी ही चला रहे थे। गैंग बॉलीवुड मूवी स्पेशल 26 की तर्ज पर काम कर रहा था। जिस तरह फिल्म स्पेशल-26 के किरदार सिर्फ वारदात के वक्त ही इकट्ठा होते थे, बाकी समय अपनी नौकरी-बिजनेस में बिजी रहते थे, उसी तरह जबलपुर में पकड़े गए जालसाजों में से कोई बैंक में काम करता है, तो कोई प्राइवेट नौकरी। मप्र एसटीएफ ने अब तक इस गैंग के 9 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है इसलिए इस गैंग को स्पेशल-9 कहा जा रहा है। आरोपियों के पास से करोड़ों रुपए की फर्जी रजिस्ट्री सहित आधार कार्ड, पैन कार्ड और सील बरामद की गई हैं।

एसटीएफ का कहना है कि गैंग ने अभी तक लोन के नाम पर करीब 6 करोड़ रुपए शहर के अलग-अलग बैंकों से ठगे हैं। गिरोह के सदस्यों ने इतनी चालाकी से काम किया कि न तो बैंक अधिकारियों को जानकारी लगी और न ही उस व्यक्ति को, जिसके नाम की फर्जी रजिस्ट्री लगाकर लोन लिया गया। एसटीएफ के अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह के तार न सिर्फ मप्र बल्कि अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं। 22 अगस्त को सभी 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जबलपुर के गढ़ा फाटक इलाके में रहने वाले सुमित काले ने 10 अगस्त को एसटीएफ को लिखित शिकायत की। इसमें बताया कि वह एक बिल्डर की कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। बिल्डर का सूखा पाटन में प्लॉटिंग का काम है। अधिकतर प्लॉट बिक चुके हैं, इसलिए साइट बंद कर दी गई है। बिके प्लॉट में से कुछ को बिना जानकारी के रिसेल किया गया है। सुमित ने कहा, मेरे फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड बनाकर हिंदुजा बैंक में किसी और को सुमित काले बनाकर खड़ा किया गया। एक प्लॉट की रजिस्ट्री जमाकर लाखों रुपए का लोन निकाला गया। सुमित ने एसटीएफ को बताया कि कुछ माह पहले एक बैंक कर्मचारी को लोन के लिए रजिस्ट्री की फोटो कॉपी दी थी, लेकिन लोन नहीं लिया था। एसटीएफ बैंक पहुंची। लोन के लिए जमा रजिस्ट्री को जब्त कर रजिस्ट्री कार्यालय से सत्यापन करवाया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जमीन की रजिस्ट्री तो सुमित काले की थी, लेकिन उस पर फोटो विकास तिवारी की लगी थी। एसटीएफ को ये समझने में देर नहीं लगी कि ये काम फर्जी रजिस्ट्री के नाम पर बैंक से लोन लेने वाला गिरोह का है। सबसे पहले विकास तिवारी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में विकास ने अपने गिरोह के सभी सदस्यों के नामों का खुलासा कर दिया। उसने बताया कि गैंग को एक्सिस बैंक का प्लान मैनेजर अनुभव दुबे और संदीप चौबे लीड करते थे। दोनों ही बैंक के अधिकारी हैं, इसलिए ये अच्छे से जानते थे कि कैसे दस्तावेज लगाकर लोन लिया जा सकता है। गिरोह का सदस्य प्रवीण पांडे अकाउंट होल्डर बनता था। कभी शेख सलीम, तो कभी प्रवीण काले बनकर शहर के एक नहीं बल्कि कई बैंकों में खाते खुलवाए और फिर फर्जी रजिस्ट्री जमा कर लोन लिया। एक्सिस बैंक में अनुभव दुबे और हिंदुजा बैंक में संदीप चौबे की मदद से प्रवीण ने अलग-अलग नाम की फर्जी रजिस्ट्री लगाकर लोन लिए। गिरोह का एक और सदस्य पुनीत उर्फ राहुल पांडे माढोताल स्थित जना बैंक का कर्मचारी था। इसकी मदद से प्रवीण ने जना बैंक में 6 फर्जी रजिस्ट्री लगाकर करीब 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। प्रवीण ने एक्सिस बैंक, जना बैंक, हिंदुजा बैंक, इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस से भी अच्छा खासा लोन लिया था। एसटीएफ की जांच में पुष्टि हुई है कि गैंग ने अभी तक करीब 6 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है। अनुभव दुबे और संदीप चौबे इस गैंग के लीडर थे। बैंक अधिकारी होने की वजह से दोनों जानते थे कि राष्ट्रीयकृत बैंक में केवाईसी कराने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए उन बैंकों को चुना जाए जहां ई-केवाईसी नहीं होती है। गैंग के सदस्यों ने शुरुआत में सरकारी बैंकों को टारगेट किया लेकिन जब सफलता नहीं मिली और सर्च के दौरान लोन एप्लिकेशन रिजेक्ट हो गई तो प्राइवेट बैंकों को निशाना बनाना शुरू किया। एसटीएफ के मुताबिक, गैंग के सदस्य अभी तक एक्सिस बैंक से करीब 50 लाख, हिंदुजा बैंक से करीब 3 करोड़, जना बैंक से करीब 1 करोड़ और ग्रामीण सहकारी बैंक से करीब 50 लाख से फर्जी रजिस्ट्री लगाकर लोन ले चुके हैं।

गैंग में किसका क्या काम है, कितना कठिन है, उस हिसाब से पैसा बांटा जाता था। प्रवीण पांडे अकाउंट होल्डर था। लोन के लिए फर्जी रजिस्ट्री लगाने के बाद जो पैसा खाते में आता था, वह प्रवीण पांडे के नाम पर आता था। खाते में पैसा आने के बाद गिरोह के सभी 9 सदस्य इकट्ठा होते, फिर अनुभव, संदीप और विकास के इशारे पर रुपए का बंटवारा होता था। जिसकी जितनी ज्यादा मेहनत, उसे उतना ही बड़ा हिस्सा मिलता था। विकास तिवारी लोगों से लोन के लिए संपर्क करता था और उनकी रजिस्ट्री की फोटो कॉपी ले लिया करता था। इसके बाद अनुभव, पुनीत और संदीप रजिस्ट्री को चेक करने के बाद लकी उर्फ लखन प्रजापति की दुकान में लेकर जाते जहां पर फर्जी रजिस्ट्री तैयार की जाती थी। रजिस्ट्री में लगाए गए स्टाम्प भी कलर फोटो कॉपी मशीन से ऐसे तैयार किए जाते थे कि असली लगें। फर्जी रजिस्ट्री तैयार होने के बाद उसमें उप पंजीयक के सील-साइन अनवर लगाता था। अनवर 15 साल से जबलपुर कलेक्ट्रेट में काम कर रहा है। वह अच्छे से जानता है कि रजिस्ट्री में कितने का स्टाम्प लगता है और किस पेज में कहां सील लगाई जाती है। अनवर ने नकली सील भी तैयार कर रखी थीं। फर्जी रजिस्ट्री तैयार होने के बाद प्रवीण का काम होता था कि वह अलग-अलग नामों से बैंक में जाकर लोन के लिए आवेदन दे। मोहम्मद अनीस का काम होता था कि सभी लोगों से फर्जी रजिस्ट्री इकट्ठा कर अपने पास रखें और समय आने पर उस रजिस्ट्री को प्रवीण पांडे को दे।

● **जितेंद्र तिवारी**

मप्र के नेताओं का हक 'बाहरियों' को

बिना चुनाव लड़े ही जीत गए जॉर्ज कुरियन

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मप्र से राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, लेकिन गुना संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद उन्होंने ऊपरी सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। भाजपा ने राज्यसभा की रिक्त हुई सीट के लिए केरल से नाता रखने वाले केंद्रीय मंत्री कुरियन को उम्मीदवार बनाया था। नाम वापसी की तारीख और समय निकलने के बाद केंद्रीय मंत्री कुरियन के मुकाबले में कोई नहीं था। लिहाजा वह निर्विरोध निर्वाचित हो गए। मप्र में राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 7 पर भाजपा और 3 कांग्रेस के खाते में है। अब कुरियन के निर्वाचित होने से राज्यसभा की 8 सीटों पर भाजपा का कब्जा हो गया है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की स्थिति पर गौर करें तो भाजपा के उमेश नाथ महाराज, बंशीलाल गुर्जर, एल मुरुगन, माया नारोलिया, कविता पाटीदार, सुमित्रा बाल्मीकि और सुमेर सिंह सोलंकी हैं। वहीं कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा और अशोक सिंह हैं।

मप्र भाजपा का ऐसा गढ़ है, जहां से पार्टी राज्यसभा के लिए दूसरे राज्यों के नेता को बेझिझक टिकट दे देती है। इसी कड़ी में मप्र में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव के लिए भाजपा ने केरल के नेता जॉर्ज कुरियन को प्रत्याशी बनाया। कुरियन मोदी कैबिनेट में मत्स्य पालन, पशुपालन-डेयरी विभाग के राज्य मंत्री हैं। दरअसल, इस एक सीट के लिए मप्र के कई नेता दावे कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि मप्र के भाजपा नेताओं की प्रतिस्पर्धा में कुरियन की लॉटरी लगी है। कुरियन दूसरे राज्य के पहले नेता नहीं हैं जिनको मप्र से राज्यसभा भेजा जा रहा है। मप्र से पहले भी बाहरी राज्यों के नेताओं को यहां के नेताओं का हक मारकर राज्यसभा भेजा जाता रहा है।

मप्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के बाद खाली हुई राज्यसभा की सीट पर अप्रैल 2026 तक का कार्यकाल बचा हुआ है। इस सीट पर राज्यसभा के लिए कई नेताओं के नाम की चर्चा थी, उनमें गुना के पूर्व सांसद डॉ. केपी सिंह यादव भी थे। वहीं, पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी, कांतदेव सिंह और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल के नामों की चर्चा थी। पवैया और नरोत्तम मिश्रा दो साल के लिए राज्यसभा जाने के लिए राजी नहीं थे। सुरेश पचौरी ने भी इस दौड़ से खुद को अलग कर लिया था। सूत्र बताते हैं कि केपी यादव के लिए संगठन में सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में मप्र भाजपा ने फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया, और केरल के खाते में मप्र की राज्यसभा सीट चली गई। जॉर्ज कुरियन का चयन इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि वे मप्र से राज्यसभा में जाने वाले दूसरे बाहरी नेता हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तमिलनाडु के एल. मुरुगन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया था। जॉर्ज कुरियन को निर्विरोध चुन लिया गया है। उनका कार्यकाल दो वर्ष का रहेगा, क्योंकि वे सिंधिया के राज्यसभा के बचे कार्यकाल को ही पूरा करेंगे। सिंधिया अब लोकसभा सदस्य हैं।

पहले भी पार्टी करीब एक दर्जन से अधिक बाहरी नेताओं को मप्र से टिकट दे चुकी है। राज्यसभा के लिए प्रदेश से बाहर के नेता को भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने की बात पहली बार नहीं हो रही है। इसके पहले भी भाजपा अपने कई वरिष्ठ नेताओं को जो दूसरे राज्य से नाता रखते थे, उन्हें मप्र से राज्यसभा भेज चुकी है। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी से लेकर अब जार्ज कुरियन तक के नाम शामिल हो गए हैं। मप्र को भाजपा की नर्सरी कहा जाता है। पार्टी के देशभर के जो वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्रों से चुनाव नहीं जीत पाते या फिर उस प्रदेश में पार्टी इस स्थिति में नहीं रहती कि वह अपने प्रत्याशी को राज्यसभा के लिए जीत दिला सके। ऐसे में पार्टी उन्हें मप्र से राज्यसभा भेज देती है। इसका उदाहरण प्रदेश से भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं का राज्यसभा का टिकट देकर उच्च सदन में भेजने का रिकार्ड है। जहां पार्टी ने दो बार लालकृष्ण आडवाणी को यहां से राज्यसभा भेजा था। इसके अलावा प्रदेश के बाहर के वह नेता जो मप्र से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए उसमें ओ राजगोपाल, भाई महावीर, सुषमा स्वराज, सु थिरूनावक्कारासर, नजमा हेपतुल्ला, एल गणेशन, एमजे अकबर, सिकंदर बख्त, प्रकाश जावडेकर, चंदन मित्रा, एम मुरुगन के बाद अब जार्ज कुरियन शामिल हैं। भाजपा ने एक बार फिर बाहरी नेता को मप्र से राज्यसभा उम्मीदवार बनाने से केपी यादव को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, गुना से पूर्व सांसद यादव प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 के चुनाव में सवा लाख वोटों से हराया था। इसके बाद 2020 में सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने उनको राज्यसभा सदस्य बनाकर केंद्र में मंत्री बनाया था। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंधिया को केपी यादव का टिकट काटकर प्रत्याशी बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान 26 अप्रैल 2024 को गुना में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी केपी यादव की प्रशंसा करते हुए कहा था कि उनकी चिंता भाजपा करेगी और उन्हें आगे बढ़ाने की सभी जिम्मेदारियां पार्टी संभालेगी। इस बयान के बाद ऐसा लगने लगा था कि राज्यसभा की खाली सीट पर केपी यादव को मौका मिलेगा, लेकिन भाजपा ने जॉर्ज कुरियन को उम्मीदवार बनाकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया। राज्यसभा से उम्मीदवार के ऐलान के बाद अब चर्चा है कि केपी यादव का क्या होगा? सियासी जानकारों का कहना है कि अब यादव को पांच साल लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा या दूसरा विकल्प उनको निगम-मंडल या संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। वहीं, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा जा रहा है कि वे चुनाव होने तक प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की रेस में बने हुए हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खजुराहो में वीडी शर्मा के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए जनता से कहा था कि आप एक सांसद नहीं चुन रहे हैं, आप एक बड़ा नेता चुन रहे हैं। इसके बाद फरवरी 2020 में वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। वहीं, केपी यादव के मामले में शाह का आश्वासन फिलहाल खाली जाता दिख रहा है।

● **लोकेश शर्मा**

नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 2 साल के बजाय 3 साल की अवधि तय कर दी गई है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो तिहाई के बजाय तीन चौथाई बहुमत की जरूरत होगी। इसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया जा सकेगा। कैबिनेट ने पूर्व में लाए गए अध्यादेश को पलट दिया है। नगरपालिका अधिनियम की धारा 43 (क) में संशोधन करके यह फैसला लिया गया है।

बगावत रोकने नया नियम!

मप्र के नगरीय निकायों में चुने जाने वाले नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। डॉ. मोहन यादव सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 3 साल के पहले नहीं लाया जा सकता। पिछले दिनों बानमोर नगरीय निकाय की घटना के बाद राज्य सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 43 (क) में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इसके जरिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बड़ी राहत दी गई है। इस नए नियम के तहत अब नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाना आसान नहीं होगा। अब अविश्वास प्रस्ताव 3 साल के पहले नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए तीन-चौथाई पार्षदों की सहमति अनिवार्य होगी। अभी तक किसी नगर पालिका के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए दो-तिहाई पार्षदों की सहमति जरूरी होती थी।

नए संशोधन विधेयक में 3 साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अभी तक यह समयसीमा 2 साल की थी। जब इसकी पड़ताल की गई तो पता चला कि इसकी वजह विपक्ष या कांग्रेस के नेता नहीं बल्कि भाजपा के ही नेता हैं, जो अपने पसंद के अध्यक्षों को कुर्सी पर बैठाना चाहते हैं। इसके जरिए वे शहर सरकार पर कब्जा जमाना चाहते हैं। ये नेता अध्यक्षों के दो साल के कार्यकाल पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें कुर्सी से हटाया जा सके। सरकार को इनके मंसूबों की भनक लग गई और कैबिनेट बैठक में आनन-फानन में प्रस्ताव लाकर इन मंसूबों पर पानी फेरा गया है। अंदरूनी सूत्रों से सरकार को ये भी पता चला कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए पार्षदों का समर्थन हासिल करने खरीद-फरोख्त की भी तैयारी की जा रही थी। ऐसा होता तो प्रदेश भर में पार्टी में खलबली मचना तय था।

हालांकि, कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव के आने से पहले कई नगरीय निकायों में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जा चुका है। अब सरकार इन प्रस्तावों को मैनेज करने में जुटी है। खास बात ये है कि सात में से पांच निकायों में महिला अध्यक्ष कुर्सी पर बैठी हैं और उनके पतियों के हाथ में निकाय की बागडोर है। केवलारी नगर परिषद् की अध्यक्ष सुनीता बघेल केवल एक वोट से अध्यक्ष का चुनाव जीती थीं। अब भाजपा के 9 पार्षदों ने ही अपने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। उनका आरोप है कि अध्यक्ष के पति देवी सिंह बघेल नगर परिषद में विधायक प्रतिनिधि बन गए हैं। यहां अध्यक्ष नहीं, बल्कि उनके पति देवी सिंह सभी फैसले लेते हैं। परिषद के हर काम में उनका दखल रहता है। उनकी अनुमति के बिना पार्षदों के कोई काम नहीं होते हैं। पार्षदों ने जो अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उसमें अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि वार्डों में काम नहीं हो रहे हैं, वे मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। कलेक्टर ने 6 सितंबर को पार्षदों से चर्चा के लिए केवलारी एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

चाचौड़ा नगर परिषद की अध्यक्ष सुनीता नाटानी पर आरोप है कि वे अधिकांश समय इंदौर में रहती हैं। ऐसे में परिषद के काम उनके पति प्रदीप नाटानी देखते हैं। उनसे विकास कार्यों की बात की जाती है तो वे बार-बार अपमानित करती हैं। मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना में 9 करोड़ के घोटाले का भी आरोप है। यही वजह है कि परिषद उपाध्यक्ष रश्मि शर्मा सहित 13

दमोह में भाजपा पार्षद लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव

दमोह नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस की मंजू राय के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पेश हो गया है। भाजपा के 20 पार्षदों ने कलेक्टर को शपथ पत्र देकर अध्यक्ष को हटाने की मांग की है। इनकी अगुवाई अध्यक्ष का चुनाव हार चुके विक्रांत गुप्ता कर रहे हैं। वे कांग्रेस की मंजू राय से 9 वोट से हार गए थे। दरअसल, नगर पालिका के 39 वार्डों में से भाजपा ने 14, कांग्रेस ने 17, सिद्धार्थ मलैया द्वारा बनाई पार्टी टीएसएम ने 5, बसपा ने एक और दो वार्डों में निर्दलीय जीते थे। बाद में टीएसएम के 5 और दोनों निर्दलीय भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में भाजपा पार्षदों की संख्या बढ़कर 21 हो गई। सूत्रों का कहना है कि भाजपा ने कांग्रेस के कुछ पार्षदों को क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार कर लिया है। फिलहाल इनके नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए 21 अगस्त को 8 पार्षदों ने हस्ताक्षर कर पत्र कलेक्टर को सौंपा था। इसके बाद 12 पार्षदों ने 22 अगस्त को पत्र दिया। इधर, कलेक्टर सुधीर कोचर ने सभी पार्षदों से शपथ पत्र लेने के बाद नियमानुसार प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है।

पार्षदों ने हस्ताक्षर कर अध्यक्ष सुनीता को हटाने की मांग कर दी। भाजपा के 6, कांग्रेस के 2 और 5 निर्दलीय पार्षदों ने तीन जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव नगर परिषद सीएमओ और कलेक्टर को सौंपा है। सूत्रों का कहना है कि अध्यक्ष का एक साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद से ही पार्षद विरोध में उतर आए थे। कुछ पार्षदों ने अध्यक्ष की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए प्रदर्शन भी किया था। सुनीता को क्षेत्रीय विधायक प्रियंका पेंची का करीबी कहा जाता है, इसलिए संगठन स्तर पर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है।

पता चला है कि जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार ने हाल ही में नाराज पार्षदों की बैठक लेकर अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने की कोशिश की है। नपा अध्यक्ष के चुनाव में गीता जाटव को 9 वोट, जबकि कांग्रेस के कमल सिंह राजे को 6 वोट मिले थे। जाटव भले ही अध्यक्ष बन गईं, लेकिन भाजपा को डर था कि निर्दलीय पार्षदों ने पाला बदल लिया तो अध्यक्ष पद चला जाएगा। भाजपा के न्यू जॉइनिंग अभियान के दौरान कांग्रेस नेता राकेश मावई के साथ 4 पार्षदों ने भी भाजपा की सदस्य ले ली। ऐसे में भाजपा ने खतरे को टाल दिया। सूत्रों का कहना है कि उपाध्यक्ष राजवीर यादव की अध्यक्ष गीता जाटव से पटरी नहीं बैठ रही है। जाटव को पूर्व विधायक रघुराज कंसाना का समर्थक माना जाता है। डेढ़ महीने पहले उपाध्यक्ष यादव का परिषद कार्यालय में अध्यक्ष से विवाद हो गया था। इसे लेकर अध्यक्ष के साथ परिषद की तरफ से थाने में यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद यादव ने भाजपा के 9, कांग्रेस के एक पार्षद को अपने पाले में लाकर 10 पार्षदों के समर्थन होने का पत्र कलेक्टर को सौंप दिया। बताया जाता है कि भाजपा के जिस गुट ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, वे राकेश मावई के समर्थक हैं। 8 अगस्त को ही अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है।

देवरी नगर पालिका के 12 पार्षदों ने अध्यक्ष नेहा जैन के खिलाफ 16 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव कलेक्टर को सौंपा है। यहां 15 पार्षदों में से 13 भाजपा और 2 कांग्रेस के पार्षद हैं। अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए उन्हें 7 पार्षदों का समर्थन चाहिए। चुनाव के बाद से ही पार्षद दो धड़ों में बंट गए थे। अध्यक्ष पद के लिए नेहा के खिलाफ भाजपा की ही आरती जैन मैदान में उतर गई थीं। उन्हें 7 पार्षदों का समर्थन मिल गया था, लेकिन कांग्रेस पार्षद नईम खान ने नेहा जैन को समर्थन देकर बाजी पलट दी। उस समय आरोप लगा कि नेहा जैन ने खरीद-फरोख्त के जरिए अध्यक्ष पद हासिल किया। नेहा जैन के पति अलकेश को पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल का करीबी माना जाता है। वहीं, आरती जैन के पति बबलू को देवरी विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया का समर्थन हासिल है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बबलू के समर्थक 6 पार्षदों ने नपा अध्यक्ष के खिलाफ धरना दिया था। उन्होंने अध्यक्ष पर वार्डों में विकास कार्य न करवाने के आरोप लगाए थे। एक हफ्ते तक चले धरने को कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए ब्रज बिहारी पटेरिया ने खत्म करवाया था।

ब्रज बिहारी देवरी सीट से विधानसभा चुनाव जीते तो नगर पालिका का सियासी समीकरण भी बदल गया। विधायक बनने के बाद पटेरिया ने आरती के पति बबलू जैन को नगर पालिका में विधायक प्रतिनिधि बना दिया। इससे नगर पालिका में पटेरिया का दखल बढ़ गया। इस दौरान नेहा जैन को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग तेज हो गई। दो साल का कार्यकाल पूरा होते ही 16 अगस्त को 12 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर को पत्र सौंप दिया। गत दिनों स्थानीय नेताओं के साथ पार्षदों ने मुख्यमंत्री से भोपाल में मुलाकात भी की थी। पार्षदों ने 20 अगस्त को कलेक्टर से मुलाकात कर जल्द से जल्द परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है लेकिन अब यह मामला लंबित है।

नर्मदापुरम नगर पालिका अध्यक्ष का पद ओबीसी महिला के लिए रिजर्व है। भाजपा की नीतू यादव 29 वोट लेकर अध्यक्ष बनी थीं, लेकिन 2 साल का कार्यकाल (11 अगस्त 2024) पूरा होने से पहले ही उन्हें हटाने की मुहिम शुरू हो गई। नीतू के पति महेंद्र यादव को मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का करीबी माना जाता है। अध्यक्ष को राज्यसभा सांसद माया नरोलिया का भी समर्थन है। बावजूद इसके उन्हें पद से हटाने के लिए 21 पार्षदों ने न सिर्फ मोर्चा खोला, बल्कि अविश्वास प्रस्ताव पर दस्तखत भी किए। नगर पालिका का विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए 8 अगस्त को कलेक्टर सोनिया मीणा को पत्र भी सौंपा है। एक स्थानीय भाजपा नेता के मुताबिक, नगर परिषद में मंत्री उदय प्रताप सिंह के अलावा सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह और होशंगाबाद के पूर्व विधायक गिरिजाशंकर शर्मा के समर्थक पार्षद भी हैं। अब सिंह और शर्मा के समर्थक पार्षद नीतू यादव के खिलाफ लामबंद हुए हैं। इन पार्षदों की 17 अगस्त को तवा डेम रिसॉर्ट में एक बैठक भी हुई थी। पार्षदों का आरोप है कि उनकी अनदेखी हो रही है और अध्यक्ष विकास कार्यों में रुकावट बन रही हैं। इन पार्षदों ने 21 अगस्त को कलेक्टर से मुलाकात कर नगर पालिका का विशेष सम्मेलन बुलाने का दोबारा अनुरोध किया है। बताया जा रहा है कि संगठन स्तर पर पार्षदों को मनाने की जिम्मेदारी अब प्रभारी मंत्री राकेश सिंह को सौंपी गई है।

● **सुनील सिंह**

नियम में संशोधन का क्या असर

नगरीय निकाय अधिनियम के जानकार संजय अग्रवाल कहते हैं कि सरकार ने 20 अगस्त को कैबिनेट में संशोधन का प्रस्ताव पास कर दिया है, मगर अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। ऐसी नगर पालिकाएं या परिषद, जहां अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो गया है और उनके खिलाफ 20 अगस्त से पहले अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है तो वहां नया नोटिफिकेशन लागू नहीं होगा। मगर ये देखना होगा कि सरकार संशोधन का जो नोटिफिकेशन जारी करेगी, उसकी भाषा क्या होगी? ऐसा तो नहीं है कि यह संशोधन भूलक्षित प्रभाव यानी अध्यक्ष का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने की तारीख से लागू किया जा रहा हो?

बुलडोजर का कानून

छतरपुर में थाने पर पथराव के बाद शुरू हुए बुलडोजर एक्शन की चर्चा पूरे देश में है। इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर संविधान की शपथ लेने वाली सरकारों का ये कैसा न्याय है? दूसरी तरफ भाजपा नेता ये कहकर बचाव कर रहे हैं कि कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। मप्र में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत 90 के दशक में हुई थी। उस समय बुलडोजर विकास का प्रतीक था। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर ने पटवा सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था। मकसद राजधानी भोपाल की सड़कों को चौड़ा करना था। इसके बाद उन्हें बुलडोजर मंत्री कहा जाने लगा।

साल 2017 में योगी आदित्यनाथ उप्र के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने बुलडोजर को कानून व्यवस्था से जोड़ दिया। उप्र में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। इसके बाद उप्र के इस मॉडल को 2018 में मप्र की कमलनाथ सरकार ने अपनाया। 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया। जब मप्र में शिवराज सरकार की वापसी हुई तो बुलडोजर की स्पीड बढ़ गई। शिवराज ने कुछ ऐसे बयान दिए जिससे वे योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा की तरह बुलडोजर मामा की छवि गढ़ते दिखे। मप्र में बुलडोजर से मकान और दुकानों को ढहाने की सबसे बड़ी कार्रवाई 10 अप्रैल 2022 को हुई थी। दरअसल, खरगोन में रामनवमीं के जुलूस पर पथराव हुआ था उसके बाद शहर में दंगे भड़क गए। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाते हुए दंगाईयों को गिरफ्तार किया। एक दिन बाद प्रशासन ने तालाब चौक स्थित मस्जिद की सभी दुकानों को अवैध बताकर तोड़ दिया। ये दावा किया गया कि इसी मस्जिद से दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी। हालांकि, जिनकी दुकानें तोड़ी गईं, उनका दावा है कि उनका दंगे से कोई लेना-देना नहीं था। इन्हीं में शामिल जाहिद अली कहते हैं कि मेरा दंगे से कोई लेना-देना नहीं था। इसके बाद भी मेरे मकान और दुकान को तोड़ दिया। मुझे न तो मुआवजा मिला और न ही इंसाफ। खरगोन के ही सामाजिक कार्यकर्ता अल्ताफ आजाद इस दर्द को अपनी एक शायरी से व्यक्त करते हैं। कहते हैं- लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में...।

14 जून 2024 को मंडला में नैनपुर के भैंसवाही गांव में 11 घरों से 150 से ज्यादा गौवंश के अवशेष मिले थे। अगले दिन पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी 11 आरोपियों के अवैध घरों को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। मौके पर खुद तत्कालीन एसपी रजत सकलेचा, एएसपी समेत 8 चौकियों का पुलिस बल तैनात था। प्रशासन की ओर से बताया गया कि आरोपियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तरीके से गौवंश के अवशेष जैसे हड्डी, चर्बी आदि जमा कर रखे थे। पुलिस ने एक आरोपी वाहिद कुरैशी को उसी दिन और बाकियों को बाद में गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी की गई थी। गौवंश की तस्करी के चलते स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी थी। आज भी आरोपियों के मकान वहां नहीं बन पाए। प्रशासन ने सरकारी जमीन का हवाला देते हुए सभी को वहां से बेदखल कर दिया। आरोपी परिवार के लोग वहां से पलायन कर दूसरी जगह जा चुके हैं। 4 जुलाई 2023 को सीधी के कुबरी गांव का रहने वाला भाजपा नेता प्रवेश शुक्ला का एक वीडियो वायरल हुआ था। जिसमें वह उसी गांव के आदिवासी युवक दशमत पर पेशाब करते हुए नजर आया था। विधानसभा चुनाव से पहले हुए वायरल वीडियो से प्रदेश की सियासत गर्मा गई। राजनीतिक नुकसान की आशंका देख तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद डैमेज कंट्रोल में जुटे। आरोपी को गिरफ्तार कराया। पीड़ित दशमत को सीएम हाउस बुलाकर उसके पैर धोकर सम्मानित किया। आर्थिक मदद दी। इसके बाद आरोपी प्रवेश शुक्ला के मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से ब्राह्मण समाज नाराज हो गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की पहल पर समाज के लोगों ने चंदा एकत्र कर आरोपी परिवार को मकान बनवाने के लिए दिए। प्रवेश का तोड़ा गया मकान फिर से बन चुका है। प्रवेश शुक्ला के पिता रमाकांत शुक्ला का कहना है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मैंने जबलपुर हाईकोर्ट में दो याचिका लगाई हैं। वहीं से न्याय की उम्मीद है। मैंने मकान गिराए जाने के एवज में प्रशासन से क्षतिपूर्ति मांगी है।

17 जुलाई 2023 को उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान एक बिल्डिंग से तीन लड़कों ने थूका और कुल्ला कर पानी फेंका था। सवारी में शामिल भैरवगढ़ निवासी सावन लोट ने देखा। इसका मोबाइल से वीडियो भी बनाया। ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने पर स्थानीय लोग भड़क गए। वीडियो बनाने वाले सावन लोट की शिकायत पर खाराकुआं थाने में आरोपियों के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और सद्भावना बिगाड़ने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ। 19 जुलाई को उज्जैन नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने तीनों आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। मप्र में डॉ. मोहन यादव सरकार के गठन के बाद बुलडोजर एक्शन का ये पहला मामला था। दरअसल, 5 दिसंबर 2023 को भोपाल की जनता कॉलोनी में रहने वाले भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करते हुए इसी कॉलोनी के फारुख राइन, असलम, समीर शाहरुख और बिलाल ने हाथ का पंजा काट दिया था। घटना के बाद सभी गिरफ्तार हुए और 14 दिसंबर को पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के अमले ने सभी आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। मुख्य आरोपी फारुख राइन पर एनएसए की कार्रवाई की गई।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

बुलडोजर एक्शन का गणित

सरकार का ये एक्शन कानून से ज्यादा जनभावनाओं पर आधारित है और इसके जरिए सिस्टम अपनी ताकत दिखाकर मैसेज भी दे देता है। संबंधित व्यक्ति को लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी सीधे चोट पहुंचाई गई है। छतरपुर में हाजी शहजाद अली की 20 करोड़ की हवेली हो या फिर कोई और कार्रवाई। मकान तोड़ने के पीछे प्रशासन की मंशा होती है कि ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर किया जाए। मगर इसकी चपेट में कभी-कभी ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका ऐसे मामलों से लेना-देना नहीं होता। बुलडोजर एक्शन को राजनीति अपने-अपने चश्मे से देखती है। भाजपा समर्थित नेता इसे कानून के राज के लिए जरूरी बताते हैं। जबकि दूसरा धड़ा, इस एक्शन को संविधान के खिलाफ बताता है। उनका तर्क है कि सरकार का ऐसा एक्शन न्याय व्यवस्था के खिलाफ है। प्रशासन मकान तोड़ने की कार्रवाई करता है तो दलील दी जाती है कि उस शख्स ने अवैध तरीके से निर्माण किया था।

सफेद हाथी साबित हो रहे ताप विद्युत गृह

मप्र के लगभग सभी ताप विद्युत गृह सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। यानी इन ताप विद्युत गृहों की कोई न कोई इकाई खराब होने के कारण बंद रहती है। वहीं बूढ़ी हो चुकी इकाईयों का मेंटेनेंस मंहगा पड़ रहा है। इस कारण लगभग सभी ताप विद्युत गृहों में बिजली का उत्पादन क्षमता से आधा भी नहीं हो रहा है। जबकि बिजली उत्पादन का खर्च वही पड़ रहा है। इससे सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए की चपत लग रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुल बिजली उत्पादन क्षमता 22,730 मेगावाट है। मप्र जनरेटिंक कंपनी के ताप विद्युत ग्रह से 5400 मेगावाट, मप्र जनरेटिंक कंपनी के जल विद्युत गृह से 921.58 मेगावाट, संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत गृह और अन्य से 2484.13 मेगावाट, केंद्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत गृह 5251.74 मेगावाट, दामोदर घाटी विकास निगम के ताप विद्युत गृह 3401.5 मेगावाट और नवकरणीय ऊर्जा स्रोत 5171 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। वर्तमान समय में प्रदेश में बिजली की डिमांड 14 से 15 हजार मेगावाट है। इस तरह प्रदेश में 8 से 9 हजार मेगावाट सरप्लास बिजली है।

प्रदेश बिजली के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। लेकिन प्रदेश के ताप विद्युत गृह सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से 50 फीसदी से कम बिजली उत्पादन हो रहा है। इससे बिजली कंपनी को रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की दो यूनिट पिछले कई दिनों से बंद हैं। प्रदेश के सभी ताप विद्युत गृहों की बिजली उत्पादन क्षमता 5400 मेगावॉट है। इनसे 1783 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हुआ। ग्रिड में बिजली 1667 मेगावॉट पहुंची। यानी उत्पादन 50 फीसदी से कम हो गया है। इससे पॉवर जनरेशन कंपनी को करोड़ों रुपए का घाटा हो रहा है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के ताप विद्युत गृहों से बिजली उत्पादन में बड़े पैमाने पर लापरवाही की जा रही है। बिजली उत्पादन यूनिटें आए दिन खराब हो जाती हैं। फिर इन यूनिट को सुधारने में महीनों लग जाते हैं। इससे करोड़ों रुपए का नुकसान बिजली कंपनियों को होता है। कुछ दिन पहले संजय गांधी ताप विद्युत गृह की एक यूनिट बायलर ट्यूब में खराबी आ जाने से बंद हो गई है। इससे इस यूनिट से बिजली उत्पादन ठप हो गया है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की एक और यूनिट पहले से ही बंद पड़ी है। इस तरह से अकेले संजय गांधी ताप विद्युत गृह से ही रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन कम हो गया है। इससे हर दिन कंपनी को 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसी तरह सतपुड़ा, श्री सिंगाजी और अमरकंटक ताप विद्युत गृहों से भी पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है।

अमरकंटक ताप विद्युत गृह की बिजली उत्पादन क्षमता 210 मेगावॉट है। इस यूनिट से अभी बिजली उत्पादन बंद है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 1200 मेगावॉट है। यहां बिजली का उत्पादन सिर्फ 428 मेगावॉट हो रहा है। इस विद्युत केंद्र में भी आधे से ज्यादा बिजली उत्पादन ठप है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की स्थिति ज्यादा खराब है। अधिकारियों की लापरवाही से यहां की एक यूनिट का बायलर ट्यूब पूरी तरह से जल गया है। इससे इस यूनिट को 60 दिन के लिए बंद कर दिया है। इस यूनिट को सुधरने में ही करोड़ों रुपए का ही खर्च आएगा। एक यूनिट यहां पहले से ही बंद है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह की बिजली उत्पादन क्षमता 1340 मेगावॉट है। इस ताप विद्युत केंद्र से शाम की स्थिति में बिजली उत्पादन 742 मेगावॉट हो रहा है। श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह की 660 मेगावॉट की 3 नंबर यूनिट बंद है। इससे बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। वहीं इतने ही उत्पादन क्षमता की दूसरी यूनिट से 378 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है। संजय गांधी ताप विद्युत गृह के चीफ इंजीनियर शशिकांत मालवीय का कहना है कि एक यूनिट बायलर ट्यूब फट जाने से 60 दिन के लिए बंद है। दूसरी यूनिट 7 सितंबर को चालू हो जाएगी। अभी बिजली की ज्यादा डिमांड नहीं है। इससे यूनिट बंद होने से ज्यादा दिक्कत नहीं है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह में भ्रष्टाचार भी चरम पर

मप्र के ताप विद्युत गृह भ्रष्टाचार का गढ़ भी बने हुए हैं। मप्र पावर जनरेटिंग कंपनी की श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह दोंगलिया (खंडवा) के कोल हैंडलिंग विभाग में 45 लाख रुपए के उपकरण खरीदी घोटाले के तार आला अधिकारियों से भी जुड़े हैं। इन पर कंपनी प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टा एक अधिकारी का सामान्य तरीके से तबादला कर दिया गया। मामले की जांच करने ताप गृह पहुंची जांच टीम ने बयानों और तथ्यों के आधार पर पाया कि मुख्य अभियंता (उत्पादन) और अतिरिक्त मुख्य अभियंता आरके साहू के संज्ञान में मामला 3 जुलाई 2024 को प्रकरण आ चुका था, इसके बावजूद मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। इस वजह से दोनों की भूमिका संदिग्ध थी। कमेटी ने इस प्रकरण का आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की थी। श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना में 45 लाख रुपए कीमत के मटेरियल की खरीदी की गई थी। जब मटेरियल का बॉक्स खोला गया तो उसमें स्क्रैप मिला। कंपनी ने चार सदस्यीय समिति का गठन कर जांच कराई। पता चला मटेरियल की जगह बॉक्स में स्क्रैप भरकर भेजा गया था। कंपनी प्रबंधन द्वारा मटेरियल सप्लाई करने वाली फर्म मेसर्स क्रिशिव पॉवर बिरसिंहपुर के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। कंपनी ने वर्तमान में बाणसागर जल विद्युत गृह (देवलोंद) में पदस्थ सहायक अभियंता रामराज पटेल, अनुज विश्वकर्मा सहायक अभियंता (उत्पादन) चालू प्रभार ताप गृह दोंगलिया, अरुण कुमार विश्वकर्मा सहायक अभियंता (उत्पादन) सिंगाजी और सुरक्षा कर्मचारी मुकेश घिघोड़े को संदिग्ध मानते हुए समिति की रिपोर्ट के आधार पर निलंबित कर दिया है।

मप्र बाघों की मौत में भी नंबर-1

टाइगर स्टेट मप्र में बीते 6 माह में 23 बाघों की मौत हो चुकी है। इनमें से 12 की मौत अकेले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई है। देशभर में टाइगर की मौत के मामले में मप्र पहले पायदान पर है। वर्ष 2024 में अब तक देश में कुल 75 टाइगर की मौत हुई है। मप्र के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में 14 और तीसरे स्थान पर कर्नाटक में 12 टाइगर की मौत हुई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) के मुताबिक, देश में टाइगर की सर्वाधिक मौतें बांधवगढ़ में ही हो रही हैं। 2012 से 2022 के बीच बांधवगढ़ में 65 टाइगर की मौतें हुई थी, जो देशभर में किसी भी टाइगर रिवर्ज में हुई मौतों में सर्वाधिक थी।

बांधवगढ़ में बाघों की सभी मौतें प्राकृतिक या टेरिटोरियल फाइट नहीं हैं। इनमें आधी मौतों का कारण यहां पदस्थ मैदानी स्टाफ की लापरवाही के साथ कुछ लोगों की शिकारियों से मिलीभगत भी है। यहां के स्थानीय शिकारियों से बाघों के अंतरराष्ट्रीय तस्करों के नेटवर्क से भी जुड़े होने के कुछ सबूत वन विभाग के हाथ लगे हैं। यहां से पकड़े गए कुछ संदिग्ध शिकारियों के बैंक खातों में पिछले कुछ सालों में अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांजेक्शन भी होते आ रहे हैं। वन विभाग की ओर से राज्य शासन को भेजी गई एक गोपनीय जांच रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, यह रिपोर्ट एक माह पहले ही वन विभाग को मिल चुकी है। रिपोर्ट में शिकारियों के नेटवर्क व मनी ट्रेल की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक, 4 माह पहले एनटीसीए ने मप्र वन विभाग से बांधवगढ़ में टाइगर की मौतों के कारणों की पड़ताल करने को कहा था। मार्च 2024 में विभाग ने बांधवगढ़ में 3 साल में हुई मौतों के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें मप्र टाइगर स्ट्राइक फोर्स के प्रभारी रितेश सरोठिया, जबलपुर के स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. काजल जाधव व मानसेवी वन्यप्राणी अभिरक्षक कटनी से जुड़ी अधिवक्ता मंजुला श्रीवास्तव को शामिल किया गया था।

प्रदेश में बाघों की मौत पर उठे सवालों के बाद राज्य के वन्यजीव विभाग ने अधिकारियों की लापरवाही और बाघ संरक्षण में रुचि की कमी को स्वीकार किया है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व (बीटीआर) और शहडोल वन मंडल में 2021 से 2023 के बीच 43 बाघों की मौत के संबंध में वन्यजीव विभाग ने अपनी गलती स्वीकारते हुए अधिकारियों की लापरवाही उजागर की है। विभाग का कहना है कि कुछ अधिकारी अपने कार्य के प्रति लापरवाह थे। बता दें कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने राज्य के वन्यजीव विभाग से स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) द्वारा बाघों की मौतों पर उठाए गए सवालों के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर ये बात सामने आई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले तीन सालों में 34 बाघों की मौत और शहडोल में 9 मौतों के बाद मप्र के बाघ संरक्षण पर सवाल उठाए गए। इस दौरान गठित जांच समिति की रिपोर्ट में कई खामियों का उल्लेख किया गया। इसमें वन विभाग की लापरवाही मुख्य रूप से सामने आई। जांच में बाघों की मौतों के पीछे शिकारियों का हाथ होने का भी अंदेशा जताया गया था। पाया गया कि कई मामलों में तो पोस्टमार्टम ही नहीं किया गया। न ही शिकारियों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कार्रवाई की गई।

प्रदेश में बीते कुछ महीनों से बाघों की मौत का सिलसिला जारी है। बुधनी में हुए हादसे के पहले भोपाल से सटे रायसेन जिले के रातापानी टाइगर रिजर्व के चकलोद रेंज में भी एक बाघ का शव मिला था। वन विभाग से संबंधित लोगों का कहना था कि बाघ की मौत करीबन 10 से 12 दिन पहले हुई होगी। डीएफओ हेमंत रैकवार के मुताबिक इस बाघ की मौत कैसे हुई इसकी जांच कराई जा रही है। इसका पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने इस मामले में पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ शुभरंजन सेन को शिकायत की थी, कि गोली मारकर बाघ का शिकार किया गया है। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद से वन विभाग का अमला बाघ के शव को दो दिनों से खोज रहा था। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग के अमले ने बाघ के शव को खोज निकाला।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 से 2023 के बीच बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन क्षेत्र में 43 बाघों की मौत हुई। इनमें से अधिकांश की जांच में वन्यजीव अधिकारियों की लापरवाही पाई गई। वन्यजीव अधिकारियों की शिथिल जांच, शिकार के मामलों की अनदेखी, पोस्टमार्टम प्रक्रिया में गड़बड़ियां और चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई बाघों की मौतें एसआईटी द्वारा उठाए गए मुद्दों में शामिल थे। इन मुद्दों पर एनटीसीए ने वन्यजीव विभाग से स्पष्टीकरण मांगा था। वन्यजीव विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन ने एनटीसीए को लिखे पत्र में स्वीकार किया कि कुछ मामलों में वन्यजीव मुख्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। जांच में यह भी था कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 34 बाघों की मौत हुई, जबकि शहडोल वन क्षेत्र में 9 बाघों की मौत दर्ज की गई। ये मौते तब हुईं, जब संबंधित क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक अपने पद पर तैनात थे और कोताही बरती गई थी। इस पूरे मामले के बाद, वन्यजीव कार्यकर्ता, जिन्होंने राज्य में बाघों के शिकार की घटनाओं को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी, ने कहा कि वे अब इस मामले में सीबीआई जांच के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।

● कुमार विनोद

बफर जोन में जा रहे बाघ

रिपोर्ट के अनुसार बीटीआर बाघों द्वारा मवेशियों की हत्या में वृद्धि से जूझ रहा है। यह बाघों की आबादी में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ मेल खाता है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान (एआईटीई) के आंकड़ों के अनुसार 2014 में औसतन 63 से 2022 में 165 तक। मवेशियों की हत्या का आंकड़ा सालाना 2,200 तक बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोर क्षेत्रों में बाघों की संख्या बढ़ने से बड़ी बिल्लियों की मृत्यु दर में कमी आई है, जबकि शिकार की आबादी बढ़ी है। नतीजतन, युवा बाघ, विशेष रूप से नर बाघ जो अपने इलाके की तलाश में हैं, बफर जोन में जा रहे हैं। जिसके कारण उनकी पशुधन से मुठभेड़ की खबरे सामने आती हैं। इसकी पुष्टि पशुधन मुआवजे के दावों में वृद्धि से होती है।

खंड-खंड बुंदेलखंड...!

आम जनता को जोड़ने का प्रयास

पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर अक्टूबर महीने में जनजागरूकता अभियान की शुरुआत पदयात्रा से होगी। कार्यक्रम की योजना को लेकर फिल्म अभिनेता और संयोजक राजा बुंदेला ने जिले में समाज के विभिन्न वर्गों से भेंटकर जनसमर्थन जुटाया। ललितपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड के विकास को लेकर केंद्र व राज्य सरकार संकल्पित है। सरकार ने एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरीडोर, हर घर नल जल से लेकर तमाम विकास परक कार्य किए हैं, लेकिन समग्र विकास के लिए जरूरी है अलग राज्य। बुंदेलखंड राज्य की 100 बीमारियों का एक इलाज और वह है पृथक बुंदेलखंड राज्य। छोटे राज्यों को बनाने का श्रेय भाजपा को ही है। भाजपा के चुनावी एजेंडे में भी पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा शामिल रहा है। पृथक राज्य को लेकर स्व. शंकरलाल मल्होत्रा के समय में लगभग डेढ़ दशक पहले तमाम जनांदोलन हुए, रेलें रोंकी गईं, चक्काजाम हुए। विधानसभा में पर्चे फेंके गए और हिंसक आंदोलन हुए। अब केवल इस आंदोलन को वैचारिक रूप से तेज करने की जरूरत है। इसी विचार क्रांति को लेकर और व्यापक जनसमर्थन जुटाने के लिए अक्टूबर महीने में पदयात्रा की शुरुआत होगी। पहले झांसी मंडल में पदयात्रा होगी। इसके बाद जनवरी या फरवरी में चित्रकूटधाम मंडल में पदयात्रा का दौर चलेगा। अक्टूबर महीने में होने वाली पदयात्रा की तैयारियों और जनसम्पर्क के लिए बुंदेलखंड का दौरा शुरू किया गया है।

बुंदेलखंड के लोगों की एक पुरानी मांग एक बार फिर उठने लगी है। यह मांग है बुंदेलखंड राज्य की। इस मांग को मजबूती से उठाने के लिए भाजपा नेता और बॉलीवुड अभिनेता राजा बुंदेला एक पदयात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड की मांग के लिए दशहरे के दिन ललितपुर से पदयात्रा शुरू की जाएगी। यह यात्रा चित्रकूट में जाकर समाप्त होगी। दूसरे चरण में यह पदयात्रा मप्र के बुंदेलखंड में होगी। गौरतलब है कि बुंदेलखंड राज्य की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। विभिन्न जिलों में कुल 13 संगठन है जो इस मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब यह सभी संगठन एक साथ आकर अपनौ बुंदेलखंड नाम से एक अभियान चलाएंगे। बुंदेलखंड राज्य उप्र के 7 और मप्र के 7 जिलों को जोड़कर बनाने की मांग उठाई जाती है। पूर्व में इसके लिए कई बड़े आंदोलन हुए। लेकिन, बीते कुछ समय से यह मांग ठंडी पड़ती नजर आ रही थी। इस पदयात्रा से बुंदेलखंड की मांग को एक बार फिर केंद्र में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग दिनों दिन तेज हो रही है। आम आदमी पार्टी ने भी पृथक राज्य की मांग की है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा गया। पदाधिकारियों ने कहा कि पृथक राज्य से बुंदेलखंड की बदहाली को दूर किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रेमनारायण सिंह राजपूत के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने गत दिनों कलेक्ट्रेट पहुंचकर पृथक राज्य की मांग को जोरदार तरीके से उठाया है। प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि बुंदेलखंड वर्षों से बदहाली का दंश झेल रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में यहां के लोग महानगरों पर आश्रित है। देश के सबसे बड़े प्रदेश को चार राज्यों में बांटा जाए जिसमें पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और पश्चिम प्रदेश हो। आजादी के बाद प्रदेश दो राज्यों में विभाजित था जिसमें विंध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कामता प्रसाद सक्सेना थे। 1956 में मप्र के आठ और उप्र के दस जिलों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। बाद में विंध्य प्रदेश को बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम मिला। 18 जिलों को मिलाकर बुंदेलखंड राज्य की मांग उठाई गई है।

यूं तो बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर कई बार बयानबाजी हुई, लेकिन चुनाव में कभी यह मुद्दा हावी नहीं हो पाया। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में पृथक बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा कभी जोर-शोर से नहीं उठ पाया। यहां तक कि बड़े सियासी दलों के घोषणा पत्रों में भी इसे कभी जगह नहीं मिली। हालांकि, देश की आजादी के बाद करीब 8 सालों तक बुंदेलखंड अगल राज्य रहा, लेकिन बाद में इसके सभी जिलों को उप्र और मप्र में शामिल कर दिया गया। इसके बाद कभी यह अपना पुराना स्वरूप वापस नहीं पा सका। देश की आजादी के बाद 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था। इसकी राजधानी नौगांव हुआ करती थी। तब 35 छोटी-बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। लेकिन, अलग राज्य का यह सफर लंबा नहीं चल पाया। 1 नवंबर 1956 को सातवां संविधान संशोधन लागू होने के बाद मप्र अलग राज्य बना। इसमें बुंदेलखंड के बड़े हिस्से को मप्र में शामिल कर दिया गया, जबकि बाकी हिस्से का उप्र में विलय हो गया था। तब इसको लेकर खूब विरोध-प्रदर्शन और आंदोलन हुए। तब से लेकर अब तक आंदोलन का दौर लगातार जारी है। चुनावों के दौरान समय-समय पर स्थानीय प्रत्याशियों ने इसे अपने निजी एजेंडे में तो जरूर शामिल किया, लेकिन भाजपा, कांग्रेस, सपा व बसपा जैसे दलों के घोषणा पत्रों में यह अपनी जगह कभी नहीं बना पाया।

बुंदेलखंड क्षेत्र में मप्र और उप्र के 14 जिले आते हैं। इसमें उप्र के झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और महोबा जिले आते हैं, जबकि मप्र के दतिया, निवाड़ी, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर और पन्ना जिले आते हैं। इसके अलावा मप्र के भिंड जिले की तहसील लहार, शिवपुरी जिले की करैरा व पिछोर तहसील, अशोकनगर की चंदेरी तहसील, गंजबासौदा जिले की गंजबासोदा तहसील, कटनी जिले की कटनी तहसील एवं सतना जिले की चित्रकूट तहसील बुंदेलखंड में मानी जाती है। इस क्षेत्र में लोकसभा की 9 और विधानसभा की 48 सीटें हैं। उप्र के हिस्से में आने वाले बुंदेलखंड में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 19 सीटें हैं, जबकि मप्र में लोकसभा की 5 और विधानसभा की 29 सीटें हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले जिलों की आबादी 1,84,34,793 थी। जबकि, अब अनुमानित आबादी सवा 2 करोड़ मानी जाती है। बुंदेलखंड का क्षेत्रफल 70,592 वर्ग किलोमीटर है। यहां खनिज की भरमार है, जबकि सबसे ज्यादा बांध भी बुंदेलखंड में हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

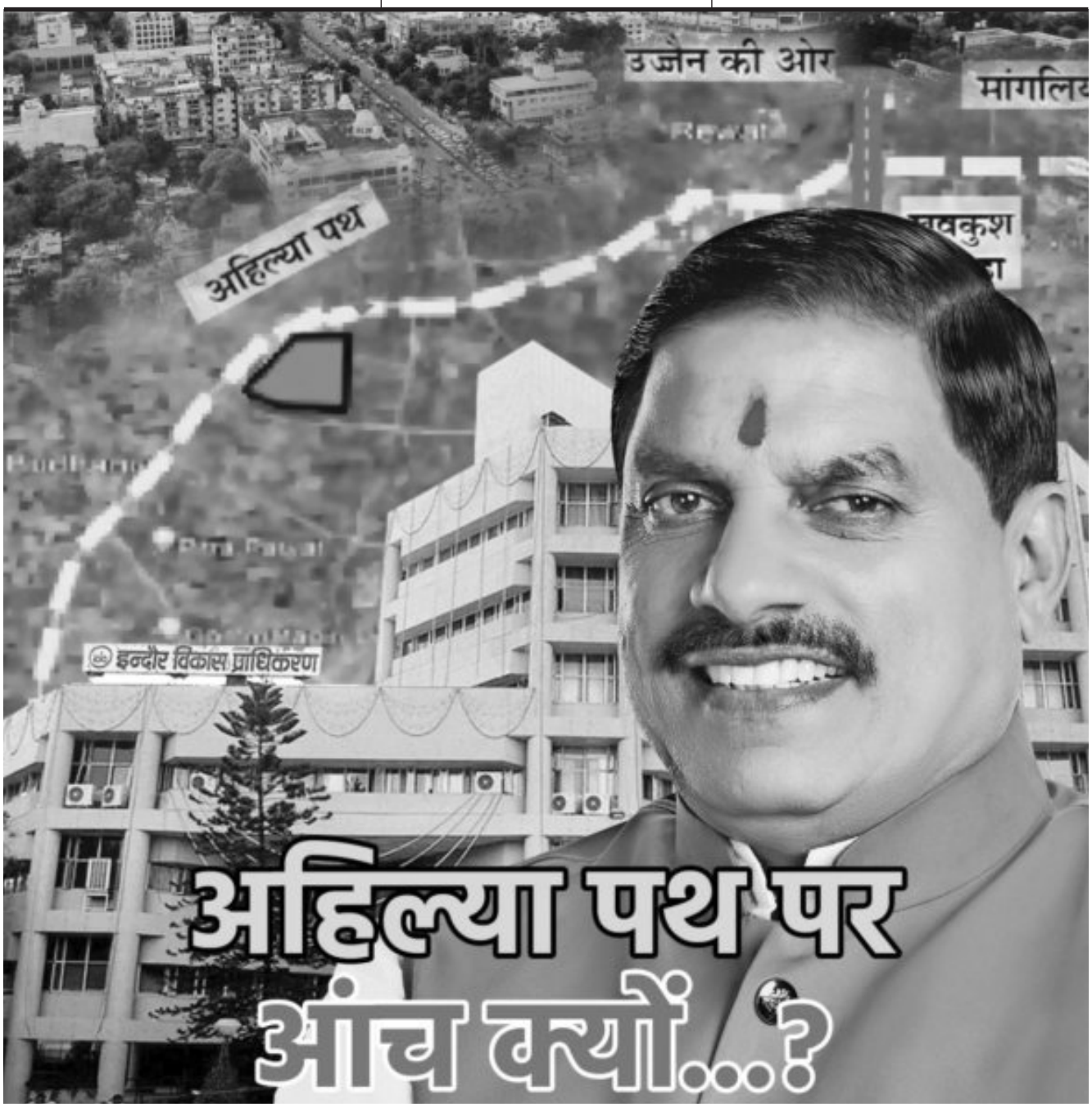

अहिल्या पथ पर आंच क्यों...?

शहरों के विकास के लिए बने प्राधिकरण भर्राशाही, लापरवाही, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) भ्रष्टों की गिरफ्त में इस कदर है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की महत्वाकांक्षी परियोजना 'अहिल्या पथ' भी विवादों में फंस गई है। इस परियोजना में अफसरों ने कई तरह की मनमानी की है, जिससे योजना की राह में कांटे ही कांटे नजर आने लगे हैं।

● राजेंद्र आगाल

मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जिस तरह प्रदेश में सुशासन की नींव मजबूत करने के अभियान में जुटे हुए हैं और प्रदेश में एक समान विकास पर फोकस किए हुए हैं, उसको देखते हुए उनको रिझाने के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण के अफसरों ने एक तानाबाना बुना, जिसके तहत इंदौर से उज्जैन की तरफ विकास के लिए अहिल्या पथ परियोजना का खाका तैयार किया गया है। लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण के अफसरों की भर्राशाही, लालफीताशाही, लापरवाही और भ्रष्टाचार की नीयत ने अहिल्या पथ को विवादित बना दिया है। भावी अहिल्या पथ के लिए जो खाका तैयार किया गया है, उसको लेकर चारों तरफ विरोध हो रहा है। परियोजना के क्षेत्र में आने वाले किसानों ने मोर्चा खोल लिया है। वहीं आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्राधिकरण के अफसरों ने बड़े स्तर पर सांठगांठ कर कुछ लोगों को लाभान्वित करने के लिए योजना का मनमाने तरीके से खाका तैयार किया है।

इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) अपनी कार्यशैली के चलते लगातार भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है। टीपीएस 9 में मास्टर प्लान की रोड मोड़कर खास बिल्डर को फायदा पहुंचाने का मामला रहा हो या स्टेडियम की जमीन खास लोगों को देने का खेल या फिर सुपर कॉरिडोर पर एक खास बिल्डर के होटल प्रोजेक्ट में जमीन की रजिस्ट्री कराने की तेजी का मामला। अब आईडीए की आ रही अहिल्या पथ स्कीम को लेकर हुए करोड़ों के खेल के आरोप लगे हैं। इस मामले की जब पूरी पड़ताल की तो इसमें गंभीर खुलासे हुए, स्कीम अभी भी भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। आईडीए की कोई भी स्कीम गोपनीयता वाली होती है, ताकि पहले से किसी को सर्वे नंबर की जानकारी नहीं मिले। इसके लिए किसी भी स्कीम के लिए फाइल सीईओ और आईडीए की भूमि अर्जन शाखा से चलती है। इनके साथ आईडीए के प्लानर बैठते हैं और फिर गोपनीय बैठकें कर स्कीम की बाउंड्रीवाल तय होती है। इस बाउंड्रीवाल में तय होता कि रोड के दोनों ओर कितने मीटर तक जमीन लेना है, जैसे सुपर कॉरिडोर में तय हुआ 500-500 मीटर, पीथमपुर इकॉनामिक कॉरिडोर में 300-300 मीटर तय हुआ। इस बाउंड्रीवाल के पूरे सर्वे नंबर चेक करते हैं और सभी को स्कीम में लिया जाता है। कोई भी स्कीम सीधी होती है, दोनों ओर समान मीटर तक जाने के चलते इसका एक फिक्स पैटर्न अलग दिखता है। बोर्ड बैठक में स्कीम के साथ सर्वे नंबर आते हैं और फिर यह स्कीम घोषित करने का प्रस्ताव शासन को जाता है। वहां से स्कीम घोषित होने के साथ ही सर्वे नंबर जारी किए जाते हैं।

रोजगार सृजन के लिए बड़ा अवसर

मप्र की व्यवसायिक राजधानी इंदौर से महाकाल की नगरी उज्जैन तक बनने वाला अहिल्या पथ रोजगार सृजन का भी बड़ा अवसर है। 15 किमी लंबी तथा 75 मीटर चौड़ी इस सड़क के किनारे 5 तरह की कॉलोनी बनेंगी, एपी-1 से एपी-5 तक। योजना की कुल लागत 400 करोड़ रुपए है। प्रदेश में पहली बार 6-7 लेन की सड़क बनेगी, जिसके दोनों तरफ फूड पार्क, शॉपिंग मॉल, दुकानें, मेट्रो कॉरिडोर आदि बनाए जाएंगे। यह रोजगार के लिए बड़ा अवसर होगा। अहिल्या पथ योजना की खूबसूरती यह है कि जहां एक ओर फाइनेंशियल व टेक्नोलॉजीकल डेवलपमेंट में 5 हजार करोड़ से ज्यादा पूंजी निवेश आएगा, बल्कि दूसरी तरफ मध्यम वर्ग के लोगों एवं बेरोजगारों के सपनों को पूरा करने के लिए अहिल्या पथ मप्र सरकार की विजीबिलिटी को भी स्थापित करेगा।

अलग-अलग योजनाओं में बनेगा पथ

ये हैं 5 फेज	क्षेत्रफल, हेक्टेयर ग्राम	सड़क की चौड़ाई
अहिल्या पथ -1	227 नैनोद रिजलाय	4.55 किमी
अहिल्या पथ -2	450 बुढ़ानिया बड़ा बांगड़दा	1.80 किमी
अहिल्या पथ -3	214 पालाखेड़ी बुढ़ानिया	2.40 किमी
अहिल्या पथ -4	338 पालाखेड़ी लिंबोदागारी	1.25 किमी
अहिल्या पथ -5	171 रेवती, बरदरी	5 किमी

इस तरह बना भ्रष्टाचार का पथ

अहिल्या पथ किस तरह भ्रष्टाचार का पथ बना जब इसकी पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आया कि आईडीए के चेयरमैन जयपाल सिंह चावड़ा के समय नवंबर 2023 में ही इस स्कीम को लाने की बात बाजार में छोड़ दी गई। इसकी खबरें तक छप गईं और गांव की जानकारी भी सामने आ गई। यानी गोपनीयता पूरी तरह तभी खत्म हो चुकी थी। सबसे अहम बात स्कीम लाने की कोई भी फाइल कभी भी भू-अर्जन विभाग से चली ही नहीं है, जो सबसे पहला कदम होता है। यह काम केवल चावड़ा, आईडीए सीईओ अहिरवार, कॉन्ट्रैक्ट पर प्लानर बने मयंक जगवानी और उनकी टीम के सदस्य प्रदीप चौरसिया, सुरभि और आईडीए प्लानर रचना बोचरे के बीच रहा। स्कीम का लब्बोलुआब इन लोगों ने ही तय किया और फिर दो दलालों के जरिए बाजार में जमीन मुक्त करने और लेने के लिए खेल शुरू हुआ। एक दलाल तो लगातार आईडीए सीईओ के चेंबर के बाहर ही बैठक करते रहे। स्कीम की कोई तय बाउंड्रीवाल नहीं बनाई गई। ना तय हुआ कि रोड के दोनों ओर कितने मीटर तक जमीन लेना है। सभी सौदे तय होने के बाद फिर रोड के दोनों और बाउंड्रीवाल बनाने का काम शुरू किया गया। इसमें जिसके सर्वे नंबर लेने या छोड़ने का मामला तय हुआ उस हिसाब से जमीन की बाउंड्रीवाल बनी। इसके चलते पूरी स्कीम में कहीं पर जमीन रोड के 300 मीटर तक ली तो कहीं पर 700 मीटर तो कहीं पर 200 मीटर, यानी कोई फिक्स नियम नहीं रखा। इसके चलते स्कीम का पैटर्न फिक्स नहीं, बल्कि एक आड़ा-तिरछा अलग ही हो गया। जनवरी से लेकर जून तक इस स्कीम को लेकर सौदे और खेल होते रहे, इस दौरान 30 बड़े लोगों ने टीएंडसीपी भी करा ली और आईडीए से जुड़े एक कॉन्ट्रैक्टर ने तो वहां 30 एकड़ जमीन खरीद ली और किसानों को बयान देकर कई सौदे इस स्कीम के दायरे में हो गए। जून में हुई आईडीए की बोर्ड बैठक में स्कीम लॉन्च की गई, इसके साथ ही टीएंडसीपी पर रोक लग गई। लेकिन इसके पहले नवंबर से जून तक पूरा खेल हो चुका था। अब हद तो यह है कि आईडीए के भू-अर्जन विभाग को स्कीम के पहले दिन शामि और जगवानी को 13-14 अगस्त को बोर्ड बैठक (16 अगस्त) के दो-तीन दिन पहले था फिर सर्वे नंबर तय हुए और बोर्ड में प्रस्ताव रख शासन को अब भेजा गया।

पूरी प्रक्रिया जगवानी के हवाले चली

इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता रखने की जगह आउटसोर्स पर कॉन्ट्रैक्ट पर लिए गए मयंक जगवानी और उनकी टीम के हवाले रखी गई। क्या चल रहा है यह आईडीए में सिर्फ और सिर्फ अहिरवार और जगवानी की जानकारी में रहा। प्लानर रचना बोचरे को अभी भी आईडीए के पूरे खेल की जानकारी नहीं है और उनकी इस अनभिज्ञता का पूरा फायदा इस टीम ने उठाया और मनचाहे तौर से स्कीम बनाई। मयंक जगवानी को करीब चार साल पहले आईडीए में तब के प्लानर द्वारा मदद के लिए लाया गया था, क्योंकि तब आईडीए में प्लानर की कमी थी। उस समय जगवानी का वेतन मात्र 50 हजार रुपए प्रतिमाह था। लेकिन यह फिर 75 हजार, फिर सवा लाख रुपए से होते ही चार साल में पांच गुना हो गया और करीब ढाई लाख रुपए प्रतिमाह का भुगतान आईडीए द्वारा उन्हें किया जाता है। आईडीए ने उन्हें कमरा व अन्य संसाधन भी दिए हैं। हालत यह है कि वह आईडीए में बैठकर उन्हीं के रिसोर्स, कर्मचारी सभी का उपयोग करते हैं। इंदौर में क्योंकि जमीन का खेल है और पूरे प्रदेश के बड़े लोगों की नजरें और निवेश दोनों यहीं पर है, इसका फायदा जमकर जगवानी उठा रहे हैं, वह एक तरह से आईडीए अधिकारी के तौर पर ही टीएंडसीपी, अन्य विभाग, भोपाल सभी जगह लाइजनिंग में जुट गए हैं। आईडीए ने भी गोपनीय कामों में जगवानी को पूरा जिम्मा दे दिया है। आईडीए

अहिल्या पथ का विरोध, सड़कों पर उतरे ग्रामीण

मप्र के इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा करीब 400 करोड़ की लागत से बनने वाले अहिल्या पथ को लेकर तैयारी चल रही है। वहीं इस पथ को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में इंदौर के रेवती रेंज के ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर इस योजना के तहत किए जाने वाले अतिक्रमण को लेकर विरोध जताया है। इंदौर-उज्जैन रोड के समीप रेवती रेंज से रिजलाय तक करीब 15 किलोमीटर तक बनने वाले अहिल्या पथ को लेकर पहले ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं योजना मार्ग में आने वाले क्षेत्र के रहवासी अब इस योजना का विरोध सड़क पर कर रहे हैं। सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रेवती के सैकड़ों रहवासियों ने गत दिनों शासकीय स्कूल के समीप चौराहे पर एकत्रित होकर योजना का विरोध किया। विरोध करने वालों में पुरुषों के साथ महिलाओं भी थी। योजना का विरोध कर रहीं महिलाओं का कहना था कि उन्हें जानकारी लगी है, कि इस योजना के तहत बनाई जाने वाली सड़क के लिए कई मकानों को हटाया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान मप्र के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट के प्रतिनिधि और पूर्व सरपंच राजू ठाकुर भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे अहिल्या पथ योजना हो या अन्य कोई योजना हो किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। यदि ऐसा होता है, तो वह रहवासियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पूर्व सरपंच राजू ठाकुर ने इस दौरान लोगों के बीच इंदौर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार से भी फोन पर बात की। उन्होंने जनता की ओर से अपनी बात अधिकारी के सामने रखी। इस पर सीईओ आरपी अहिरवार ने फोन पर सकारात्मक आश्वासन दिया। जिसके बाद भाजपा नेता राजू ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में आईडीए के संबंधित अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाएगा और इस मामले को लेकर यहीं चर्चा होगी। किसी का भी मकान किसी कीमत पर नहीं टूटने दिया जाएगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने जमकर नारे भी लगाए।

सीईओ अहिरवार ने पूरा जिम्मा मयंक जगवानी को सौंप दिया है, इसके साथ ही दो दलाल तो आईडीए में घूमते ही रहते हैं। इस तरह से पूरा नेक्सस बन चुका है जो बाजार में जमीन को स्कीम में मुक्त करने या शामिल करने के साथ एक और बड़ा खेल खेलते हैं। वह खेल है स्कीम में जिसकी जमीन ली है उसे प्लाट कहां दिया जाए। स्कीम में जिससे डील हो उसे मौके का, कार्नर का फ्रंट में प्लाट दिया जाता है और यह डील करोड़ों की होती है, वहीं जिससे डील नहीं हो और जो पॉवरफुल नहीं हो उसे पीछे प्लाट दे दिया जाता है। अब अहिल्या पथ स्कीम में अगला खेल यही होना है। इसके लिए कोई फिक्स नीति नहीं होती है।

बड़े भ्रष्टाचार की आशंका

अहिल्या पथ पर भूमाफियाओं, दलालों, नेताओं और अधिकारियों ने सिंडिकेट बनाकर जनवरी 2023 से 20 अगस्त 2024 के बीच अहिल्या पथ स्कीम से प्रभावित गांवों में 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के नक्शे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से स्वीकृत कराकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव के अनुसार योजना 1400 हेक्टेयर की है, लेकिन अधिकारियों ने स्कीम में शामिल गांवों की 300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के नक्शे स्वीकृत कर योजना का बंटाधार कर शासन को 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया है। बड़ा बांगड़दा में 35 नक्शे 125 हेक्टेयर में स्वीकृत किए गए, नेनौद में 16 नक्शे 50 हेक्टेयर, बरदरी में 9 नक्शे 15 हेक्टेयर, लिम्बोदागिरी में 5 नक्शे 9 हेक्टेयर, पालाखेड़ी में 7 नक्शे 18 हेक्टेयर, बुधानिया में 5 नक्शे 16 हेक्टेयर मिलाकर अहिल्या पथ की लगभग 300 हेक्टेयर पर साजिश रच ताबड़तोड़ नक्शे स्वीकृत कराए हैं। ज्यादातर नक्शों को ऑनलाइन नहीं किया गया है। यादव ने आरोप लगाया कि अहिल्या पथ में एलायमेंट परिवर्तित करने का खेल सीईओ रामप्रसाद अहिरवार और मयंक जगवानी ने खेला है। अनेक जमीन मालिकों से अहिल्या पथ अलायमेंट बदलकर स्कीम की बाउंड्री परिवर्तित करके करोड़ों का भ्रष्टाचार स्कीम से जमीन बाहर करने में किया गया है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान की सूची एवं अहिल्या पथ स्कीम के अलायमेंट के दो नक्शे भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए जारी किए गए हैं।

रिजलाय एवं रेवती में एक भी नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है। इन दो गांवों में लैंड यूज परिवर्तन का बड़ा षड्यंत्र अहिरवार ने किया है। कृषि, ग्रीन बेल्ट लैंड यूज होने से नक्शे स्वीकृत नहीं हुए, लेकिन आईडीए की स्कीम लगते ही लैंड यूज आवासीय और वाणिज्यिक में परिवर्तन होने के साथ ही जमीन सोना उगलना शुरू कर देगी। अनेक भूमाफियाओं और भोपाल के एक बड़े अधिकारी ने पिछले एक साल में सैकड़ों एकड़ जमीन इन गांवों में ताबड़तोड खरीदी है। रजिस्ट्रार के आंकड़े सारी कहारियां बयां कर रहे हैं।

अहिल्या पथ स्कीम भ्रष्टाचार कांड में आईडीए सीईओ रामप्रसाद अहिरवार, मंयक जगवानी एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर केएस गवली को तत्काल पदों के हटाया जाना चाहिए। जयपाल सिंह चावड़ा और अहिरवार ने क्रमश: पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी में कंपनियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर स्कीम की जमीन खरीदकर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से नक्शे स्वीकृत कराए हैं। इस आरोप की उच्च स्तरीय जांच कराने पर तथ्य सामने आ जाएंगे। 1 जनवरी 2023 से 20 अगस्त 2024 तक अहिल्या पथ स्कीम में आने वाले समस्त गांवों में स्वीकृत नक्शे तत्काल प्रभाव से निरस्त करना चाहिए। अहिल्या पथ स्कीम में शामिल समस्त खसरों के नंबर तत्काल फ्रीज कर सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे अलायमेंट के खेल से होने वाला भ्रष्टाचार रोका जा सके।

अहिल्या पथ स्कीम में शामिल गांवों की भूमि लगभग पूर्णत: निर्माण रहित खाली है। सरकार जियो टेपिंग कराकर स्कीम क्षेत्र को चिन्हित करे जिससे अवैध निर्माण या षड्यंत्र न हो सके। खाली जमीनों की वीडियोग्राफी एवं वर्तमान गूगल मैप का भी सत्यापन करके जारी करना चाहिए। रिजलाय और रेवती में मास्टर प्लान में भू उपयोग कृषि एवं ग्रीन बेल्ट होने की वजह से सरकार को आईडीए स्कीम में इन दोनों गांवों में लैंड यूज कृषि और ग्रीन बेल्ट को फ्रीज कर भूमाफियाओं को सबक सिखाना चाहिए। इन दोनों गांवों में अहिल्या पथ स्कीम में लैंड यूज परिवर्तित नहीं कराना चाहिए।

भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को निलंबित करने की मांग कांग्रेस महासचिव राकेश सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से की है कि अहिल्या पथ स्कीम में भ्रष्टाचार करने वाले सीईओ रामप्रसाद अहिरवार, मयंक जगवानी और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डिप्टी डायरेक्टर केएस गवली को तत्काल निलंबित कर सभी

मामलों की निष्पक्ष जांच के आदेश देना चाहिए। इस संदर्भ में लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा को सबूतों सहित शिकायत की गई है। आईडीए एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की मिलीभगत से पास 77 से ज्यादा नक्शे डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त कर मप्र सरकार और आईडीए को 1000 करोड़ से ज्यादा की होने वाली राजस्व हानि से बचाना चाहिए।

आसान नहीं राह

इंदौर विकास प्राधिकरण ने 15 किमी लंबे अहिल्या पथ को सैद्धांतिक मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। 8 गांव की 1400 हेक्टेयर जमीन पर आईडीए की यह योजना आकार लेगी। इस 1400 हेक्टेयर जमीन में से टाउनशिप, मकान बने हुए हैं। वहीं कई जमीन मालिकों ने नगर तथा ग्राम निवेश में 3 से 5 लाख रुपए तक फीस भरकर अनुमति भी ले रखी है। प्रशासन ने ही विकास अनुमति भी जारी कर दी है। जमीन मालिकों ने निजी विकास के लिए भी आवेदन कर रखे हैं। सैद्धांतिक सहमति के बाद से 8 गांव के जमीन मालिकों में चिंता है। योजना में कौन-से खसरे शामिल किए जाएंगे, यह भी तय नहीं है। इन गांवों में दर्जनों जमीन मालिकों ने टाउनशिप विकसित कर ली है या कर रहे हैं। निवेशकों को प्लॉट भी बेच दिए हैं। वहीं ऐसे भी लोग हैं, जिन्होंने सैद्धांतिक सहमति से पहले ही टीएंडसीपी में फीस जमा करा दी थी। इस मामले में आईडीए अफसरों का कहना है कि पूरी योजना का सर्वे किया जाएगा। जमीन मालिकों की सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ही योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। ग्राम पालाखेड़ी, बड़ा बांगड़दा ऐसे गांव हैं जो आईडीए की योजनाओं में ही खत्म हो गए हैं। सबसे पहले सुपर कॉरिडोर लॉन्च किया गया। बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी के किसानों ने कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक के समक्ष जमीन नहीं देने के लिए प्रदर्शन किया था। यहां के किसानों को उनके मालिकाना हक की जमीन का उपयोग उनकी मर्जी के हिसाब से करने का अवसर ही कभी नहीं मिला। आज तक भी कई किसानों की विकसित प्लॉट की रजिस्ट्री तक नहीं कराई गई।

सैद्धांतिक स्वीकृति के बाद किसानों की जमीन एक तरह से फ्रीज हो गई है। छह महीने के भीतर आईडीए स्कीम जारी नहीं कर पाया तो ही नियमानुसार यह लैप्स हो पाएगी। राऊ में जब स्कीम लाई गई थी, तब किसान इसी तरह परेशान हुए थे। आईडीए की विभिन्न योजनाओं में भी 110 से ज्यादा कॉलोनियां मुक्त होने का इंतजार कर रही हैं। इनका नियमितीकरण नहीं हो रहा है। वहीं कई हाउसिंग सोसायटी की जमीन भी आईडीए ने अपनी योजनाओं में उलझाकर

योजनाओं में शामिल जमीनों पर अभिन्यास मंजूरी अधर में

प्राधिकरण ने पिछले दिनों 15 किलोमीटर लंबे अहिल्या पथ में शामिल 1400 हेक्टेयर जमीन पर 5 नई टीपीएस योजनाएं घोषित की हैं, जिनमें लगभग 100 एकड़ जमीनों पर 2 दर्जन अभिन्यासों की मंजूरी हो चुकी है। हालांकि प्राधिकरण ने इन जमीनों को भी योजना में शामिल कर लिया है। वहीं बोर्ड ने संकल्प पारित कर अब शासन को इन योजनाओं की मंजूरी के लिए भी पत्र भेज दिया है। दूसरी तरफ कलेक्टर ने इन जमीनों पर अभिन्यास मंजूर करने पर रोक भी लगा दी, जिसके खिलाफ तीन जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कीं, जिस पर सुनवाई के बाद फिलहाल कोई राहत इन जमीन मालिकों को नहीं मिल सकी है। यानी नगर तथा ग्राम निवेश कोई भी नए अभिन्यास इन जमीनों पर मंजूर नहीं करेगा। 10 सितंबर या उसके बाद हाईकोर्ट इस मामले में फिर अगली सुनवाई करेगा। दरअसल, इन योजनाओं की जानकारी कॉलोनाइजरों-बिल्डरों से लेकर रसूखदारों को मिल गई और उन्होंने धड़ाधड़ जमीनें तो खरीदी ही, साथ में अभिन्यास भी मंजूर करवा लिए, ताकि योजना में जमीनें शामिल न हो सकें और उसका लाभ भी उन्हें अलग से मिल जाए, क्योंकि प्राधिकरण 15 किलोमीटर का अहिल्या पथ बनाएगा, जिसके चलते दोनों तरफ की जमीनों के दाम कई गुना बढ़ जाएंगे। अभी 16 अगस्त को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 5 नई टीपीएस योजनाएं मंजूर की गई, जिसमें नैनोद, रीजलाय, बुड़ानिया, बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, लिम्बोदागारी, रेवती और बरदरी की लगभग 1400 हेक्टेयर यानी लगभग साढ़े 3 हजार एकड़ जमीनें शामिल की गईं। रीजलाय से रेवती तक मास्टर प्लान में घोषित 15 किलोमीटर लंबा और 75 मीटर चौड़ा मार्ग प्राधिकरण बनाएगा, जिसे अहिल्या पथ नाम दिया गया है। कुछ दिन पहले प्राधिकरण ने बोर्ड संकल्प के साथ इन पांचों योजनाओं में शामिल जमीनों, उनके खसरों सहित अन्य जानकारी शासन को भिजवा दी है, ताकि वहां से मंजूरी मिल सके।

रख दी है।

अभिन्यास कर डाले मंजूर

प्राधिकरण ने अपनी पिछली बोर्ड बैठक में 15 किलोमीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े अहिल्या पथ निर्माण के लिए नई आधा दर्जन टीपीएस योजनाओं को लागू करने की सैद्धांतिक सहमति दी। नैनोद, रीजलाय, बुड़ानिया, बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, बरदरी और रेवती में ये योजनाएं प्रस्तावित की गईं। इनके साथ लिम्बोदागारी में गोल्फ कोर्स सिटी योजना भी अमल में लाने का निर्णय लिया गया। वहीं दूसरी तरफ नगर तथा ग्राम निवेश में एक बड़ा खेला हो गया और 100 एकड़ से अधिक इन नई टीपीएस योजनाओं में शामिल की जाने वाली जमीनों के अभिन्यास रसूखदारों ने मंजूर करवा डाले। अब भोपाल में बैठे प्रमुख सचिव से लेकर संभागायुक्त, कलेक्टर सहित अन्य आला अधिकारी इस खेल पर भौंचक हैं और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार अधीनस्थ अफसरों से जानकारी भी मांगी और साथ ही मंजूर अभिन्यासों की सूची तैयार करवाई। जिसमें 23 अभिन्यास तो मंजूर भी हो गए, जबकि 35 अभिन्यास अभी मंजूरी की प्रक्रिया में थे। मगर कलेक्टर ने सभी पर रोक लगवा दी।

यह पहला मौका नहीं है जब इंदौर के जमीनी जादूगरों ने इस तरह का चमत्कार दिखाया है। पूर्व में भी प्राधिकरण की योजनाओं में इस तरह के खेल होते रहे हैं। अपनी जमीनों को योजनाओं से बचाने के लिए जहां अभिन्यास मंजूर करवाकर रख लिए जाते हैं, तो दूसरी तरफ नई योजनाओं की भनक मिलने पर भी संबंधित गांवों की जमीनों की ना सिर्फ खरीद-फरोख्त की जाती है, बल्कि उनके भी अभिन्यास मंजूर करवा लेते हैं, ताकि योजनाएं घोषित होते ही कई गुना मुनाफा कमाया जा सके। ऐसा ही अभी एक बड़ा खेला नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों ने खेला और प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में अहिल्या पथ निर्माण के लिए जो 5 टीपीएस योजनाएं अमल में लाई जानी है और उसके साथ छठी योजना

गोल्फ कोर्स सिटी भी है, उनकी जमीनों पर नगर तथा ग्राम निवेश के होशियार अधिकारियों ने अभिन्यास मंजूर कर दिए हैं। जबकि वहां बोर्ड के एक सदस्य संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश खुद रहते हैं। सूत्रों के मुताबिक नैनोद में अशोक एसोसिएट तर्फे पार्टनर चेतन शाह का अभिन्यास 3.146 हेक्टेयर जमीन पर मंजूर हुआ, तो इसी तरह बर्दरी में राजेश बलवानी का खसरा नंबर 65/2/2 पर, इसी तरह कल्याणी कंस्ट्रक्शन तर्फे मनमीतसिंह सलूजा का अभिन्यास पालाखेड़ी में 2.326 हेक्टेयर जमीन पर, रामराज, चंद्रशेखर व अहिल्याबाई के नाम से बड़ा बांगड़दा में 1.012 हेक्टेयर, संगीता बाकलीवाल का अभिन्यास बड़ा बांगड़दा में, तो रुपेश और भावना सिंघल का अभिन्यास लिम्बोदागारी में, नागेश्वर इंफ्राबिल्ट तर्फे कैलाश गोयल, बदरीलाल, विक्रम, मुकेश व अन्य का अभिन्यास बड़ा बांगड़दा की 3.182 हेक्टेयर जमीन पर मंजूर कर दिया, तो इसी तरह शंकरलाल, रवीशचंद्र घिया, सविता कुलवाल, पीयूष खंडेलवाल, गीता देवी, हरीश कुलवाल, सौरभ खंडेलवाल व अन्य की नैनोद स्थित 5.509 हेक्टेयर का अभिन्यास मंजूर हुआ, तो बड़ा बांगड़दा में ही 5.049 हेक्टेयर में नेक्सटीन रियलिटी तर्फे पार्टनर सुभाष पंवार व अन्य के अलावा बड़ा बांगड़दा में गणेश कुमावत, रामेश्वर, भरत शर्मा के अभिन्यास मंजूर हुए, तो बुड़ानिया की 2.595 हेक्टेयर जमीन पर आइडियल ग्रुप रियलिटी तर्फे बहादुर सिंह, बड़ा बांगड़दा की 2.9415 हेक्टेयर जमीन पर रिद्धी-सिद्धी देवकॉन तर्फे मनीष लड्ढा, सुमित जैन, राम गोपालदास महंत का अभिन्यास मंजूर हुआ, तो बड़ा बांगड़दा की ही 6.032 हेक्टेयर पर राजेश काले, राजेश शर्मा, गौरी बाई, विष्णु, हीरालाल व अन्य, बड़ा बांगड़दा में ही 3.286 हेक्टेयर पर कैलाश गोयल, दीपक, सतीश व शत्रुंजय ब्रदर्स के अभिन्यास के अलावा बड़ा बांगड़दा में 4.487 पर रामचंद्र कुसुमाकर, ठाकुर लाल, राधा बाई और अन्य जमीन पर विनायक इंफ्रा तर्फे रीतेश गोयल, सीमा सिंघल, अशोक कुमार व अन्य के अलावा 5.131 हेक्टेयर बड़ा बांगड़दा की ही जमीन पर नितिन कुसुमाकर और लीड्स डेवलपर्स और 6.5584 हेक्टेयर बड़ा बांगड़दा में ही नेक्स्ट ट्रीन रियलिटी का दूसरा अभिन्यास भी मंजूर कर डाला। इसी तरह बड़ा बांगड़दा में 0.347 हेक्टेयर पर मनोहर सिंह, सीमा सिंह और ग्राम बर्दरी में 0.405 हेक्टेयर पर मोहनलाल, जीतेश सहलानी व अन्य के अभिन्यास मंजूर कर डाले हैं, जिनमें कुल मिलाकर 100 एकड़ से अधिक जमीनें शामिल है, जो प्राधिकरण की प्रस्तावित टीपीएस योजनाओं में ली जानी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि शहर के कई प्रमुख बिल्डरों-कालोनाइजरों से लेकर राजनीतिक दबाव-प्रभाव वाले रसूखदारों को उनके व्हाट्सएप पर ही योजना और उसमें शामिल होने वाली जमीनों की जानकारी पहले ही मिल गई थी, जिसके चलते जहां जमीनों के नए सौदे किए गए, वहीं धड़ाधड़ अभिन्यास मंजूर करवाए गए।

प्राधिकरण ने अपनी पिछली बोर्ड बैठक में रेवती से लेकर रीजलाय तक 15 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 5 टीपीएस योजनाएं अहिल्या पथ निर्माण के लिए लागू करने की सहमति दी और फिर सीईओ आरपी अहिरवार ने भोपाल पहुंचकर प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई को भी इन योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही प्रमुख सचिव ने भी इस बात पर आश्चर्य जताया कि नगर तथा ग्राम निवेश के इंदौर कार्यालय ने इन प्रस्तावित योजनाओं की कई जमीनों पर अभिन्यास कैसे मंजूर कर दिए। यही स्थिति संभागायुक्त और प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक सिंह से लेकर कलेक्टर आशीष सिंह की भी है। ये सभी आला अधिकारी भी भौंचक हैं कि ये अभिन्यास कैसे मंजूर किए गए, जिसको लेकर अब जांच भी शुरू की गई है। साथ ही नगर तथा ग्राम निवेश से इन आला अफसरों ने योजना में शामिल की जाने वाली नैनोद, रिजलाय, बुड़ानिया, बड़ा बांगड़दा, पालाखेड़ी, बर्दरी और रेवती की जमीनों पर मंजूर और लंबित अभिन्यासों की सूची भी तैयार करवाई। ये सभी अभिन्यास अभी कुछ समय पूर्व ही ताबड़तोड़ मंजूर किए गए हैं, जिसको लेकर भोपाल तक हल्ला मचा है।

आईडीए की योजनाओं में घालमेल

प्राधिकरण की योजना 171 की गुत्थी सालों से सुलझ नहीं सकी है, क्योंकि इसमें शामिल एक दर्जन से अधिक गृह निर्माण संस्थाएं विवादित रही हैं, जिनकी जमीनों को चर्चित भूमाफियाओं ने हड़प लिया। अब प्राधिकरण द्वारा इस योजना को मुक्त कराने के लिए डीनोटिफिकेशन करवाया जा रहा है, जिसके लिए शासन ने भी पिछले दिनों मार्गदर्शन भेजा, जिसके आधार पर प्राधिकरण बोर्ड प्रस्ताव पारित कर दावे-आपत्तियों को बुलवाने की प्रक्रिया करेगा। वहीं इस योजना में शामिल देवी अहिल्या गृह निर्माण के अलावा न्याय नगर कर्मचारी गृह निर्माण संस्था की वरीयता सूची भी तैयार की जा रही है, ताकि पात्र-अपात्रों का निर्धारण हो सके। प्रदेश शासन ने लैंड पुलिंग पॉलिसी घोषित की, जिसके चलते प्राधिकरण की पुरानी योजनाएं भी पहले तो समाप्त हुईं, उसके बाद टीपीएस के तहत उन्हीं जमीनों पर नई योजनाएं घोषित कर दी गईं। मगर योजना 171 को इसलिए समाप्त नहीं किया था, क्योंकि इसकी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में रहीं। देवी अहिल्या, मजदूर, पंचायत, न्याय नगर से लेकर सूर्या गृह निर्माण, रजत गृह निर्माण, त्रिशला गृह निर्माण, महिराज, लक्ष्मण नगर सहित एक दर्जन से अधिक संस्थाएं विवादित रही हैं, जहां पर भूखंड पीड़ितों की जमीनें भूमाफियाओं ने बेच दीं। हालांकि इनमें से कुछ जमीनें सरेंडर करवाईं और अभी पिछले दिनों ही देवी अहिल्या की कॉलोनी अयोध्यापुरी और श्री महालक्ष्मी नगर की ढाई लाख स्क्वायर फीट से अधिक जमीनों पर हुई अवैध रजिस्ट्रियों को कोर्ट ने भी शून्य कर दिया। दूसरी तरफ पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए विधायक महेंद्र हार्डिया एक बार फिर जुटे और कलेक्टर आशीष सिंह के साथ चर्चा की, जिसमें राजगृही, न्याय नगर, श्री महालक्ष्मी नगर, पुष्प विहार, अयोध्यापुरी के पीड़ितों का मामला उठा। प्राधिकरण सीईओ अहिरवार और उपायुक्त सहकारिता गजभिये भी मौजूद रहे। इसमें यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही प्राधिकरण डीनोटिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू करे, ताकि इन संस्थाओं को एनओसी मिल सके। अभी सिर्फ कब्जे हैं, मगर भवन निर्माण सहित अन्य अनुमतियां नहीं मिल पा रही है। अब प्राधिकरण बोर्ड शासन से मिले मार्गदर्शन के आधार पर योजना 171, 77 सहित अन्य को डीनोटिफाईड करने पर निर्णय लेगा और फिर प्रशासन तथा सहकारिता विभाग से प्राप्त भूमि स्वामी सहित अन्य रिकॉर्डों के आधार पर दावे-आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

राज्यों की मनमानी पर पहरा

केंद्रीय योजनाओं के लिए प्राप्त राशि या राज्य के लिए आवंटित विशेष फंड के इस्तेमाल में कुछ राज्य सरकारों के स्तर पर हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। वित्त मंत्रालय द्वारा एसएनए-स्पर्श (समयोजित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) नाम से लागू इस नई व्यवस्था के तहत राज्यों के फंड प्रवाह पर अब ज्यादा सतर्क नजर केंद्र रख सकेगी। इस नई व्यवस्था मे केंद्र सरकार के विभागों की भूमिका भी ज्यादा प्रभावशाली होगी और उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी निभानी होगी। इस नई व्यवस्था से केंद्र राज्यों के वित्त प्रबंधन पर इस हिसाब से नजर रख सकेगा कि कहीं किसी खास उद्देश्य से भेजे गए फंड का इस्तेमाल चुनावी वादों को पूरा करने के लिए तो नहीं किया जा रहा। केंद्र सरकार ने मप्र समेत सभी राज्यों को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में केंद्रांश प्राप्त करने के लिए एसएनए-स्पर्श (समयोजित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) मॉडल को अपनाना अनिवार्य कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, मप्र उन राज्यों में शामिल है, जो इस मॉडल को अपनाने में पिछड़ गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मप्र समेत अन्य राज्यों को पत्र भेजा है। इसमें केंद्र प्रवर्तित 27 योजनाओं के लिए केंद्रांश प्राप्त करने के लिए एसएनए-स्पर्श मॉडल को अपनाकर भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग समाधान ई-कुबेर में अनिवार्य रूप से खाता खुलवाने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि यदि सरकार ऐसा नहीं कर पाती है, तो उसे केंद्रीय योजनाओं में केंद्रांश नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार का पत्र मिलते ही मप्र सरकार हरकत में आ गई है। वित्त विभाग ने आयुक्त कोष एवं लेखा (सीटीए) को आरबीआई के ई-कुबेर में सभी विभागों का खाता खोलने की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जो फंड इस्तेमाल ना हुआ हो उसे भारत सरकार के फंड में ट्रांसफर करने की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार के खाते में केंद्र सरकार की तरफ से दी गई राशि का जो हिस्सा इस्तेमाल न हुआ हो उसे भी वापस करने का निर्देश दिया गया है। इस बारे में अलग से भी विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की बात कही गई है। जिस दिन राज्य सरकार अपने हिस्से का फंड संबंधित खाते में डालेगी, केंद्र का हिस्सा भी उसी दिन ही जाएगा।

दरअसल, हाल ही में वित्त मंत्रालय को फंड इस्तेमाल में राज्यों की तरफ से की जा रही गड़बड़ियों की सूचना दी गई है। एसएनए-स्पर्श व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग को भी आरबीआई में एक विशेष खाता (एसएनए) खोलना होगा जिसके जरिए फंड का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए घोषित हर विशेष कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी का गठन करेगी। राज्य सरकार की तरफ से भी आरबीआई में अपने विशेष स्कीम के लिए एसएनए खोलेगी। इसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त खाते में दोनों के हिस्से की राशि जमा हो। इसमें जिस आधार पर फंड वितरण का फैसला हुआ हो उसी हिसाब से पैसे जमा किए जाएं। बाद में यह देखा जाएगा कि इस फंड का कितना इस्तेमाल हो रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी विभागों के खाते ई-कुबेर में खुलवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। जैसे ही ई-कुबेर में ये खाते खुलेंगे, मप्र सरकार एसएनए-स्पर्श पोर्टल पर आ जाएगी। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एसएनए स्पर्श मॉडल लागू होने पर बैंकों में पहले से खुले राज्य सरकार के विभागों के एसएनए (स्टेट नोडल एजेंसी) खाते बंद हो जाएंगे। उनके स्थान पर आरबीआई में ई-कुबेर में खाते खोले जाएंगे। सभी विभाग एसएनए खातों में पैसा जमा रखते हैं और जब किसी योजना में जरूरत होती है, तो खातों से पैसा निकालकर उपयोग करते हैं। एसएनए-स्पर्श मॉडल में पैसा बैंक खातों में जमा नहीं रहेगा। जैसे ही राज्य सरकार को किसी योजना के लिए फंड की जरूरत होगी, तो संबंधित विभाग केंद्र को प्रपोजल भेजेगा। प्रपोजल मिलने के बाद केंद्र सरकार के विभाग आरबीआई में ई-कुबेर में खुले खाते में अपना शेयर ट्रांसफर करेंगे और यहां से राज्य सरकार अपना शेयर ट्रांसफर करेगी और तत्काल हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। केंद्र

सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार जिन केंद्रीय योजनाओं के लिए ई-कुबेर में खाता जरूरी है उनमें रूसा, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्राकृतिक स्रोतों व ईकोसिस्टम का संरक्षण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना, पशुपालन विभाग के डेवलपमेंटल प्रोग्राम, खाद्यानों का एक से दूसरे राज्य में आवाजाही, पीएम एफएमई, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन, इन्फ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस, आयुष्मान भारत-पीएम जन आरोग्य योजना, अमृत, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ज्यूडीशरी के लिए अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेट गारंटी प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएमश्री, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नदी जोड़ो योजना, मिशन शक्ति और पुलिस बल का आधुनिकीकरण योजना शामिल है।

● इंद्र कुमार

रियल टाइम में रिलीज होगा पैसा

एसएनए-स्पर्श मॉडल अपनाने से कई फायदे होंगे। एसएनए-स्पर्श मॉडल में हितग्राहियों को रियल टाइम में पैसा रिलीज होगा। एसएनए खातों में अनावश्यक पैसा जमा नहीं रहेगा। वर्तमान में यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार से राशि जारी होने के बाद राज्य सरकार को 30 दिन की अवधि में केंद्र और राज्य के पैसे को मिलाकर एसएनए खाते में राशि जमा करना होती है। एसएनए खाते में पैसा डालने के बाद खर्च करने तक वह खाते में जमा रहता है। महालेखाकार (एजी) को अभी जो अकाउंटिंग मिल रही है, वह एसएनए खाते में ओवरऑल राशि ट्रांसफर करने संबंधी मिल रही है। एसएनए-स्पर्श मॉडल लागू होने के बाद एजी को राज्यों के वित्त प्रबंधन पर बारीकी से नजर रख सकेगा कि किसी खास उद्देश्य से भेजे गए फंड का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ है या नहीं। किस योजना में कितने हितग्राहियों को, कितनी राशि का आवंटन किया गया है।

दलबदलुओं पर दांव

भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि वह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन राज्यसभा के लिए हो रहे चुनाव में पार्टी ने अपने नेताओं को दरकिनार कर दलबदलुओं को टिकट दिया है। इससे पार्टी में रोष है। वहीं लगातार दलबदलुओं को महत्व देने से पार्टी के कैडरबेस कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं।

राज्यसभा उपचुनाव में 11 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है जबकि एक राज्यसभा सीट के लिए मतदान कराया जाएगा। निर्विरोध चुने जाने वालों में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की 10 सीटें खाली हो गई थीं। वहीं बाद में राज्यसभा के दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था। नए चुनाव के बाद चुने जाने वाले सदस्य निवर्तमान सदस्यों के बाकी बचे कार्यकाल के लिए होंगे। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट में दलबदलुओं पर दांव है तो साथ ही कैडर को बैलैंस करने की कवायद भी। आइए, जानते हैं भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट में क्या खास है?

मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मप्र से राज्यसभा सांसद थे। सिंधिया ने गुना संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री सिंधिया के इस्तीफे से रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने एक केंद्रीय मंत्री को ही उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद वे निर्विरोध चुन लिए गए। भाजपा ने मप्र की इस सीट से उपचुनाव में केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन को टिकट दिया था। साल 1980 में भाजपा की स्थापना के समय से ही वह पार्टी में हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। केरल भाजपा के उपाध्यक्ष जॉर्ज कुरियन को हालिया लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल नारे की भी झलक है। भाजपा ने अधिकतर राज्यों की सीट पर स्थानीय चेहरे ही उतारे हैं।

मप्र से जॉर्ज कुरियन और राजस्थान से रवनीत बिट्टू, इन दो को छोड़ दें तो हर राज्य की सीट से उसी राज्य के नेता को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा से किरण चौधरी हों, बिहार से मनन कुमार मिश्रा हों या त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य, भाजपा ने स्थानीय चेहरे उतारने पर ही फोकस किया है। कुरियन और बिट्टू जिस राज्य से आते हैं, वहां की किसी सीट के लिए न तो उपचुनाव हो रहे हैं और ना ही विधानसभा में भाजपा किसी को राज्यसभा भेजने की स्थिति में है। ऐसे में इन दो केंद्रीय मंत्रियों का किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा जाना मंत्री पद की शपथ के साथ ही तय हो गया था।

8 राज्यों की 9 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने चार दलबदलुओं पर दांव लगाया। इन चार में से दो कांग्रेस से आए नेता हैं। महाराष्ट्र की शेतकारी कामगार पक्ष और ओडिशा की बीजू जनता दल से छोड़ भाजपा में आए एक-एक नेता को भी राज्यसभा का टिकट दिया गया है। पंजाब कांग्रेस का कद्दावर चेहरा रहे रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में आए थे।

जिन 11 राज्यसभा सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, उसमें असम, बिहार और महाराष्ट्र में दो-दो, हरियाणा, मप्र, राजस्थान, तेलंगाना और ओडिशा में एक-एक सीट शामिल हैं। 10 मौजूदा सदस्यों के लोकसभा सांसद के तौर पर निर्वाचित होने के बाद राज्यसभा की सीटें खाली हो गई थीं। वहीं बाद में राज्यसभा के दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया था।

हरियाणा- इस राज्य से भाजपा की किरण चौधरी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। हाल ही में तोशाम से विधायक किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई थीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आवश्यक संख्या बल न होने का हवाला देते हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवारी न पेश करने की घोषणा की थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा से इस्तीफे के कारण राज्य में चुनाव हुआ। दीपेंद्र ने रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीता था।

मप्र- इस राज्य से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन निर्विरोध चुने गए हैं। केरल से आने वाले भाजपा के दिग्गज नेता जॉर्ज कुरियन केंद्र में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यह सीट मप्र से राज्यसभा के सदस्य रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी। सिंधिया ने गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की। भाजपा नेता को केंद्र की मोदी कैबिनेट में दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय

एक तरफ जाट, दूसरी तरफ सिख

भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए जिन उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है उसमें हरियाणा और पंजाब की राजनीति को साधने का प्रयास किया है। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दो नेताओं को बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया है और राज्यसभा भेजने की तैयारी है। हरियाणा से बंसीलाल परिवार की पुत्रवधू किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर पार्टी से नाराज माने जा रहे जाट वोटबैंक को साधने का प्रयास किया गया है। कहा जाता है कि भाजपा हरियाणा में नॉन जाट पॉलिटिक्स करती है, लेकिन किरण चौधरी के चेहरे को आगे करके भाजपा ने इसका जवाब दिया है। इससे पहले एक और पार्टी के बड़े जाट चेहरे सुभाष बराला को भी राज्यसभा भेजा जा चुका है। वहीं, केंद्रीय रेल राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से राज्यसभा सांसद चुन लिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने उनको पंजाब से सिख चेहरे के तौर पर आगे किया और केंद्र सरकार में राज्यमंत्री का पद दिया और अब रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा सांसद चुन लिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू के माध्यम से भाजपा पंजाब में सिख वोट को टारगेट कर रही है।

पंजाब में बड़े सिख वोट बैंक को साधने की कोशिश

माना जाता रहा है कि पंजाब में भाजपा हमेशा से ही एक बड़े सिख चेहरे की तलाश में रही है जो कि पार्टी को पंजाब में और भी मजबूती दे सके। इसी कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू पर लगातार पार्टी की और से भरोसा जताया जा रहा है। दूसरा रवनीत सिंह बिट्टू बेअंत सिंह परिवार से आते हैं और भाजपा इस परिवार के जरिए पंजाब के बड़े सिख वोटबैंक को साधने का प्रयास लगातार कर रही है। कांग्रेस से तीन बार सांसद सदस्य रहे, पार्टी को अलविदा कहकर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं और परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। रवनीत सिंह बिट्टू पहली बार आनंदपुर साहिब से 2009 में लोकसभा चुनाव जीते थे, उसके बाद 2014 में सीट बदलकर लुधियाना आ गए, वहां से लगातार दो बार जीते। 2024 में लुधियाना से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से 20 हजार वोटों के मामूली अंतर से हार गए। हार के बावजूद केंद्र में राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया। भाजपा ने पंजाब से सिख चेहरे के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्र में आगे किया, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। 2009 में उन्होंने पंजाब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंजाब के युवाओं में मादक पदार्थों की लत के खिलाफ अभियान शुरू किया। रवनीत सिंह बिट्टू का जन्म 10 सितंबर, 1975 को कोटली, जिला लुधियाना, पंजाब में हुआ। उन्हें पंजाब के युवा सिख राजनेता के तौर पर पहचान मिली।

भी सौंपा गया है।

राजस्थान- यहां से भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू निर्विरोध चुने गए। यहां तीन उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से भाजपा के एक डमी उम्मीदवार सुनील कोठारी थे, जिन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। इनके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी बबीता वाधवानी का नामांकन पत्र 22 अगस्त को जांच के दौरान रद्द कर दिया गया था। वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया था। जिसके चलते बिट्टू उपचुनाव में एकमात्र उम्मीदवार बचे थे। पंजाब से आने वाले सिख नेता केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री हैं।

बिहार- इस राज्य से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और सुप्रीम कोर्ट के वकील मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र और भाजपा नेता मिश्रा सत्तारूढ़ एनडीए के उम्मीदवार थे। राज्यसभा के सदस्य रहे भाजपा के विवेक ठाकुर और राजद की मीसा भारती लोकसभा चुनाव जीते थे और उच्च सदन से इस्तीफा दे दिया था।

महाराष्ट्र- यहां से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नितिन पाटिल और भाजपा के धैर्यशील पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। राज्यसभा की ये दोनों सीटें पीयूष गोयल और उदयनराजे भोंसले के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने से रिक्त हुई थीं। महाराष्ट्र से भाजपा के राज्यसभा के सांसद रहे पीयूष और उदयनराजे अब लोकसभा के सदस्य हैं। मुंबई उत्तर सीट से जीते गोयल को मोदी सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री बनाया गया। वहीं दूसरे नेता उदयनराजे भोंसले सतारा से लोकसभा सांसद चुने गए।

असम- प्रदेश भाजपा के राज्यसभा चुनाव उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजनदास निर्विरोध चुने गए। डिब्रूगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और काजीरंगा से कामाख्या प्रसाद तासा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद दोनों सीटें खाली हुई थीं। विपक्षी दलों ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारे थे। सोनोवाल केंद्र में खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री हैं।

तेलंगाना- राज्यसभा उपचुनाव में निर्विरोध चुने वालों में कांग्रेस से वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हैं। कांग्रेस ने तेलंगाना में उपचुनाव के लिए वरिष्ठ वकील सिंघवी की उम्मीदवारी की घोषणा की थी। इस साल की शुरुआत में सिंघवी कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा चुनाव हार गए थे। तेलंगाना में हाल में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के के. केशव राव पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। राव ने उच्च सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी।

ओडिशा- भाजपा उम्मीदवार ममता मोहंता राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। कुड़मी समुदाय की प्रमुख नेता ममता मोहंता के ओडिशा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के कुछ घंटे बाद ही पार्टी के एक और नेता जगन्नाथ प्रधान ने 21 अगस्त को डमी उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था। बाद में प्रधान ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन वापस ले लिया। दरअसल, बीजू जनता दल (बीजद) की सांसद रहीं ममता मोहंता ने राज्यसभा सीट और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मोहंता बीजद से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गईं।

जिन 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 7 सीटें भाजपा, दो कांग्रेस और एक-एक राष्ट्रीय जनता दल (राजद), बीआरएस और बीजद के पास थीं। कांग्रेस और राजद दोनों ही विपक्षी गठजोड़ के प्रमुख घटक हैं। वहीं बीआरएस और बीजद अभी किसी भी गठजोड़ में शामिल नहीं हैं। अब 11 सीटों पर उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन से उच्च सदन में भाजपा नीत एनडीए को फायदा हुआ है। भाजपा के 8 उम्मीदवार और उसके सहयोगी दलों, रालोम और राकांपा के एक-एक उम्मीदवार संसद के उच्च सदन के लिए निर्विरोध चुने गए। उधर कांग्रेस ने तेलंगाना से एक सीट जीती है जिससे राज्यसभा में इसकी कुल सीटें 27 हो गई हैं।

राज्यसभा में कुल सीटें 245 हैं। अभी 8 सीटें रिक्त हैं, जिनमें चार जम्मू-कश्मीर और चार मनोनयन वाली सीटें हैं। इस तरह मौजूदा सदस्य संख्या 237 है और बहुमत का आंकड़ा 119 है। गत दिनों एनडीए के सदस्य 111 हो गए। उच्च सदन में अकेले भाजपा के 96 सदस्य हैं, जो इसे सबसे बड़ी पार्टी बनाता है। एनडीए को छह मनोनीत और एक निर्दलीय सदस्य का भी समर्थन है। इस तरह, उसके सदस्यों की संख्या 118 हो गई, जो बहुमत से एक सीट कम है। हालांकि, 3 सितंबर को त्रिपुरा में होने वाले मतदान में भाजपा अकेले ही अपने उम्मीदवार को जिता सकती है। इस नतीजे के बाद एनडीए को राज्यसभा में बहुमत मिल जाएगा।

● **विपिन कंधारी**

विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी भाजपा आराम की नहीं बल्कि मिशन मोड में नजर आ रही है। पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए भाजपा देशभर में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने के लिए 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरु करने जा रही है। इसके तहत मप्र में भाजपा ने डेढ़ करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने संगठन का गठन ही नहीं किया है।

सदस्यता मिशन में जुटी भाजपा

मप्र के गठन के 68 सालों के दौरान कांग्रेस ने यहां सबसे अधिक शासन किया है। लेकिन इसके बाद भी आज की स्थिति में मप्र में कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भाजपा संगठन का मुकाबला कर सके। इसका असर विधानसभा और उसके बाद लोकसभा चुनाव में देखा जा चुका है। एक तरफ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रिकार्ड जीत के बाद भी भाजपा संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक सदस्य बनाने के अभियान में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति यह है कि 7 माह बाद भी प्रदेश संगठन का गठन तक नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव होने के बाद एक बार फिर भाजपा ने पार्टी में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को जोड़ने और भर्ती करने का प्लान बनाया है। 1 सितंबर से शुरू होने वाले भाजपा सदस्यता अभियान का लक्ष्य पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने और सदस्य बनाने का है। भाजपा का राष्ट्रीय सदस्यता अभियान 1 सितंबर से शुरू होगा। ये अभियान दो चरणों में चलेगा। अभियान का पहला चरण 1 सितंबर से 25 सितंबर तक चलेगा। इसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान का द्वितीय चरण चलेगा। 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक एवं सक्रिय सदस्यता का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस अभियान के लिए मप्र की कमान अतुल गर्ग को सौंपी गई है। अतुल गर्ग गाजियाबाद से भाजपा सांसद हैं, जिन्हें मप्र का प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि मप्र में ये अभियान दो चरणों में होगा।

मप्र में एक बार फिर भाजपा संगठन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, जहां मप्र में भाजपा सदस्यता महाअभियान शुरू करने जा रही है। इस सदस्यता महाअभियान से पहले संगठन की बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें संगठन की मजबूती के साथ-साथ महाअभियान की सफलता का खास प्लान तैयार किया गया है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा एवं सदस्यता अभियान प्रदेश प्रभारी व विधायक भगवानदास सबनानी ने प्रदेश कार्यालय में संगठन पर्व-2024 के अंतर्गत आयोजित प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि हम सबके लिए गर्व कि बात है कि हमारे आदर्श नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक विजय बूथ-बूथ पर हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पणभाव का परिणाम है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि संगठन के प्रति उनके परिश्रम के चलते मप्र विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय एवं लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीट पर अभूतपूर्व विजय हासिल हुई है। जन-जन के मन में भाजपा संगठन की लोकप्रियता के पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की शक्ति है। हम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर यह संकल्प लिया है कि मप्र में भाजपा की सदस्यता का नया इतिहास रचेंगे। संगठन पर्व के तहत इस बार हम मप्र में डेढ़ करोड़ नए भाजपा सदस्य बनाएंगे।

परफार्मेंस पर पोस्ट फार्मूला

देशभर में शुरू हुए भाजपा के सदस्यता अभियान में पार्टी ने मप्र में डेढ़ करोड़ नए सदस्य बनाने का टारगेट रखा है। टारगेट को पूरा कैसे किया जाएगा, इस पर भोपाल में हुई पार्टी की पहली बड़ी कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अब सरकार के ऐसे कई काम आने वाले हैं, आप सदस्यता करके दिखा दें, बाद में यही पूछा जाएगा कि पद मांगने आ गए, उस समय कहां थे जब सदस्यता अभियान चल रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि चुने हुए लोगों की भी परीक्षा हो जाएगी कि जब पद मिले तब क्या किया। डॉ. मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश में साढ़े 8 से 9 करोड़ की आबादी में 68 लाख मतदाता पिछली बार बनाए गए थे। इस बार करीब साढ़े 4 करोड़ मतदाता हैं। जिसमें से डेढ़ करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि रोगी कल्याण समिति एल्डरमेन समिति, जनकल्याण समिति जैसी कई समितियां बनने जा रही हैं। सरकार के ऐसे कई बड़े काम आने वाले हैं। अब आपके पास मौका है, आप सदस्यता करके दिखा दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाद में यही पूछा जाएगा कि पद मांगने आ गए, उस समय कहां थे, जब सदस्यता अभियान चल रहा था।

पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से भाजपा संगठन सदस्यता अभियान में नया रिकॉर्ड बनाएगा।

सदस्यता अभियान के लिए भाजपा ने नेताओं के लिए टारगेट भी तय किया है। 1 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है जिसमें सांसद को 25 हजार, विधायक को 15 हजार, महापौर को 10 हजार, जिलाध्यक्ष, मंडलाध्यक्ष, मोर्चा जिलाध्यक्ष को 5-5 हजार सदस्य जोड़ने का टारगेट दिया है। भाजपा अपनी जनहितैषी नीतियों से पहले मतदाताओं को जोड़ती है फिर वह भाजपा का सदस्यता बनता है। सदस्यता से वह सक्रिय कार्यकर्ता, पदाधिकारी और फिर नेता बनता है। ऐसे भाजपा खड़ी होती है। भाजपा सदस्यता अभियान में चार तरीके अपनाएगी। पार्टी ने एक मिस्ड कॉल नंबर 8800002024 जारी किया है, जिस पर कॉल करके लोग सदस्य बन सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत हर मिस्ड कॉल को फिजिकली वेरीफाई किया जाएगा। इसके साथ ही, क्यूआर कोड और नमो एप के जरिए भी सदस्यता अभियान को बढ़ावा दिया जाएगा। मैनुअली फॉर्म भरकर भी भाजपा की सदस्यता ली जा सकेगी। सदस्यता अभियान को मजबूत करने के लिए जिलेवार टीमें बनेंगी। जिलास्तर पर सदस्यता अभियान को बढ़ावा देने के लिए 1+3 टीमें बनाई जाएंगी। शक्ति केंद्रों के संयोजक सदस्यता अभियान का नेतृत्व करेंगे। जिलेवार सदस्यता अभियान को मजबूत करने के लिए टीमें गठित की जाएंगी। सदस्यता अभियान में नए सदस्यों को जोड़ने के लिए जिलास्तर पर टीमें बनेंगी। इस दौरान निष्क्रिय नेताओं की सूची तैयार होगी। साथ ही सक्रियता पर कार्यकर्ता और नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। मप्र में भाजपा इस बार केवल मिस्ड कॉल से नहीं बल्कि क्यूआर कोड और नमो एप के जरिए पार्टी की सदस्यता बढ़ाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष

वीडी शर्मा ने बताया कि इस सदस्यता अभियान में इस बार डॉक्टर्स, आर्टिस्ट और समाजसेवियों की तरफ भी पार्टी का रुझान होगा। कांग्रेस से जुड़े वोटरों को भी भाजपा की सदस्यता लेने का मौका है। भाजपा इसके अलावा नए सदस्यों की स्क्रीनिंग के साथ पुराने सदस्यों के मेंबरशिप रिन्यूअल की प्रोसेस शुरू करेगी। पिछली बार जिस तरह से मिस्ड कॉल के जरिए नए सदस्य बनाए गए थे, इस बार भाजपा क्यूआर कोड और नमो एप के जरिए पार्टी की सदस्यता दिलाएगी। वीडी शर्मा ने कहा कि हमारा खास फोकस बूथ और शक्ति केंद्रों पर है, जिसमें हारे हुए बूथ, जहां लगातार हार मिली और जहां जीते उन बूथों पर हमारा खास फोकस है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ भाजपा अकेली पार्टी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह से लेकर हर कार्यकर्ता को सदस्यता रिन्यू करवानी पड़ती है। 6 साल बाद सबको नए सिरे से सदस्यता लेनी पड़ती है। ये नियम केवल भाजपा में ही है। इसी बहाने पार्टी में सदस्यता का रिव्यू भी होता है।

मप्र भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी का लक्ष्य 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का है। इस बार, अभियान की सफलता से न केवल संगठन को मजबूती मिलेगी, बल्कि इससे जिलों के नेताओं का कद भी तय होगा। जो नेता ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने में सफल होंगे, उन्हें संगठन में बड़ा पद मिल सकता है। वहीं, निष्क्रिय नेताओं की सूची भी तैयार की जाएगी। बता दें, भाजपा हर छह साल में नए सिरे से सदस्य बनाती है। पिछली बार भाजपा के 95 लाख सदस्य थे। इस बार 55 लाख अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि हर नेता को अपने क्षेत्र में संगठन को मजबूती से खड़ा करना होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हार का सामना कर चुकी है। वीडी शर्मा ने कहा कि संगठन को कमजोर बूथों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। इसके लिए हर सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को जुटना होगा। उन्होंने कहा कि एक-एक शक्ति केंद्र पर ध्यान देना होगा। नए प्रयोग करने होंगे। कौन सा वर्ग हमसे छूटा हुआ है उस पर ध्यान दें। विधानसभा, लोकसभा में किस वर्ग का वोट हमें नहीं मिला इस पर फोकस करें। शर्मा ने कहा कि अवसर पर काम होता है तो इतिहास बनता है। प्रदेश में 2 करोड़ 24 लाख वोट लोकसभा में मिले। हमें लोकसभा में हारी हुई 27 विधानसभा और विधानसभा चुनाव में हारी 66 सीटों पर फोकस करना होगा।

● **रजनीकांत पारे**

मंत्रियों को जरूरत के हिसाब से प्रभार

मंत्रियों को जिलों में प्रभार वितरण में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने विकास और सुशासन के फॉर्मूले का आधार बनाया है। इसलिए मंत्रियों को जिलों का प्रभार उनकी पसंद नहीं बल्कि जिलों की जरूरत के हिसाब से दिया गया है। गौरतलब है कि प्रभारी मंत्री को जिले में चल रही योजनाओं की सीधी मॉनीटरिंग और नई योजनाओं की मंजूरी का अधिकार रहता है। प्रभारी मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार प्रभार के जिले में जिला योजना समिति की बैठक करनी होती है। सरकार जिलों में प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में ही नई योजना या नए कार्यक्रम का शुभारंभ करती है। इस प्रकार जिले में विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभारी मंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमूमन किसी जिले में बड़ी घटना-दुर्घटना होने पर प्रभारी मंत्री को ही डैमेज कंट्रोल करने भेजा जाता है। प्रभारी मंत्री जिले में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मप्र के हर क्षेत्र में एक समान विकास का जो मॉडल बनाया है, उसको देखते हुए प्रदेश सरकार के मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपने में ऐसे कई तरह के समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। ऐसे में कई मंत्री नाखुश बताए जा रहे हैं। कई दिग्गज मंत्रियों को छोटे जिलों का प्रभार सौंपने का फैसला चौंकाने वाला है, लेकिन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रणनीति के तहत वरिष्ठ मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा है। जिलों में बड़े नेताओं के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्री की रहेगी, ताकि विकास कार्य प्रभावित न हों। मुख्यमंत्री ने अपने पास इंदौर जिले का प्रभार रखा है। इंदौर प्रदेश की व्यापारिक राजधानी है। आने वाले वर्षों में प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन इंदौर में होगा, मुख्यमंत्री प्रभारी मंत्री के रूप में इन आयोजनों पर सीधी नजर रखेंगे।

मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा पर समीक्षा बैठक

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन मार्च 2026 तय की है। उन्होंने कहा है कि सरेंडर पॉलिसी, हमले और विकास के दम पर इसे खत्म किया जाएगा। शाह का यह दावा इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि नक्सलियों के गढ़ फोर्सेस लगातार अभियान चला रही है। लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। फोर्स नक्सलियों की मांद में घुसकर उनसे टक्कर ले रही है।

इसी का नतीजा है कि पिछले आठ महीने में राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में 46 नए कैंप स्थापित किए हैं। इस दौरान 546 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है जबकि नक्सल गतिविधियों में संलिप्त 559 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसी तरह 147 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता भी मिली है। वहीं सिर्फ अगस्त महीने में ही 179 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। शाह की डेडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार के पास इस समस्या को जड़ से मिटाने के लिए सिर्फ 17 महीने का समय ही शेष है। वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में नक्सली सक्रिय हैं। इनमें बीजापुर, दंतेवाडा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, आबगढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली जिले शामिल हैं। शाह ने खुद स्वीकार किया है कि देश का 90 फीसदी हिस्सा छत्तीसगढ़ का है जो नक्सल प्रभावित है।

छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाकों पर नजर डालें तो वहां पर लगभग 60 हजार से ज्यादा जवान तैनात हैं। इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के अलावा सीएएफ के जवान शामिल हैं। इसके अलावा बस्तर बटालियन, पुलिस, डीआरजी के जवान भी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। पिछले 8 माह में सरकार ने नक्सल इलाकों में 33 सुरक्षा कैंप स्थापित किए हैं। इसके अलावा जल्द ही 16 और कैंप खोले जाने की तैयारी चल रही है। कैंप खोलने के साथ ही क्षेत्र के विकास की रणनीति भी तैयार की गई है। राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में नियद नेल्लानार योजना चलाई जा रही है। इसे आपका अच्छा गांव भी कहा जाता है। इस योजना के तहत कैंप के पांच किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। इसके तहत 17 विभागों की 53 जनकल्याणकारी तथा 28 सामुदायिक योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

गत दिनों केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर राज्यीय समन्वय समिति की बैठक रायपुर में हुई। नक्सलवाद के खात्मे के लिए 7 राज्यों के अधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे तक बैठक चली। जिसमें सभी राज्यों ने अपनी-अपनी समस्याएं बताईं। इस दौरान अमित शाह ने कहा- मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। शाह ने कहा कि अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ रुथलेस रणनीति बनाई जाए और अब नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम प्रहार किया जाए। अमित शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद लोकतंत्र व्यवस्था के लिए चैलेंज है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, पहले 10 वर्षों में 6617 सुरक्षाकर्मी और नागरिकों की मृत्यु हुई थी और अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। मुझे विश्वास है कि हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंच गई है और हम देश को मार्च 2026 तक पूरी तरह से नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं का 100 फीसदी क्रियान्वयन हो, ऐसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति हो और ऐसी परियोजनाओं के दौरान आने वाली चुनौतियों को दूर किया जा सके, इसके लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। अब समय आ गया है कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या पर एक मजबूत रणनीति के साथ अंतिम प्रहार किया जाए।

अमित शाह ने कहा कि बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कुछ फैसले भी लिए हैं, जो लोग वामपंथी उग्रवाद के लंबे समय के प्रभाव के कारण निरक्षर रहे हैं चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, उन्हें साक्षर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक अभियान चलाएगा। तेंदूपत्ता की खरीदी में हम अमूलचूल परिवर्तन भी करेंगे। अमित शाह ने कहा, कहीं 3 राज्यों का तो कहीं 2 राज्यों का संयुक्त टास्क फोर्स बनाया गया है, जहां जैसा जंक्शन है वह बनाया गया है, सूचनाओं के आदान-प्रदान का खाका मजबूत किया गया है और भारत सरकार की एजेंसियां सभी राज्यों के बीच समन्वय के लिए काम कर रही हैं और संयुक्त टास्क फोर्स के हमें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं।

बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, मप्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के सामने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर प्लान बना। शाह ने कहा कि 2026 में देश नक्सलवाद से मुक्त होगा। अमित शाह ने बताया कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ फैसले लिए हैं। इसके साथ ही राज्य की सरेंडर पॉलिसी को अपडेट किया जाएगा। शाह ने कहा कि नई पॉलिसी को जल्द ही घोषित किया जाएगा। नक्सवाद वाले इलाकों में साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। जो लोग निरक्षर हैं उनको साक्षर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय इसके लिए काम करेंगे।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

सात राज्यों में एक्टिव हैं नक्सली

नक्सली सात राज्यों में एक्टिव हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाडा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनांदगांव, मोहल्ला मानपुर, आबगढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, सुकमा, कबीरधाम और मुंगेली जिले में नक्सली सक्रिय हैं। वहीं ओडिशा के कालाहांडी, कंधमाल, बोलांगीर, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नुआपाड़ा और रायगढ़ नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। झारखंड के पांच जिले गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूमि इसमें शामिल है। आंध्रप्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू, पूर्वी गोदावरी, पार्वतीपुरम मान्यम, श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिले शामिल हैं। मप्र के बालाघाट, मंडला जिले और डिंडोरी जिले में नक्सलियों का प्रभाव दिखता है। केरल के वायनाड़ और कुन्नूर, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली और गोंदिया, तेलंगाना में भाद्राद्री-कोथागुड़ेम और मुगुलू जिलों में नक्सलियों का दबदबा है।

सीएम फेस का पेंच

क्या शरद पवार कर रहे हैं खेल

उद्धव के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जिस तरह से शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है, उसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। क्या उद्धव के नाम पर शरद पवार पेंच फंसा रहे हैं? 2019 में महाविकास अघाड़ी के गठन के वक्त तीनों दलों की ओर से उद्धव के नाम पर सहमति जाहिर कर दी गई थी। उद्धव सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाले थे, लेकिन शरद पवार ने डिमांड का दांव खेल दिया। इसकी वजह से राजभवन में दावा पेश करने से उद्धव चूक गए और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। हालांकि, देवेंद्र के शपथ की वजह से एक महीने में ही महाराष्ट्र से राष्ट्रपति शासन हट गया। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि शरद पवार उद्धव के नाम पर पेंच फंसाकर अपने निगोसिएशन पावर बढ़ाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। गठबंधन में अब तक सिर्फ 2 पार्टियों को लेकर ही तस्वीर साफ होने की बात कही जा रही थी। इनमें कांग्रेस के ज्यादा सीटों पर लड़ने की चर्चा और शिवेसना (यूबीटी) के उद्धव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात थी। हालांकि, शरद पवार की मांग शुरू से सभी पार्टियों के बराबर-बराबर सीटों पर लड़ने की रही है।

महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में यह सवाल काफी अहम हो चुका है। इस बीच उद्धव ठाकरे ने साफ शब्दों में कह दिया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा जल्द से जल्द घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि शरद पवार और पृथ्वीराज इसकी घोषणा करें। मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि मैं अपने लिए नहीं लड़ता। मैंने महाराष्ट्र के लिए अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ दिया है। महाराष्ट्र को झुकाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। बैठक में पृथ्वीराज चव्हाण और शरद पवार भी मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने मंच से नाना पटोले का नाम लेकर भी कहा कि आप जिसे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, मेरा खुलकर समर्थन रहेगा। बस सीट शेयरिंग को लेकर मत लड़िए। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि हमने शरद पवार से बात की है उन्होंने ये भी कहा कि हम अजित पवार को छोड़कर सबको ले सकते हैं, जो-जो छोड़कर गए हैं। बैठक में उद्धव ठाकरे खूब गरजे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को बचाने का वक्त है। ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। हमें उनसे लड़ना है, जो महाराष्ट्र लूटने आए हैं। मैं महाराष्ट्र के हितों की भी रक्षा करूंगा।

उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह काफी समय से अपने सहयोगी दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करना चाहते थे। आज संयोग बन गया है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। उन्हें चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी है। हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में अपने राजनीतिक दुश्मनों को ढेर कर दिया। वह चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए था। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जैसा कहा अगर हम सब एक रहेंगे तो हमारी सरकार बनना तय है। जबकि सुप्रिया सुले ने कहा कि दिल्ली में हवा बदल चुकी है। मैं महाविकास आगाड़ी ने नेताओं से गुजारिश करती हूं कि जो भी फैसला लेना हो, वो जल्द लीजिए। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हमारी यात्रा शुरू हो गई है और लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है।

दिल्ली में उद्धव ठाकरे ने जब गत दिनों शरद पवार, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की थी, तब कहा गया कि महाराष्ट्र को लेकर महाविकास अघाड़ी में सभी पेंच सुलझ गए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एक हफ्ते में ही इन सुलझे पेंच को 3 नेताओं के बयान ने उलझा दिया है। पहला बयान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का है। उन्होंने कहा है कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला चुनाव बाद होगा। जो पार्टी सबसे ज्यादा विधायक जीतकर आएगी, मुख्यमंत्री उसी का होगा। दूसरा बयान कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दिया है। पटोले ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार अगर मुख्यमंत्री के चेहरे पर बोलते हैं तो मैं कोई प्रतिक्रिया दूं। तीसरा बयान महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के संस्थापक शरद पवार ने दिया है। सीनियर पवार ने कहा है कि पृथ्वीराज चव्हाण के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाविकास अघाड़ी (शिवसेना-उद्धव, एनसीपी-शरद और कांग्रेस) का मुकाबला महायुति (शिवसेना-शिंदे, एनसीपी-अजित और भाजपा) से है। 2019 में शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे को गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री घोषित किया गया था। हालांकि, उद्धव के नेतृत्व में 3 साल ही यह सरकार चल पाई। 2022 में उद्धव की पार्टी में और 2023 में शरद पवार की पार्टी में टूट हुई। दोनों दलों से टूटे हुए लोगों ने भाजपा के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली।

2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को महाविकास अघाड़ी ने झटका दे दिया। इस परिणाम से महाविकास अघाड़ी के दलों के हौंसले बुलंद हैं और सबकी नजर विधानसभा चुनाव पर है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग हो रही है। शिवसेना का तर्क है कि उद्धव की सरकार गिराई गई और उसी के नाम पर महायुति के खिलाफ माहौल बना है, इसलिए उद्धव ठाकरे को ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। हाल ही में उद्धव ने इसको लेकर टिप्पणी भी की थी। उद्धव ने कहा था कि सहयोगियों को बताना चाहिए कि मैंने कैसा काम किया था? शिवसेना सांसद संजय राउत के मुताबिक 2019 में महाविकास अघाड़ी ने ही उद्धव को मुख्यमंत्री बनाया था। उद्धव पूरे महाराष्ट्र में लोकप्रिय हैं और उनके मुकाबले का कोई चेहरा एनसीपी और कांग्रेस में नहीं है, इसलिए उद्धव ही चुनाव में चेहरा होंगे। अगर दोनों दलों के पास कोई चेहरा है तो इसे लाएं, हम उनका स्वागत करेंगे। शिवसेना के इस प्रस्ताव पर भले कांग्रेस के हाईकमान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस के लोकल लीडर इसको लेकर तैयार नहीं हैं। कांग्रेस के लोकल लीडर इसके लिए 2019 के ही समीकरण की दुहाई दे रहे हैं। 2019 में सबसे ज्यादा सीट शिवसेना के पास थी, इसलिए शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए। एनसीपी दूसरे नंबर की पार्टी थी तो पार्टी को उपमुख्यमंत्री और गृह-वित्त जैसा महत्वपूर्ण महकमा मिला। तीसरे नंबर वाली कांग्रेस को शिक्षा और राजस्व जैसे विभाग मिले थे।

● **बिन्दु माथुर**

18 दरिंदे और 32 सालों का इंतजार

देश में बीते कई दिनों से चर्चा का विषय बने हुए कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं-लड़कियों के खिलाफ इस तरह के अपराधों को रोकना चाहिए, इसके लिए हम किसी नए मामले का इंतजार नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि 2012 में निर्भया रेप केस के बाद से महिलाओं के साथ रेप के जघन्य अपराध चर्चा के केंद्र में ज्यादा आए और इन पर एक्शन लिया जाने लगा। लेकिन, इससे पहले भी कई ऐसे मामले आ चुके हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन्हीं में से एक मामला था अजमेर रेप एंड ब्लैक मेलिंग केस का, जिसने अजमेर शहर के गौरवशाली इतिहास पर एक काला धब्बा लगा दिया।

कहते हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद से अजमेर शहर की लड़कियों से शादी करने से पहले ये पूछा जाता था कि कहीं उनको भी तो इस केस में ब्लैकमेल नहीं किया गया था? उस वक्त की खबरों की मानें तो हाल ये हो गया था कि लड़कों के माता-पिता शादी के लिए अजमेर की लड़कियों के परिवारों से परहेज करने लगे थे। कोर्ट ने आज इस केस में एक अहम फैसला सुनाया है। इस केस में बचे हुए छह आरोपियों को 32 साल बाद **उम्रकैद** की सजा सुनाई गई है। ये केस इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक इंसान की कोशिश और हिम्मत का असर हो सकता है। साल 1992 के मई महीने का एक साधारण दिन। राजस्थान के अजमेर के एक स्थानीय अखबार में फ्रंट पेज पर एक खबर छपती है। खबर की हेडलाइन थी बड़े लोगों की पुत्रियां ब्लैकमेल का शिकार... इस खबर को देखने के बाद बवाल मच जाता है और फिर परत-दर-परत एक खौफनाक कहानी खुलती है। खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को फार्म हाउस पर बुलाकर रेप करता रहा और उसके बाद उन्हें उनकी अश्लील पिक्चरें दिखाकर ब्लैकमेल किया गया, ताकी वह और लड़कियों को भी लेकर आएं। इस पूरे स्कैंडल का मास्टर माइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती था। उसके साथ कई अन्य आरोपी भी थे।

इन लोगों ने अपने घिनौने इरादों को अंजाम देने के लिए अजमेर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज की लड़कियों को निशाना बनाया। इनमें से एक आरोपी फारूक चिश्ती ने पहले वहां की एक नाबालिग लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया। फिर उसे किसी बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया और वहां उसके साथ रेप किया। लड़की से रेप करने के बाद आरोपियों ने रील कैमरे से उसकी न्यूड तस्वीरें खींच लीं। इसके बाद पीड़िता पर आरोपियों ने इस बात का दबाव बनाया कि वह अपनी सहेलियों को भी वहां पर लेकर आए और फिर शुरू हुआ हैवानियत का सिलसिला। अपने अश्लील तस्वीरों के लीक होने के डर से मजबूर लड़की को मजबूरन अपनी सहेली को भी इस दलदल में धकेलना पड़ा। एक से दो, दो से तीन और ऐसे कर-कर के ना जाने कितनी मासूम लड़कियों से इन दरिंदों ने रेप किया और उनकी नग्न तस्वीरें उतारीं। इसके बाद सबको ब्लैकमेल कर अलग-अलग जगहों पर बुलाने लगे और उनको अपनी हवस का शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में पीड़ित लड़कियों की संख्या 100 से ज्यादा थी। घर वालों की नजरों के सामने से ये लकड़ियां फार्म हाउसों पर जाती थीं। उन्हें लेने के लिए बाकायदा गाड़ियां आती थीं और वापसी में छोड़ने भी आती थीं। ऐसा नहीं था कि पुलिस को इस मामले की भनक नहीं पड़ी, लेकिन क्योंकि ये मामला एक साम्प्रदायिक मोड़ ले सकता था और उस वक्त हालात काफी खराब थे इस वजह से इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई करने से डरती थी।

3 दशक बाद आया फैसला

पीड़ित लड़कियों से पूछताछ और आरोपियों की पहचान के बाद पुलिस ने आठ आरिपियों को गिरफ्तार किया। इस केस का पहला निर्णय छह साल बाद आया, जिसमें अजमेर की अदालत ने आठ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। कुछ समय बाद में कोर्ट ने चार आरोपियों की सजा कम कर दी गई। उन्हें उम्रकैद की बजाय 10 साल जेल की सजा दी गई। इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। लगभग 32 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार इस जघन्य कांड में दोषियों को सजा सुनाई गई जिसका इंतजार पीड़ितों के परिवारों को कब से था। बाकी बचे 7 में से 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए अजमेर की विशेष न्यायालय ने उम्रकैद और पांच लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

धीरे-धीरे इस स्कैंडल के बारे में पूरे शहर को पता चल गया। लड़कियों की अश्लील तस्वीरें वायरल होने लगीं। तस्वीरें वायरल होने के बाद इन लड़कियों को कई और लोगों ने भी ब्लैकमेल किया। इतने लोगों से ब्लैकमेल होने और अकेले इतना सब सहने के बाद एक-एक कर के लड़कियों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। इस तरह 6-7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला संगीन हो गया। ऐसे ही हवा में तैरते हुए एक लड़की की अश्लील तस्वीर एक अखबार के हाथ लगी। तब भरोसा दिलाने और समझाने के बाद छात्राओं ने भी हिम्मत दिखाई और सामने आकर मामला दर्ज करवाया।

एक अखबार के पहले पन्ने पर इस स्कैंडल की खबर छपते ही पूरे अजमेर में बवाल मच गया। इस केस पर सीरीज शुरू होने और खबरों ने पुलिस और प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, खबर के साथ लड़कियों की वह **अश्लील तस्वीरें भी** छाप दीं जिसमें केवल आरोपियों का चेहरा दिख रहा था ताकि छात्राओं के साथ हो रहे यौन शोषण को खुली आंखों से देखा जा सके। फिर, पूरे राजस्थान में कोहराम मच गया और लोग सड़कों पर उतर आए। मामले के इस तरह सामने आने और उसको दबाए जाने के बाद आखिरकार चौतरफा दबाव के बीच 30 मई 1992 को भैरोंसिंह शेखावत ने केस सीआईडी-सीबीआई के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद इस मामले में अजमेर पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू की गई। इस जांच में युवा कांग्रेस के शहर अध्यक्ष फारूक चिश्ती, उपाध्यक्ष नफीस चिश्ती, संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती, अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, सलीम, जमीर, सोहेल गनी, पुत्तन इलाहाबादी, नसीम अहमद उर्फ टार्जन, परवेज अंसारी, मोहिबुल्लाह उर्फ मेराडोना, कैलाश सोनी, महेश लुधानी, पुरुषोत्तम उर्फ जॉन वेसली उर्फ बबना और हरीश तोलानी नाम के अपराधियों के नाम सामने आए।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

मुलायम की गतली सुधारेंगे अखिलेश

आधी-आबादी की पूरी आजादी

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठाने और उन्हें सहायता देने के लिए समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी बनाने की घोषणा की है। ये वर्तमान के संदर्भ में स्त्री-संरक्षणीकरण की नवीन अवधारणा को जन-जन तक ले जाएगी और सद्भावनापूर्ण प्रयासों और समानता के विचारों के प्रसारण से नारी के प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाकर, सामाजिक सोच में आमूलचूल परिवर्तन लाएगी। समाजवादी सबला-सुरक्षा वाहिनी नारी के मुद्दों और मामलों में चार दिन की चिंता की तरह केवल कहकर नहीं रह जाएगी, केवल औपचारिकता नहीं निभाएगी बल्कि बीते कल से सबक लेते हुए वर्तमान को झकझोर कर सचेत बनाएगी। इसमें नारी के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनके आर्थिक सबलीकरण और नारी-सुरक्षा जैसे विषयों के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उनके चतुर्दिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने का अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी।

समाजवादी सबला सुरक्षा वाहिनी रक्षाबंधन के मौके पर अखिलेश यादव ने इस नाम से एक फ्रंट बनाने की घोषणा की है। उनके इस ऐलान के पीछे उनका कामयाब पीडीए वाला फार्मूला है। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर अखिलेश यादव अब समाजवादी पार्टी की एक नई छवि गढ़ने की तैयारी में हैं। कभी गठबंधन के नाम पर तो कभी सोशल इंजीनियरिंग के रूप में अखिलेश यादव राजनीति में प्रयोग करते रहते हैं। इस बार सुरक्षा वाहिनी बनाकर उनकी नजर महिला वोटरों पर है। योगी सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था को लेकर महिलाएं भाजपा के समर्थन में रही हैं। अखिलेश यादव इस ट्रेंड को बदलने के प्रयास में हैं। लड़कों से गलती हो जाती है वाली छवि को किनारे लगाना चाहते हैं।

लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा दिया था। इस नारे के साथ ही उनकी कोशिश एमवाय वाली इमेज को बदलने की थी। लगातार चार चुनाव हार चुके अखिलेश को समझ में आ गया था कि राजनीति बदल चुकी है। मुस्लिम और यादव वोट के दम पर भाजपा को हराना अब नामुमकिन है। भाजपा के **सामाजिक** समीकरण के आगे मुसलमान और यादव वाला एमवाय वोटबैंक पीछे छूट चुका था। इसीलिए उप्र के पूर्व मुख्यमंत्री इस चुनाव में पीडीए फार्मूला लेकर आए। शुरुआत में अखिलेश यादव को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका पीडीए चुनाव की बाजी पलट देगा। इसीलिए वे इसका मतलब बदलते रहे। उन्होंने पी के लिए पिछड़ा और डी के लिए हमेशा दलित शब्द का इस्तेमाल किया। जब भी ए को डिकोड करने की बारी आई, वे गोल पोस्ट बदलते रहे। अखिलेश यादव ने पीडीए में ए को कभी अल्पसंख्यक कहा, तो कभी अगड़ा कहा। कई बार उन्होंने इसे आधी आबादी भी बताया। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी समाज का वोट मिला। दलित वोटरों के एक बड़े हिस्से ने अखिलेश यादव का साथ दिया। मुसलमान तो हमेशा से समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव की नजर अगले विधानसभा चुनाव पर है। वो ये जानते हैं कि समाजवादी पार्टी कभी भी महिलाओं की पहली पसंद नहीं रही। इसकी वजह पार्टी की पुरानी छवि है। भाजपा और बसपा का सबसे बड़ा आरोप एक जैसा है। दोनों ही पार्टियां समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहती रही है। चढ़ गुंडों की छाती पर, मुहर लगेगी हाथी पर। इसी नारे के दम पर बसपा ने समाजवादी पार्टी को हरा दिया था।

कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के रेप के बाद से देशभर के लोग आक्रोश में हैं। उप्र में भी अयोध्या रेप कांड समेत कई घटनाओं में समाजवादी पार्टी के नेता आरोपों के घेरे में हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में समाजवादी पार्टी को डिफेंसिव होना पड़ता है। मुलायम सिंह यादव का विवादित बयान आज भी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ पा रहा है। रेप के एक मामले में उन्होंने कह दिया था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए मुलायम सिंह यादव का ये बयान गले की फांस बन चुका है। अखिलेश यादव जानते हैं कि महिलाओं के समर्थन बिना सत्ता में वापसी असंभव है। सात सालों से अखिलेश यादव उप्र की सत्ता से बाहर हैं। लोकसभा में 37 सीटें पार्टी के हिस्से में आईं। विधानसभा चुनाव साल 2027 में है। इससे पहले अखिलेश यादव आधी आबादी का दिल जीतने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी पत्नी और लोकसभा सांसद डिंपल यादव भी इस मिशन में उनके साथ हैं। फार्मूला बस इतना है कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। इसीलिए सबला सुरक्षा वाहिनी, आधी आबादी की पूरी आजादी का नारा दिया गया है।

अखिलेश यादव का कहना है कि नारी के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उनके आर्थिक सबलीकरण और नारी-सुरक्षा जैसे विषयों के विविध कार्यक्रमों के माध्यम से उनके चतुर्दिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने का अति महत्वपूर्ण कार्य करेगी। नारी में सुरक्षा की भावना उसकी शिक्षा की निरंतरता, उसकी कुशलता-समर्थता, सक्रियता व आत्मनिर्भरता और परिवार-समाज में सम्मान के साथ जीने का सुदृढ़ आधार बनती है। नारी जितनी सुरक्षित होगी, उतनी ही उसकी सक्रियता बढ़ेगी और उतना ही उसका आर्थिक योगदान बढ़ेगा और साथ ही उसका पारिवारिक-सामाजिक सम्मान भी और देश-दुनिया के विकास में योगदान भी। उन्होंने कहा कि ये आधी-आबादी की पूरी आजादी का अभियान है, जिसके शुभारंभ के लिए रक्षाबंधन जैसे पावन-पर्व से अच्छा अन्य कोई पर्व और क्या हो सकता है, लेकिन ये कोई एक दिन का पर्व नहीं होगा, बल्कि हर पल, हर जगह, हर दिन सक्रिय रहने वाली जागरूकता का रूप होगा। जो नारी को सुरक्षित रखते हुए, आर्थिक रूप से सशक्त करते हुए एक बड़े सामाजिक-मानसिक बदलाव की ओर ले जाएगा। अखिलेश ने कहा कि हमारा संकल्प-सिद्धांत है- स्त्री शक्ति का प्रतीक भी होनी चाहिए और प्रमाण भी। इसलिए समाज के सभी वर्गों और तबकों की स्त्री-शक्ति से आव्हान और अनुरोध है कि वे समाजवादी सबला-सुरक्षा वाहिनी से जुड़ने के लिए आगे आएं और अपनी कुशलता व हुनर से अन्य स्त्रियों को आर्थिक-सामाजिक रूप से समर्थ-सबल बनाने में अपना योगदान दें।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

नीतीश कुमार के कारण डिमोशन

लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सम्राट चौधरी के हटाए जाने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कारण है, वो उनका नीतीश कुमार से बेहतर तालमेल का न होना है। बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी को नीतीश का विरोधी नेता माना जाता है। राजनीतिक जानकारों के गुणा-गणित से इतर बिहार भाजपा के पहले भी कई ऐसे नेता रहे हैं, जिन्हें नीतीश कुमार की वजह से हाईकमान ने शंट कर दिया। इनमें कुछ नेता बाद के दिनों में सियासत में असरदार हुए तो कुछ नेपथ्य में चले गए।

2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उसमें भाजपा कोटे से चंद्रमोहन राय को शामिल किया गया। राय को स्वास्थ्य मंत्रालय की कमान सौंपी गई। शुरुआत में राय के लिए सबकुछ ठीक था, लेकिन 2007 के आसपास वे नीतीश के निशाने पर आ गए। 2008 में नीतीश कुमार ने जब कैबिनेट का फेरबदल किया तो उससे राय को ड्रॉप कर दिया गया। राय की रुखसती ने बिहार भाजपा के भीतर बवाल मचा दिया। दिल्ली तक यह विवाद पहुंचा, लेकिन हाईकमान ने मामले को शांत करा दिया। राय इसके बाद राजनीति के नेप्थय में ही रह गए। उन्हें न तो बिहार कैबिनेट और न ही देश की राजनीति में कुछ बड़ा पद मिला। साल 2015 में राय को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया।

2010 के विधानसभा चुनाव से पहले सीपी ठाकुर को भाजपा की कमान मिली। उस वक्त भाजपा-जेडीयू के साथ गठबंधन में थी। सीट बंटवारे के दौरान सीपी ठाकुर और नीतीश कुमार के बीच तल्खी आ गई, जिसके बाद नीतीश ने सीधे भाजपा हाईकमान से संपर्क किया। हाईकमान ने समझौते के तहत नीतीश को पटना की दीघा सीट दे दी। इससे नाराज होकर चुनाव के बीच ही सीपी ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि ठाकुर ने यह इस्तीफा प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत दिया था, लेकिन नीतीश टस से मस नहीं हुए। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबर्दस्त जीत मिली। नीतीश कुमार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। कयास लगाया जा रहा था कि ठाकुर को सरकार में कोई बड़ा पद मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के साथ ही काम करने की इच्छा जताई। हाईकमान ने उनकी बात मान ली और सीपी ठाकुर संगठन में ही रह गए। एक वक्त भाजपा के कद्दावर नेता रहे गोपाल नारायण सिंह को भी भाजपा ने सम्राट की तरह ही शंट कर दिया था। दरअसल, साल 2005 में विधानसभा के चुनाव होने थे। भाजपा की तरफ से गोपाल नारायण सिंह अध्यक्ष थे। पार्टी के भीतर और बाहर उन्हें ही चेहरा बताया जा रहा था, लेकिन चुनाव से 3 महीने पहले ही उन्हें पद से हटा दिया। सिंह के बदले सुशील मोदी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में भाजपा और जेडीयू की सरकार बनी और सुशील मोदी उपमुख्यमंत्री बनाए गए। गोपाल नारायण सिंह तब तक शंटिंग जोन में रहे, जब तक भाजपा और जेडीयू की सरकार थी। साल 2016 में भाजपा ने गोपाल नारायण सिंह को राज्यसभा भेजा। राज्यसभा सांसद बनने के बाद सिंह नीतीश पर काफी मुखर रहे।

लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भाजपा नेताओं के सुर अचानक बदल गए हैं। जनवरी से पहले नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने तक पगड़ी बांधे रहने की सौगंध खाने वाले (जनवरी में गठबंधन के बाद उन्होंने इसके कारण भी बताए) उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नतीजे के बाद कहा- हम नीतीश के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेंगे। हम 1996 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी के सरेंडर के बाद भाजपा के प्रदेश स्तर के सभी छोटे-बड़े नेता ये स्वीकार करने लगे कि नीतीश ही उनके नेता हैं और आगे भी रहेंगे। सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में **अटकलों** का बाजार गर्म है कि आखिर लोकसभा चुनाव के नतीजे के तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने विधानसभा चुनाव में नेता का मुद्दा क्यों उठाया? जबकि, चुनाव में डेढ़ साल का समय बाकी है। दरअसल इसका जवाब लोकसभा चुनाव नतीजों के आंकड़े में है। इस नतीजे के बाद भाजपा के सामने नीतीश कुमार को नेता मानने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। लोकसभा चुनाव से लगभग डेढ़ साल पहले अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ने की बात करने वाली भाजपा अभी तक बिहार में आत्मनिर्भर नहीं हो पाई है। वहीं, दूसरी तरफ अभी भी नीतीश कुमार बिहार के स्वीकार्य नेता हैं।

लोकसभा चुनाव को देखें तो सीट और वोट शेयर के हिसाब से जदयू को 4 सीटें तो भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर बात वोट शेयर की करें तो भाजपा को 1 प्रतिशत और जदयू को 3.5 प्रतिशत वोट शेयर का नुकसान हुआ है। अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों के ट्रेंड को विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट करें तो चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर इसी ट्रेंड पर विधानसभा के नतीजे आए तो 15 साल बाद जदयू एक बार फिर से बिहार विधानसभा में सबसे ताकतवर पार्टी के रूप में उभर सकती है। वहीं, सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए में भाजपा को और महागठबंधन में राजद को होते हुए दिख रहा है।

● **विनोद बक्सरी**

नीतीश के बिना नैया पार नहीं लगेगी

जानकार कहते हैं कि नीतीश को नेता मानने की सबसे बड़ी वजह ये है कि भाजपा ये मानकर चल रही थी कि वो लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन न वे बिहार में अच्छा कर सके और न ही केंद्र में अपने दम पर बहुमत हासिल कर सके। भाजपा के कई बड़े नेता और मंत्री भी अपनी सीट खो दिए। इसके बाद अब इन्हें ये समझ आ रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार के बिना इनकी नैया पार होने वाली नहीं है। इसलिए नीतीश अब इनके लिए मजबूरी बन गए हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जो सामाजिक समीकरण निकलकर सामने आए हैं, उसमें भाजपा के उस दंभ की हवा निकल गई है, जिसमें वे अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। लोकसभा में अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ती तो बिहार में उसके परिणाम और बुरे हो सकते थे। चुनाव में जदयू का स्ट्राइक रेट भी भाजपा से अच्छा रहा है।

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

तालिबानी कुशासन के तीन साल

अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान को लौटे तीन साल हो गए हैं, लेकिन इस दौरान वे कई मोर्चों पर बुरी तरफ विफल साबित हुए हैं। तालिबानी शासन महिलाओं के दमन, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बिगड़ते संबंधों और अंतरराष्ट्रीय मान्यता के लिए निरर्थक संघर्ष के लिए पहचाना जाता रहा है। यही नहीं, तालिबानी शासन अफगान लोगों के लिए एक दु:स्वप्न की तरह है। काबुल में तालिबानी शासन को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिसने उसके गवर्नेंस मॉडल की सीमाओं को उजागर कर दिया है। इन मुद्दों को सुलझाने की उसकी क्षमता ही अफगानिस्तान की भावी स्थिरता और सत्ता में तालिबान की दीर्घजीविता को निर्धारित करेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग होना, आर्थिक संकट, सुरक्षा जोखिम और आंतरिक विभाजन उसके लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं, जिनसे आने वाले वर्षों में तालिबान को निपटना होगा। अगस्त, 2021 में काबुल पर कब्जा करने के बाद विभिन्न चुनौतियों ने उनके शासन और राजनीतिक वैधता की परीक्षा ली है। सत्ता में तीन साल रहने के बाद भी तालिबान के सामने कई प्रमुख मुद्दे बरकरार हैं।

तालिबान सरकार को अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने अभी तक मान्यता नहीं दी है, जिससे औपचारिक राजनयिक संबंध बनाने और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों तक पहुंचने में उसे मुश्किल हो रही है। अफगानिस्तान विदेशी सहायता पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो तालिबान के सत्ता में आने के बाद से काफी कम हो गई है। प्रतिबंधों, खासकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावित किया है। महिला अधिकारों पर तालिबान की प्रतिबंधात्मक नीतियों, खासकर एक निश्चित उम्र के बाद लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध, की व्यापक निंदा हुई है, जिसने शासन को वैश्विक समुदाय से अलग-थलग कर दिया है। इससे घरेलू अशांति और असंतोष भी बढ़ा है। तालिबान द्वारा सख्त शरिया कानून लागू करने से मानवाधिकारों के हनन की चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसमें सार्वजनिक रूप से फांसी देना और अंग-भंग करना शामिल है। इन प्रथाओं की वैश्विक स्तर पर आलोचना की गई है और इससे अफगान आबादी में डर और आक्रोश पैदा हुआ है। अफगान अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। बैंकिंग प्रणाली ढहने के कगार पर है और देश में नकदी की भारी कमी है। व्यापक बेरोजगारी और गरीबी ने मानवीय संकट को जन्म दिया है। कई अफगान लोग बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं और खाद्य असुरक्षा व्याप्त है। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसआईएस-के) लगातार खतरा बना हुआ है, जो पूरे मुल्क में घातक हमले कर रहा है। इन हमलों से तालिबान की सुरक्षा क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। तालिबान के भीतर भी मतभेद हैं, जिसमें अलग-अलग गुट सत्ता के लिए होड़ कर रहे हैं। ये विभाजन अंदरूनी कलह को जन्म दे सकते हैं और उनके नियंत्रण को अस्थिर कर सकते हैं।

अफगानिस्तान अफीम का एक प्रमुख उत्पादक है, और तालिबान पर नशीली दवाओं के व्यापार से मुनाफा कमाने का आरोप लगाया गया है। इसने अंतरराष्ट्रीय जांच और प्रतिबंधों को भी आकर्षित किया है। हालांकि तालिबान ने अफीम उत्पादन पर अंकुश लगाने की कसम खाई है, लेकिन अवैध अर्थव्यवस्था अब भी फल-फूल रही है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं, खासतौर पर सीमा मुद्दों और अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान (टीटीपी) की मौजूदगी के कारण। इसी तरह, ईरान के साथ रिश्ते सांप्रदायिक मतभेदों और जल विवादों के कारण जटिल हैं। तालिबान ने चीन और रूस के साथ संबंध बनाने की कोशिश की है, लेकिन दोनों के ही अफगानिस्तान में रणनीतिक हित हैं। इसलिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं को लेकर संशय है। हालांकि किसी भी अरब देश ने तालिबान को अब तक मान्यता नहीं दी है, लेकिन वे तालिबान शासन के साथ व्यावहारिक रूप से जुड़े हुए हैं, मानवीय सहायता प्रयासों के साथ क्षेत्रीय स्थिरता संबंधी चिंताओं को संतुलित कर रहे हैं।

अफगानिस्तान दुनिया के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है, जहां लाखों लोग भूख और ढहती स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का सामना कर रहे हैं। तालिबान इन मुद्दों को हल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहायता संगठनों पर निर्भर है। कई अफगान भागकर पड़ोसी देशों में या यूरोप चले गए हैं। इस प्रतिभा पलायन ने देश में सुधार की संभावनाओं को और कमजोर कर दिया है। तालिबान के केंद्रीयकृत शासन मॉडल में सत्ता कुछ ही नेताओं के हाथों में केंद्रित है, जिससे अक्षमता और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। इससे पूरे देश में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना मुश्किल हो गया है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

तालिबान के साथ भारत के रिश्ते

तालिबान के साथ भारत के रिश्ते जटिल हैं और भारत सतर्कतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। भारत ने अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों का समर्थन किया है और पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों के साथ तालिबान के रिश्तों को लेकर चिंतित है। हालांकि, भारत सरकार सावधानीपूर्वक तालिबान के संबंध बनाए हुए है, अफगानिस्तान की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश सहित उसके हितों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित करने की इच्छा से भारत की भागीदारी सीमित है। तालिबानी शासन ने अफगानिस्तान को फिर से अंधकार युग में धकेल दिया है, जहां महिलाओं को उनकी दमनकारी नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने में तालिबान की असमर्थता ने मुल्क को अलग-थलग करके आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया है। कभी तालिबान का समर्थन करने वाले पाकिस्तान से भी उनके रिश्ते बिगड़ गए हैं, जिससे परेशानियां बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर, तालिबान वैधता के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसका शासन अत्याचार और विफलता का प्रतीक बना हुआ है। दुनिया देख रही है कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान अराजकता और निराशा में डूब रहा है, और बेहतर भविष्य की कोई उम्मीद नहीं है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफगान लोगों, खासकर महिलाओं के साथ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, जिन्होंने इस क्रूर शासन का खामियाजा भुगता है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर एक सभा के दौरान हुए हमले के कुछ ही दिन के भीतर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस साल के आखिर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार बन गई हैं। लंबी खामोशी के बाद आखिर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा ने हैरिस की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दे दिया। क्या ओबामा की खामोशी के पीछे कारण यह था कि बाइडेन को रेस से बाहर कर वह अपनी पत्नी मिशेल ओबामा को राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार बनाना चाहते थे? परदे के पीछे ऐसी चर्चा खूब रही थी।

पेंसिल्वेनिया में एक रैली को संबोधित करते हुए जब एक हमलावर की गोली ट्रम्प के कान को छूने के बाद उनके चेहरे पर खून की एक लकीर छोड़ते हुए निकल गई, तो भले यह ट्रम्प के जीवन को संकट में डालने वाला क्षण था; लेकिन ट्रम्प ने इसे राजनीतिक रूप से भुनाने में देर नहीं की। चेहरे पर खून की इस लकीर के साथ भिंची हुई मुट्ठी जब उन्होंने अपने समर्थकों की तरफ लहराई, उस समय सीक्रेट सर्विस के अधिकारी ढाल बनाकर उन्हें सुरक्षित स्थान की तरफ ले जा रहे थे। ट्रम्प की यह तस्वीर दुनियाभर के अखबारों और टीवी चैनलों ने बार-बार दिखाई। कोई शक नहीं कि सिर्फ इस एक तस्वीर ने ट्रम्प के प्रति अमेरिका में समर्थन का जबरदस्त माहौल बना दिया। लेकिन क्या यह माहौल स्थायी है? शायद नहीं। जो बाइडेन के डिबेट्स में कमजोर प्रदर्शन और उनकी भूलने की आदत ने ट्रम्प को बढ़त के पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया। चिंतित डेमोक्रेट्स यह चर्चा करने लगे कि क्या बाइडेन के साथ वह ट्रम्प को हराने की कल्पना कर सकते हैं? अधिकतर का जवाब न में था। बाइडेन को मैदान से बाहर करने की मुहिम के सबसे बड़े पैरोकार पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। भले वह ट्रम्प की मजबूती को देखते हुए बाइडेन को उम्मीदवारी से हटाने की मुहिम चला रहे थे; इसके पीछे एक मकसद पत्नी मिशेल ओबामा के लिए पद की उम्मीदवारी की संभावना बनाना भी था। मिशेल का नाम पहले भी दो बार डेमोक्रेटिक पार्टी में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए चर्चा में रहा है। लिहाजा ओबामा की कोशिश आश्चर्यजनक नहीं थी। लेकिन इस बीच बाइडेन ने अचानक अपना नाम राष्ट्रपति की उम्मीदवारी से वापस ले लिया। यही नहीं, उन्होंने पद के लिए कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन कर दिया। बाइडेन खेमे में ओबामा के प्रति नाराजगी थी। लिहाजा ऐसा करने से ओबामा की कोशिशों को धक्का लगा। इसके बावजूद एक हफ्ते तक ओबामा ने हैरिस के नाम का समर्थन नहीं किया, जबकि तब तक पार्टी के ज्यादातर बड़े नेता हैरिस के समर्थन की घोषणा कर चुके थे। लेकिन अब कमला हैरिस ही डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उमीदवार हैं।

कमला हैरिस को मतदान के पहले दौर में नामांकन जीतने के लिए जरूरी 1,976 प्रतिनिधियों से ज्यादा का समर्थन हासिल हुआ जिससे पहले ही साफ हो गया था कि हैरिस नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वास्तव में यह रोल कॉल वोट कहलाता है। हैरिस को अगस्त में शिकागो में हुई डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में पूरा समर्थन मिल गया। राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस के विरोधी के रूप में सामने आने से डोनाल्ड ट्रम्प के पक्ष में जो माहौल बना था, उसमें कमी आई है। उम्मीदवारी लगभग पक्की होने के बाद इजरायल के गाजा में हमलों में मरने वाले बेकसूर लोगों को लेकर जिस तरह कमला हैरिस ने कड़ा रुख दिखाया है, उससे अमेरिका में उनका समर्थन बढ़ सकता है। ट्रम्प जिस तरह जो बाइडेन की उम्र (83 साल) को लेकर सवाल उठा रहे थे, अब केवल 59 साल की हैरिस यही सवाल ट्रम्प (79) की उम्र को लेकर उठा रही हैं। ट्रम्प के कोर्ट में चल रहे मामले भी हैरिस के लिए एक मुद्दा हैं। अमेरिका में यह सवाल उठाया जा रहा है कि यदि इन मामलों में दोषी पाए जाने पर ट्रम्प को सजा मिलती है, तो क्या होगा? कमला के राष्ट्रपति उम्मीदवार होने से बड़ी संख्या में भारतीय भी उनके साथ जा सकते हैं।

कमला हैरिस की विदेश मामलों में जानकारी को लेकर रिपब्लिकन सवाल उठा रहे हैं। यदि व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर कमला हैरिस के पेज को देखा जाए, तो पता चलता है कि एक उपराष्ट्रपति के तौर पर कमला हैरिस ने पिछले साढ़े तीन साल के कार्यकाल के दौरान डेढ़ दर्जन देशों का दौरा किया। इस दौरान कमला ने 150 से ज्यादा विदेशी नेताओं से मुलाकात-बैठकें कीं। रिपब्लिक के विरोध के बावजूद अमेरिका में कई लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में कमला हैरिस की नीतियां वास्तव में अब सामने आएंगी। इनमें से कई जानकार कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के रूप में भूमिका के विपरीत अब कमला की छवि कहीं ज्यादा मजबूत नेता के रूप में सामने आ सकती है। अमेरिकी चुनाव पर बाहरी देशों- रूस, चीन और भारत की नजर है। यह माना जाता है कि रूस की प्राथमिकता अपने हित देखने की रहेगी। डोनाल्ड ट्रम्प के पिछले कार्यकाल को लेकर रूस में निराशा ही अनुभव की गई थी। यूक्रेन में रूस के हमले के बाद ट्रम्प लगभग खामोश रहे। कारण था- जो बाइडेन का राष्ट्रपति पुतिन को किलर कहना।

● **कुमार विनोद**

हैरिस मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशील नेता

हाल के वर्षों में बाइडेन प्रशासन भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के प्रति मोदी प्रशासन की नीतियों को लेकर सवाल उठाता रहा है। कमला हैरिस को मानवाधिकारों के प्रति बहुत संवेदनशील नेता माना जाता है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि ट्रम्प की जीत मोदी प्रशासन को ज्यादा रास आएगी, बनिस्बत हैरिस के। जहां तक कमला हैरिस के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी में उपराष्ट्रपति पद के संभावितों की बात है, इनमें जोश शापिरो (पेंसिल्वेनिया के गवर्नर), मार्क केली (एरिजोना के सीनेटर), रॉय कूपर (उत्तरी कैरोलिना गवर्नर), एंडी बेशर (केंटकी के गवर्नर) जेबी प्रिटजकर (इलिनोइस के गवर्नर), ग्रेचेन व्हिटमर (मिशिगन के गवर्नर), परिवहन सचिव पीट बटिगिएग, टिम वाल्ज (मिनेसोटा के गवर्नर), सेवानिवृत्त एडमिरल विलियम मैकरेवन के अलावा मैरीलैंड के गवर्नर वेस मूर, सीनेटर एमी क्लोबुचर, कोरी बुकर और जॉर्जिया के सीनेटर राफेल वारनॉक के नाम चर्चा में हैं।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

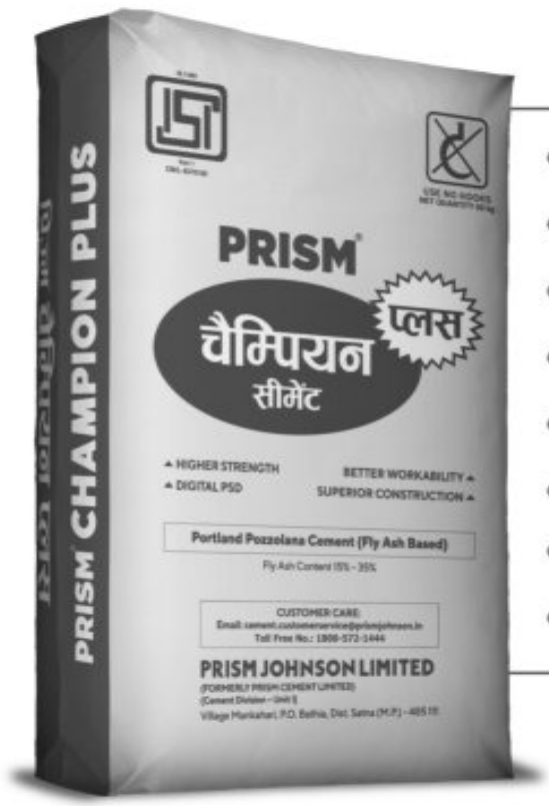

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

अंधेरों से आगे

आंख में उमड़ते आंसू थमने का नाम न ले रहे थे। परिचितों को देखकर मन की संवेदनाएं और मुखर हो उठी थीं। एकलौते युवा प्रबंधक बेटे की दुर्घटना में हुई मौत उसे बेसहारा कर गई थी। सुखद भविष्य के सपने दिखाकर ईश्वर ने उसे कहां ला पटका था?

उसके स्कूल की टीचर्स के जाने के बाद, प्रिंसिपल मैम उसके पास आकर धीरे से बोलीं, एक बहन के नाते आपसे कह रही हूं, जीना तो नियति है- हंस के जियो या रोकर जियो। घर रहोगी तो कोई न कोई आकर दिनभर रुलाता रहेगा। पर स्कूल में बच्चों के बीच रहकर आप अपना दुख भुलाकर मन शांत कर पाएंगी। मन करे तो क्लास लेना। पर कोशिश करना अधिक से अधिक समय बच्चों के बीच रहना। यही आपको डिप्रेशन से दूर रखने के लिए एकमात्र उपाय है। यदि मेरी बातें कुछ ठीक लगें, तो सोमवार से स्कूल आ जाइएगा।

प्रिंसिपल मैम के जाने के बाद वह सोचती रही। उसे लगा कि मैम ठीक कह रही थीं। घर में अकेले रहकर या लोगों के आने पर बेटे को बार-बार याद कर वह और टूटती चली जाएगी। बच्चों के बीच रहकर शायद वह अपने को संभाल पाए।

सोमवार को वह अनमने मन से स्कूल चली गईं। प्रार्थना सभा के पश्चात वह सोच ही रही थी कि कहां जाए? तभी उसकी कक्षा के दो बच्चे दीक्षा व राजेश उसके पास आए। उसके पैर छुए व बोले, मैम हम भी तो आपके ही बच्चे हैं। क्या आप हमें पढ़ाकर अपने बेटे जैसा होनहार नहीं बनाएंगी?

वह दोनों को देखती रह गई। उसे लगा कि उसके सामने उसकी पोती व पोता खड़े हैं, जो उससे कह रहे हैं कि हमारे पापा तो हमें आपके सहारे छोड़ गए। अब आप ही हमें पढ़ा लिखाकर पापा जैसा बनाएं। दादी, बोलो बनाओगी ना।

उसकी सोई ममता जाग उठी। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया और वह एक नए विश्वास के साथ उन बच्चों को लेकर क्लास रूम की ओर बढ़ गई।

- विष्णु सक्सेना

कल फिर मिलेंगे

हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे
अपनी कहेंगे तो, कुछ उनकी सुनेंगे
जिंदगी में फिर से, नए रंग भरेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
झटका जरूर, हम सबको, लगा है
नियमों के, खेल में, मेडल फंसा है
दिल न, करो छोटा, इससे उबर लेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
आंखें तो हम, सबकी ही, नम हैं
सबके अपने, अलग-अलग, ग़म हैं
भावनाओं के ज्वार, निर्बाध बहेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
पल भर में सब, उम्मीद, टूट जाती
सालों की मेहनत, न रंग ला पाती
हौंसले फिर भी हम, न टूटने देंगे
हो सका तो हम, कल फिर मिलेंगे।
जीत हार, जीवन का, अहम अंग है
आपकी हार से, हर कोई, दंग है
आपके संघर्ष, नए किस्से, गढ़ेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
कभी-कभी किस्मत, रूठ जाती है
जीत भी, हार का, मुंह दिखाती है
सिलसिले, जीवन के, यूं ही चलेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
प्रयासों में आपके, कमी नहीं थी
दांव पेंचों, की गति, थमी नहीं थी
टेढ़े-मेढ़े रास्तों पर, फिर से चलेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
किसको पता कल, क्या होने वाला
कौन हंसने और, कौन रोने वाला
जीवन के, काफिले, यूं ही चलेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।
जीवन के काफिले, यूं ही चलेंगे
हो सका, तो हम, कल फिर मिलेंगे।

- नवल अग्रवाल

भूख

रास्ते पर चल रही महिला की सोने की चेन खींचकर एक हट्टे-कट्टे बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस कांस्टेबल ने उसका पीछा किया। वह बदमाश सड़क पार करके तंग गली में घुस गया। लगातार उसका पीछा करते-करते कांस्टेबल थक गया, पर बदमाश उसके हाथ नहीं आया। वह पसीने से लथपथ हो गया। इतने में गली के नुक्कड़ पर झुग्गी से एक आदमी निकला। नुक्कड़ पर उसने लगड़ी मारी। बदमाश नीचे गिर गया। गिरते ही उस बदमाश को धर दबोचा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। सबको यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक दुबले-पतले इंसान ने हट्टे-कट्टे बदमाश को पकड़ लिया, जिसे पुलिस नहीं पकड़ सकी। सब तालियां बजाने लगे। महिला ने उसे आशीर्वाद दिया। जब वह अपनी झुग्गी में पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, च्च्आपको डर नहीं लगता?

उसने अपनी झुग्गी में औंधे पड़े बर्तनों को देखकर उत्तर दिया, मुझे किसी से डर नहीं लगता सिवाय एक चीज के- भूख।

- डॉ अनीता पंडा 'अन्वी'

चुनावी अखाड़े में दांव आजमाएंगे कई खिलाड़ी

खेलों के दंगल में विरोधियों को धूल चटाने वाले हरियाणा के छह से अधिक खिलाड़ी इस बार विधानसभा चुनाव की सियासी पिच पर दम दिखा सकते हैं। अलग-अलग दल अलग-अलग खिलाड़ियों को साधने में जुटे हैं। ओलंपियन बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और पहलवान साक्षी मलिक पर कांग्रेस की नजर है। खुद सांसद दीपेंद्र हुड्डा लंबे समय से दोनों ही खिलाड़ियों के संपर्क में हैं। बजरंग पूनिया झज्जर से ताल्लुक रखते हैं और विनेश फोगाट बाढड़ा हलके की रहने वाली हैं। हालांकि, अभी तक दोनों खिलाड़ियों ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वहीं, पिछले चुनाव में भाजपा के टिकट पर तीन ओलंपियन खिलाड़ियों ने किस्मत आजमाई थी। ये एक बार फिर से टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं।

ओलंपियन योगेश्वर दत्त 2019 में बरोदा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। बरोदा उपचुनाव में भी उन्होंने भाजपा से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार ओलंपियन खिलाड़ी बबीता फोगाट ने चरखी दादरी से भाजपा के टिकट पर विधानसभा 2019 का चुनाव लड़ा था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी सोमबीर सांगवान ने उनको हरा दिया था। हॉकी के पूर्व कप्तान संदीप सिंह भाजपा के टिकट पर पिहोवा से विधायक चुने गए और मनोहरलाल सरकार में मंत्री भी बने। ये तीनों ही खिलाड़ी फिर से अपने-अपने हलकों में सक्रिय हैं और टिकट के लिए मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। पूर्व खेलमंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली जूनियर महिला कोच ने कांग्रेस से पिहोवा विधानसभा सीट से टिकट मांगा है। वह संदीप सिंह के खिलाफ विधानसभा चुनाव में ताल ठोकना चाह रही हैं। बॉक्सिंग से राजनीति की दुनिया के कदम रखने वाले विजेंदर सिंह अब भाजपा के हो चुके हैं। 2019 में उन्होंने साउथ दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्होंने 2019 में ही कांग्रेस जॉइन की थी। विजेंदर सिंह जाट समुदाय से आते हैं, जिसका हरियाणा, पश्चिमी उप्र और राजस्थान में बड़ी संख्या में राजनीतिक प्रभाव है। वहीं, अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनावों से पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था।

भारत में क्रिकेट केवल खेल नहीं, धर्म की तरह है। यहां क्रिकेट की दीवानगी लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। कुछ क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान की तरह पूजा जाता है। क्रिकेट मैच के दौरान सड़कें खाली हो जाती हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं और पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है। लोगों के बीच क्रिकेटरों की इसी लोकप्रियता को भुनाने के लिए गाहे-बगाहे राजनीतिक दल क्रिकेटरों को चुनावी मैदान में उतार देते हैं। कई बार इन्हें सफलता मिलती है, तो कई बार ये क्लीन बोल्ड भी हो जाते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के ऑफ-ब्रेक गेंदबाज यूसुफ पठान को टिकट दिया था। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से हुआ जिन्हें उन्होंने हरा दिया। देश में सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने 1971 में विशाल हरियाणा पार्टी के माध्यम से राजनीति में प्रवेश किया, जो अब अस्तित्व में नहीं है। पटौदी ने 1971 और 1975 में दो संसदीय चुनाव लड़े और दोनों हार गए। यानी क्रिकेटरों की चुनावी पिच पर पारी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली सीट से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 3.91 लाख मतों के अंतर से शानदार सफलता हासिल की। हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने दावेदारी पेश नहीं की। गंभीर का कहना है कि वो भविष्य में क्रिकेट को अधिक महत्व देना चाहते हैं। क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2004 में भाजपा में आने के साथ की थी। 2004 लोकसभा चुनाव में सिद्धू अमृतसर सीट से जीतकर लोकसभा में पहुंचे। इसके बाद 2007 में उपचुनाव और 2009 में भी उन्होंने चुनाव जीता। लेकिन पार्टी में अंदरूनी मतभेदों के कारण उन्होंने 2016 में पार्टी का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। भारत ने 1983 में पहला क्रिकेट विश्वकप जीता। इस टीम में कीर्ति आजाद भी थे। कीर्ति ने क्रिकेट छोड़ने के बाद राजनीति में कदम रखा था। वे दरभंगा लोकसभा सीट से तीन बार भाजपा सांसद बने, लेकिन 2019 में कांग्रेस का दामन थाम लिया। अब वे तृणमूल कांग्रेस के साथ आ गए हैं।

चेतन चौहान ने 1991 में चुनावी पिच पर उतरने का फैसला किया। वे 1991 के लोकसभा चुनाव में अमरोहा से भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे। अपने पहले ही चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद साल 1996 के चुनाव में चेतन चौहान को हार मिली। साल 1998 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया। इस बार अमरोहा की जनता ने उन्हें निराश नहीं किया और फिर लोकसभा भेजा। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उप्र के अमरोहा की नौगांव सीट से जीत हासिल की थी और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का हिस्सा बने।

● आशीष नेमा

अजहर कांग्रेस के साथ

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने साल 2009 में कांग्रेस का हाथ थामा था। 2009 लोकसभा चुनाव में उन्हें उप्र की मुरादाबाद सीट से जीत मिली, लेकिन 2014 के चुनावों में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। उन्होंने पिछले साल तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जुबली हिल्स क्षेत्र से दावेदारी पेश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन शर्मा ने 2009 लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की ओर से फरीदाबाद सीट पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। उसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। एस श्रीसंत साल 2016 में केरल विधानसभा चुनाव में तिरुवनंतपुरम की सीट से दावेदारी पेश करने के कारण सुर्खियों में आए थे। उन्हें भाजपा का साथ मिला था, लेकिन चुनावी मैदान में उन्हें हार झेलनी पड़ी थी। मोहम्मद कैफ ने 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए उप्र की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वे अपने पहले ही चुनावी मैच में हार गए। मनोज तिवारी ने 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की ओर से शिवपुर सीट पर जीत हासिल की थी। वे इस समय पश्चिम बंगाल सरकार में खेल मंत्री हैं। हरभजन सिंह ने 2021 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया था और वे अभी आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। विनोद कांबली ने 2009 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लोक भारती पार्टी की ओर से विखरोली सीट पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी थी।

मुन्ना भैया नहीं होते दिव्येंदु शर्मा, अगर इस एक्टर ने नहीं कहा होता न... एसपी बन लूट ले गया महफिल

अमेजन प्राइम की सबसे हिट वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर का हर एक किरदार लोगों को काफी पसंद है। सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और इन तीनों सीजन से स्टार्स को दर्शकों का वही प्यार देखने को मिला। शो के एक किरदार मुन्ना भैया को भला कौन भूल सकता है। क्या आप जानते हैं मुन्ना भैया के लिए दिव्येंदु शर्मा पहली पसंद नहीं थे।

हिंदी फिल्मों के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। हम अमर हैं। पॉवर अगर दूसरे के नाम से हो तो अपनी नहीं होती बे... इन डायलॉग्स के साथ लोगों के दिलों में खास छवि बनाने वाले दिव्येंदु शर्मा मुन्ना भैया सिर्फ उस एक्टर की वजह से बन पाए, जिन्होंने इस रोल के लिए मना किया।

दिव्येंदु शर्मा से पहले मुन्ना भैया का रोल जामताड़ा फेम एक्टर अमित सियाल को ऑफर किया गया था। एक इंटरव्यू में अमित सियाल ने इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा- मिर्जापुर में जो मुन्ना का किरदार है, वो मुझे ऑफर हुआ था। लेकिन ऑब्वियसली मैं पंकज का बेटा तो

लग नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने रोल के लिए न किया।

एक्टर ने कहा कि मैं इसके लिए बहुत खुश हूं कि मैंने वो किया जो मुझे लगता था कि मेरे लिए ठीक है और मुझे लगता है कि वो एक क्लासिक कैरेक्टर बन गया है। दिव्येंदु की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि दिव्येंदु ने उस किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया है। अमित सियाल ने भले ही मिर्जापुर में मुन्ना भैया का किरदार ना निभाया हो, लेकिन उन्होंने इसी सीरीज में एक दूसरा रोल किया है जो कि काफी हिट रहा। उन्होंने इसमें एसपी राम शरण मौर्या का किरदार निभाया था, जिसे मिर्जापुर का केस दिया जाता है। पहले सीजन में अमित नजर आए थे और उन्होंने इस किरदार को बेहद खूबसूरती से निभाया था। अमित महारानी, जमताड़ा, तितली, वीर सवारकर समेत कई फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ चुके हैं।

1981 की वो फिल्म जो 96 दिनों तक रही हाउसफुल, 67 सप्ताह सिनेमाघरों में चली

आज से 43 साल पहले एक ऐसी बॉलीवुड फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसमें 4 सुपरस्टार दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा ने मिलकर बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था। उस फिल्म का नाम था क्रांति। विकिपीडिया के अनुसार, फिल्म क्रांति को इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि यह 67 सप्ताह तक सिनेमाघरों में चली थी और 96 दिनों तक हाउसफुल रही थी। दर्शकों ने इस फिल्म पर जमकर अपना प्यार लुटाया था। बता दें, 80 के दशक में दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज अभिनेताओं की इंडस्ट्री में एक अलग पहचान थी और जब ये चारों सुपरस्टार एक साथ क्रांति में नजर आए थे, तो सिनेमाघरों में लोग झूम उठे थे। यह साल 1981 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी।

डेब्यू करते ही साइन की 107 फिल्में, धर्मेंद्र और गोविंदा का भी हिल गया था स्टारडम

80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक ऐसे एक्टर ने इंडस्ट्री में कदम रखा, जिसे देखने सलमान खान और संजय दत्त जैसे स्टार भी आया करते थे। डेब्यू करते ही इस एक्टर ने धमाल मचा दिया था। गोविंदा और धर्मेंद्र ने तो इस एक्टर के साथ काम करने से भी मना कर दिया था। जबरदस्त पर्सनेलिटी और सुपरफिट बॉडी के जबरदस्त कॉम्बिनेशन के साथ धमाकेदार एक्टिंग टैलेंट भी ये सारी खूबियां थीं, साल 1985 में आई फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले एक्टर हेमंत बिर्जे में। हेमंत की डेब्यू फिल्म ने उन्हें वो पहचान दिलाई थी, जिसे पाने के लिए लोगों को सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। उस दौर में इस तरह की पर्सनेलिटी वाले हीरो कम ही हुआ करते थे। यही वजह थी कि अपनी पहली फिल्म से वह छा गए थे।

आदमी और कूड़ा

आदमी का कूड़े के साथ चोली-दामन का संबंध है। यह तो हो ही नहीं सकता कि जहां आदमी पाया जाए और कूड़ा न पाया जाए! कूड़ा तो आदमी के आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, अगल-बगल; यहां तक कि उसके अंदर-बाहर भी कूड़ा भरा हुआ है। जब कूड़े से आदमी का इतना आत्मीय और निकट का संबंध है, तो उसका कूड़ा प्रेम स्वाभाविक ही है। उसे मिटाया नहीं जा सकता। यद्यपि वह जीवनभर कूड़ा पैदा करता है, उसे नष्ट भी करता है; किंतु कभी भी जीवनभर कूड़ा मुक्त नहीं हो पाता। यहां तक कि एक दिन ऐसा भी आता है कि वह अपने परिजनों के लिए स्वयं कूड़ा बन जाता है। और उस कूड़ा बने हुए आदमी को हटाने में कोई विलंब भी नहीं किया जाता। आदमी की देह के कूड़ा निस्तारण को अंतिम संस्कार की संज्ञा दी जाती है।

प्रत्येक आदमी के कूड़ा-उत्पादन के अलग-अलग रूप, प्रकार और श्रेणियां हो सकती हैं। जब आदमी इस धरा धाम पर आया है, तो साथ में कुछ न कुछ कूड़ा लेकर भी आया है। अत्याधुनिक आदमी कूड़े से ऊर्जा का उत्पादन भी कर रहा है। लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसा कर नहीं सकते। अन्यथा यह कूड़ा ही उनके जीने की समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए उसका निस्तारण भी अनिवार्य हो गया है। हमारे यहां कुछ ऐसे लोग भी उत्पन्न हो गए हैं, जो भले ही देश और समाज के लिए स्वयं कूड़ा हैं, किंतु अपना कूड़ा दूसरे के दरवाजे पर फेंक आने में कुशल हैं। इस कार्य को सुगम करने के लिए वे रात के अंधेरे और एकांत आदि का सहारा लेते हैं। बस उन्हें अवसर की तलाश है कि कब किसी की आंख से बचे कि उन्होंने अपना कूड़ा किसी पड़ौसी के दरवाजे पर फेंका! फिर क्या है, जब फेंकना था तो फेंक ही दिया। अब बाद में जो भी महाभारत होना हो तो हो।

जब हल्ला मचेगा, तो वे चुप्पी साधे अपने घर के बिल में घुस जाएंगे और चुपचाप घर के कोने या किवाड़ों के पीछे खड़े होकर सुनेंगे कि कौन क्या कह रहा है। कहीं कोई उनका नाम तो नहीं ले रहा! अब यदि कोई नाम लगा भी रहा हो तो अब तो अपनी सहन शक्ति का परिचय देना उनकी मजबूरी और मजबूती हो जाती है। इससे उनकी सहन शक्ति परीक्षा भी हो लेती है और यदि सहन नहीं कर पाए तो कुंडी खोलो और निकल पड़ो जंग के मैदान में कि कूड़ा हमने नहीं फेंका। देखो इस कूड़े में भिंडी के डंठल पड़े हैं और हमारे यहां आज उड़द की दाल बनी है। भला यह कूड़ा हमारा कैसे हो सकता है? जिसके घर में भिंडी बनी हो, उसके घर की तलाशी ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अंदर से चोरी और बाहर से सीनाजोरी! इसी को कहते हैं।

आदमी का शरीर ही कूड़ा उत्पादन की एक अच्छी खासी फैक्टरी है। जिससे वह हर पल हर दिन-रात, बारहों मास कूड़ा बनाता और निष्कासित करता रहता है। इसके लिए उसने हर घर में बाकायदे स्नान घर, शौचालय, मूत्रालय, कूड़ेदान आदि साधन बना रखे हैं। कोई-कोई तो इन कार्यों के लिए खेतों का सहारा लेते हैं। वैसे तो इस देश में प्रत्येक स्थान लघुशंका निवारण स्थान है ही।

मैं यह बात पहले भी कह चुका हूं कि यह आदमी रूपी जंतु जहां भी गया, कूड़ा ही उत्पादित करता और फैलाता गया। जो जितना अधिक कूड़ा-उत्पादन करे, वह उतना ही सभ्य, सुसंस्कृत, धनाढ्य और आधुनिक कहलाता है। पहाड़ों पर गया तो वहां प्लास्टिक की बोतलें, रेडीमेड फूड के रैपर, मल-मूत्र फैलाकर आ गया। पिकनिक मनाने गया तो वहां भी वही हाल। यहां तक कि इस आदमी ने चांद को भी कूड़े से वंचित नहीं छोड़ा। यदि वहां उसने कुछ छोड़ा तो बस कूड़ा ही छोड़ा। अभी मुझे चांद पर जाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए अभी यह नहीं बतला सकता कि चांद के चंद यात्रियों ने क्या-क्या कूड़ा छोड़ा?

आदमी का शरीर ही कूड़ा उत्पादन की एक अच्छी खासी फैक्टरी है। जिससे वह हर पल हर दिन-रात, बारहों मास कूड़ा बनाता और निष्कासित करता रहता है। इसके लिए उसने हर घर में बाकायदे स्नान घर, शौचालय, मूत्रालय, कूड़ेदान आदि साधन बना रखे हैं। कोई-कोई तो इन कार्यों के लिए खेतों का सहारा लेते हैं। वैसे तो इस देश में प्रत्येक स्थान लघुशंका निवारण स्थान है ही। जहां दीवार पर लिखा हो- गधे के पूत, यहां मत मूत। तो उस स्थान पर अनिवार्यता हो जाती है, क्योंकि इस देश के आम आदमी का आम चरित्र भी यही है कि जिस काम को करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाए, उसे जरूर करो। बस वह इसी सिद्धांत को गांठ में बांधे हुए चल पड़ा है।

कुछ लोगों का जन्म ही कूड़ा फैलाने के लिए हुआ है। नेता अपने भाषणों, आश्वासनों, वादाखिलाफियों, झूठों, अत्याचारों और शोषणों का कूड़ा देशभर में फैला रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। व्यभिचारी व्यभिचार का कूड़ा और स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचार का कूड़ा फैलाकर देश और समाज को दूषित कर रहे हैं। भौतिक कूड़े का निस्तारण संभव है, किंतु मानसिक और क्रियात्मक कूड़े का निस्तारण कैसे हो? यह एक चिंतनीय विषय है। बेईमानी का कूड़ा उत्पादित और फैलाने वालों का प्रतिशत इतना अधिक है कि लगता है ये आदमी और देश की ईंट-ईंट में बेईमानी भरी हुई है। समाज में हो रहे झगड़े-फसाद, कचहरियों के मुकदमे इतने अधिक कि न्यायाधीशों को कूड़ा निस्तारण में युग बीत जाएंगे, किंतु आदमी का यह कूड़ा कभी समाप्त नहीं हो सकेगा। आदमी में बेईमानी की एक ऐसी अटूट शृंखला है कि वह अमरौती खाकर आई लगती है। झूठ है तभी तो सत्य जिंदा है, वरना सत्य को कौन पूछता है? बेईमानी के कूड़े से ही ईमान जिंदा है।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर
जबलपुर, रीवा, उज्जैन, खजुराहो
और सिंगरौली से
अंतरराज्यीय उड़ान

मध्यप्रदेश में पर्यटन
अब नयी ऊंचाइयों पर

पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा
संचालन प्रारंभ

बुकिंग काउंटर
भोपाल, इंदौर और जबलपुर एयरपोर्ट

ऑनलाइन बुकिंग
www.flyola.in

"प्रदेश में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। पीएमश्री पर्यटन वायु सेवा प्रदेश के पर्यटन को नयी पहचान देगी। हमारे प्रदेश के श्रद्धालुओं एवं देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को यह सेवा और अधिक सुविधा प्रदान करते हुए पर्यटन क्षेत्र को नये आयाम देने में सफल साबित होगी।"

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश शासन